{ विश्वास वही रफ्तार नई }

बालाघाट
शुक्रवार 15 मई 2026
वैशाख कृष्ण 14 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 230
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

PMG पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

सेंसेक्स	-	74,608.98
निफ्टी	-	23,412.60
सोना	-	1,62,000
चांदी	-	3,10,000
डॉलर	-	95.64

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

खास खबर

अमूल, मदर डेयरी और पराग ने बढ़ाए दाम

नई दिल्ली। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि के बाद अब लोगों को दूध की महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है। देश की प्रमुख दूध कंपनियों जैसे अमूल, मदर डेयरी और पराग ने अपने दूध के दामों में करीब 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। अमूल की नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी हैं, जबकि पराग की बढ़ी हुई दरें 15 मई से प्रभावी होने की संभावना है। इस मूल्य वृद्धि को लेकर वाराणसी सहित देश के कई हिस्सों में आम लोगों के बीच गहरी नाराजगी देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि जहां गैस सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से जोड़ी जा रही थीं, वहीं दूध महंगा करने का कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आता। एक निवासी ने बताया कि उन्होंने खबरों में 2 रुपए की वृद्धि देखी थी, लेकिन बाजार में अमूल गोल्ड 3 रुपए तक महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।

आंध्र में बन रहा देश का सबसे बड़ा रक्षा केंद्र

नई दिल्ली। भारत अब रक्षा तकनीक के उस शिखर की ओर बढ़ रहा है, जहां अब तक दुनिया के चुनिंदा देशों की ही पहुंच रही है। दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में देश के सबसे बड़े रक्षा और वैमानिक केंद्र की नींव रखी जा रही है, जहां भारत का पहला स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान तैयार होगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना पुट्टपर्थी, श्री सत्य साई जिला में स्थापित की जा रही है। राजनाथ सिंह और एन चंद्रबाबू नायडू 15 मई 2026 को इस ऐतिहासिक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह केंद्र वैमानिकी विकास एजेंसी के अधीन विकसित किया जा रहा है, जहां भारत के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान का एकीकरण, परीक्षण, सत्यापन और प्रमाणन किया जाएगा।

कांग्रेस कॉर्पोरेटर आशिष जोशी गिरफ्तार

वडोदरा। शहर के म्युनिसिपल कोरपोरेशन के वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस के कॉर्पोरेटर आशिष जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर संखेड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद उन्हें बोडेली कोर्ट में पेश किया गया, अदालत ने शराब से जुड़े एक पुराने मामले में उनके 24 घंटे के रिमांड की मंजूरी दे दी। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई स्थानीय स्वराज्य चुनाव के दौरान दर्ज हुए एक पुराने शराब मामले में की गई है। संखेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले की जांच के दौरान आशिष जोशी का नाम सामने आने पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। सूत्रों के मुताबिक, आशिष जोशी अहमदाबाद में अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान रामोल क्षेत्र में पुलिस ने लोकेशन के आधार पर निगरानी रखकर उन्हें हिरासत में ले लिया।

कुछ ना कहना

केरल के नए सीएम होंगे वी डी सतीशन

नई दिल्ली । कांग्रेस की केरल इकाई के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के शीर्ष और प्रदेश इकाई के नेताओं के साथ लंबी मंत्रणा के बाद सतीशन के नाम पर मुहर लगाई है। केरल के लिए पार्टी के पर्यवेक्षकों अजय माकन और मुकुल वासनिक तथा महासचिव जयराम रमेश के साथ पार्टी कार्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस की केरल प्रभारी दीपा दासमुंशी ने सतीशन के नाम की घोषणा की है।

उन्होंने कहा, कांग्रेस विधायक दल की 7 मई, 2026 को तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई थी और सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष को केरल राज्य में विधायक दल के नए नेता के चयन के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया था।

- कांग्रेस अध्यक्ष से हुई नाम पर चर्चा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष (सोनिया गांधी), लोकसभा में विपक्ष के नेता (राहुल गांधी), एआईसीसी पर्यवेक्षकों (माकन और वासनिक) के साथ व्यापक चर्चा की। सांसदों, पूर्व पीसीसी अध्यक्षों सहित राज्य के कई अन्य नेताओं से भी परामर्श किया गया।

उन्होंने बताया कि इन सभी चर्चाओं के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि वी डी सतीशन को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया जाए। सतीशन केरल की पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। सतीशन के अलावा कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में शामिल थे। बीते 7 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी आलाकमान को विधायक दल के नेता के चयन के लिए अधिकृत किया गया था। केरल में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने राज्य की कुल 140 सीट में से 102 पर जीत दर्ज की।

सतीशन ने राज्यपाल से मिलकर पेश किया दावा

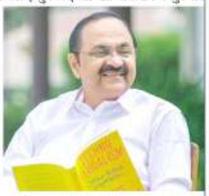

दक्षिण भारत के राजनीतिक रूप से अहम राज्य केरल में नई सरकार गठन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए वी. डी. सतीशन ने गुरुवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे की विधायक दल बैठक में सतीशन को सर्वसम्मति से नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने सहयोगी दलों के समर्थन पत्र के साथ राजभवन पहुंचकर सरकार गठन का दावा पेश किया। इसके साथ ही राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में पूरे दिन राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। पार्टी नेताओं और समर्थकों में उत्साह देखा गया। सतीशन ने कहा कि जनता ने बदलाव के लिए जनादेश दिया है और उनकी प्राथमिकता एक नई दिशा, पारदर्शी शासन और विकास को गति देना होगी। कांग्रेस नेतृत्व ने करीब दस दिनों की राजनीतिक मंथन और विचार-विमर्श के बाद सतीशन के नाम पर मुहर लगाई थी। अब राजभवन की औपचारिक मंजूरी के बाद शपथ ग्रहण समारोह की तारीख जल्द घोषित की जा सकती है। माना जा रहा है कि नई सरकार अगले कुछ दिनों में पदभार संभाल सकती है और इसके साथ ही केरल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी।

मुझे आलाकमान का फैसला स्वीकार

केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी ने वी.डी. सतीशन के नाम का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के बाद, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने दिल्ली में पत्रकारों से बात कर संयम और राजनैतिक परिपक्वता का परिचय दिया। उन्होंने हाईकमान के फैसले को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर अपनी वफादारी पर जोर दिया और किसी भी तरह की कड़वाहट जाहिर नहीं होने दी, भले ही वे उस दौड़ में पीछे रह गए थे जिसके बारे में कई अंदरूनी सूत्रों का मानना था कि यह आखिरी पल तक चली थी। वेणुगोपाल ने सतीशन को बधाई देकर कहा, सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और वह इस फैसले को स्वीकार करेगी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के लिए यह एक शानदार जीत थी, जिसमें 102 सीटें मिलीं। उन्होंने कहा कि पार्टी का सामूहिक जनादेश किसी भी व्यक्ति की निजी महत्वाकांक्षा से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि कांग्रेस के 50 से ज्यादा नए चुने गए विधायकों ने कथित तौर पर उनके दावेदारी का समर्थन किया था।

'मैं चुप नहीं रह सकती'

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल समेत अन्य नेताओं पर अवमानना कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया और अन्य नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का फैसला लिया है। शराब नीति मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि न्यायपालिका और अदालत की कार्यवाही को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक और बदनाम करने वाली सामग्री प्रसारित की गई, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत के फैसलों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और न्यायपालिका के खिलाफ एक सुनियोजित डिजिटल अभियान चलाया गया। उन्होंने विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट और वीडियो का उल्लेख किया, जिसमें अदालत से जुड़ी टिप्पणियां की गई थीं। अदालत के अनुसार कोर्ट रूम की कार्यवाही से जुड़े वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई। जज ने कहा कि जब अदालत के भीतर कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय बाहर सोशल मीडिया पर समानांतर नैरेटिव तैयार किया जा रहा था। उन्होंने टिप्पणी की कि इस तरह की गतिविधियां केवल व्यक्तिगत हमले नहीं हैं, बल्कि न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्था को कमजोर करने का प्रयास हैं। जस्टिस शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ चलाए गए अभियान में डराने-धमकाने और अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा, एक झूठ को हजार बार बोलने से वह सच नहीं बन जाता। अदालत ने यह भी कहा कि उनके लंबे समय तक चुप रहने को कमजोरी समझा गया, लेकिन जब किसी संवैधानिक संस्था को निशाना बनाया जाए, तब न्यायालय का कर्तव्य बनता है कि वह अपनी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करे। दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है और अब हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है। कानूनी जानकारों का मानना है कि अदालत की ओर से अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का फैसला न्यायपालिका की साख और स्वतंत्रता से जुड़े बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

नीट प्रश्नपत्र लीक कांड में जांच तेज, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2 और दबोचे, कुल 7 गिरफ्तार

नई दिल्ली । देश की सबसे बड़ी चिकित्सकीय प्रवेश परीक्षा नीट-स्नातक 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 24 घंटों में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं।

जांच एजेंसी के अनुसार देशभर में 14 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसके बाद धनंजय लोखंडा और मनीषा वाघमारे को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। धनंजय को अहिल्यानगर जबकि मनीषा को पुणे से हिरासत में लिया गया।

इससे पहले राजस्थान, महाराष्ट्र और गुरुग्राम से 5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। जांच एजेंसी ने 12 मई 2026 को शिक्षा मंत्रालय से मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था।

इस पूरे घोटाले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों में शुभम खैरनार, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव समेत अन्य नाम शामिल हैं। पहले पकड़े गए 5 आरोपियों को राउज एवेन्यू न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 7 दिन की केंद्रीय जांच ब्यूरो हिरासत में भेज दिया।

गौरतलब है कि 3 मई 2026 को हुई इस परीक्षा में 23 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। प्रश्नपत्र लीक के खुलासे के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब दोबारा परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में कराए जाने की संभावना जताई जा रही है।

ट्रंप चीन तो अरागची दिल्ली में, होर्मुज पर तनाव के बीच गुजरा भारतीय जहाज

नई दिल्ली,। दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों, अमेरिका और चीन ने वैश्विक व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर एक बड़ी सहमति व्यक्त की है। अमेरिकी जानकारी के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत में यह तय हुआ है कि इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी देश को अतिरिक्त शुल्क या टोल लगाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीजिंग में होने वाली शिखर बैठक से ठीक पहले हुई है, जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है।

इसी बीच, कूटनीतिक मोर्चे पर एक और बड़ी खबर आई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ युद्ध को विराम देने की दिशा में जारी बातचीत में सकारात्मक प्रगति हो रही है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप चीन की राजकीय यात्रा पर हैं। दूसरी ओर, भारत की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए ईरानी विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अरागची भी पहुंचे हुए हैं।

मध्य-पूर्व की स्थिति पर नजर डालें तो वहां मानवीय और तकनीकी संकट गहराया हुआ है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद से ईरान में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह ठप थीं। हालांकि, अब कुछ क्षेत्रों में इसे आंशिक रूप से बहाल किया गया है, लेकिन आम जनता और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े लोग अब भी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं।

कूटनीतिक दांव-पेच के बीच इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों को लेकर भी विरोधाभास सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने यूएई की एक ऐतिहासिक यात्रा का दावा किया, जिसे यूएई के विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। इस पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि इजरायल के साथ किसी भी तरह का सहयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, लेबनान में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली हमलों में अब तक 2800 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर है।

पेट्रोल-डीजल बचाओ, इनाम पाओ!

नई दिल्ली । देश में ईंधन बचत को जनआंदोलन बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब सरकारी मंत्रालयों ने इसे जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी पहल ऊर्जा मंत्रालय की ओर से सामने आई है, जहां पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने वालों को नकद पुरस्कार देने की तैयारी की गई है।

सूत्रों के अनुसार सोमवार से मंत्रालय के 20 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए विशेष रोस्टर तैयार किया जा रहा है, ताकि हर दिन तय संख्या में कर्मचारी घर से काम कर सकें और दफ्तर आने-जाने में ईंधन की बचत हो।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भी खुद मिसाल पेश करते हुए अपने काफिले की अतिरिक्त गाड़ियों को हटाने का फैसला किया है। अब उनके काफिले में केवल 2 वाहन रहेंगे और दिल्ली से बाहर की यात्राएं रेल मार्ग से करने की तैयारी है।

राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति, सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ से मांगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की

लखनऊ । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों से जवाब तलब किया है। बीजेपी नेता एस विग्नेश शिशिर ने याचिका दाखिल कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा की है। उन्होंने कोर्ट से इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई कर सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ को नोटिस जारी कर मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कह दिया है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण माना है। अधिकारियों के मुताबिक, कोर्ट अब एजेंसियों के जवाब के बाद आगे की कार्यवाही तय करेगा। इस मामले पर राजनीतिक गलियारों में भी काफी चर्चा हो रही है।

लाल किला विस्फोट केस : एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आज लाल किला इलाके में कार बम विस्फोट मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। पिछले वर्ष 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी को दहला देने वाले इस उच्च तीव्रता के विस्फोट में 11 लोगों की मौत थी, कई लोग घायल हुए थे और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।

एनआईए के अनुसार, मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी (मृत) समेत सभी 10 आरोपी अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (एक्यूआईएस) का एक सहयोगी संगठन है। आरोपपत्र यहां पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल किया गया। गृह मंत्रालय ने जून 2018 में एक्यूआईएस और उससे जुड़े सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया था।

हिंसा में बच्चों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को नहीं बख्शा

कोर्ट रूम से बाहर ममता की मौजदूगी में लगे चोर-चोर के नारे

कोलकाता। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दी। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा से संबंधित मामले में न्यायमूर्ति के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं। ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट को 10 मृतकों की सूची सौंपी, जिसमें से छह के हिंदू होने का दावा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाकर कहा कि पुलिस की मौजूदगी में घरों और कार्यालयों को लूटा जा रहा था, लेकिन इन मामलों में प्राथमिकी तक दर्ज नहीं हुई। उन्होंने एक 92 वर्षीय अनुसूचित जाति की विधवा और उसके परिवार को घर से

बेदखल करने का मुद्दा भी उठाया। कलकत्ता हाईकोर्ट में तस्वीरें दिखाते हुए ममता बनर्जी अत्यंत भावुक हो गईं और बताया कि हिंसा में बच्चों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों तक को नहीं बख्शा गया। उन्होंने खुलासा किया कि उनके अपने परिवार की 12 साल की बच्चियों को बलात्कार की धमकियां दी गई हैं। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट से तत्काल बंगाल के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई, क्योंकि अपराधी कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं।

अपनी दलीलों के दौरान, ममता ने राज्य प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस के सामने दुकानें और घर तोड़े जा रहे हैं, और मछली बाजारों को भी निशाना बनाया गया था। उन्होंने विनम्र निवेदन किया कि बंगाल के लोगों की रक्षा की जाए। फरार पार्टी कार्यकर्ताओं का विवरण देकर उन्होंने कहा कि बंगाल कोई ऐसा राज्य नहीं है, जहां बुलडोजर चलाया जा सके। हम लोगों ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में तोड़फोड़ की गई दुकानों और घरों का विवरण दिया है। पूर्व सीएम ममता ने कहा कि अनाधिकृत संरचना को ध्वस्त करते वक्त भी व्यक्तियों को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि अपराधी कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तब पुलिस को अपराध रोकना चाहिए, न कि घटना घटने के बाद जांच करनी चाहिए? उन्होंने कहा कि पुलिस का कोई अस्तित्व ही नहीं है।

सीबीआई निदेशक सूद का कार्यकाल एक साल और बढ़ा

नए नामों पर नहीं बनी सहमति, केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार को दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक पद पर एक वर्ष का सेवा विस्तार और दे दिया है। केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने बुधवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके तहत प्रवीण सूद अब 24 मई 2027 तक सीबीआई निदेशक के पद पर बने रहेंगे।

सूत्रों के अनुसार, नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर बनी चयन समिति में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पैनल में शामिल नए अधिकारियों के नामों के साथ जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर

सहमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सरकार के सामने मौजूदा निदेशक को सेवा विस्तार देने का विकल्प बचा।

बताया जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में सीबीआई प्रमुख के चयन पर विस्तार से चर्चा हुई थी। इस प्रक्रिया में कुल 39 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया, लेकिन किसी एक नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी। सीबीआई के निदेशक पद के लिए गठित चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं।

1986 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर से संबंध रखते हैं। उन्हें अगस्त 2021 में सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया था। निर्धारित दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद वह पिछले एक वर्ष से सेवा विस्तार पर कार्य कर रहे थे। अब उन्हें लगातार दूसरा विस्तार मिला है।

कलेक्टर ने ली निर्माण विभागों के अधिकारियों की बैठक

निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। कलेक्टर मृणाल मीना ने 14 मई को सभी निर्माण विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर उनके द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ भी उपस्थित थे।

समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश

कलेक्टर श्री मीना ने निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि कार्यों को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। इससे आमजन को निर्माण कार्यों का समय पर लाभ मिल सकेगा। शाला एवं छात्रावास भवनों का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर उन्हें संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाए, जिससे छात्र-छात्राओं को नवीन भवनों में अध्ययन एवं रहने की सुविधा मिल सके। उन्होंने निर्माण कार्यों में लगे सभी श्रमिकों का श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीयन कराने तथा इसकी रिपोर्ट श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों की समीक्षा

एमपीआरडीसी के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लालबर्रा-समनापुर मार्ग के 500 मीटर लंबाई में शेष कार्य कराया जा रहा है। इसमें सीसी रोड का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा एक स्थान पर बॉक्स कल्वर्ट का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। बैहर-सालेटेकरी मार्ग में 700 मीटर का कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एप्रोच रोड कार्यों पर जोर

नेशनल हाईवे लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि नैनपुर-बालाघाट सड़क का प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति के लिए दिल्ली भेज दिया गया है। सेतु निर्माण संभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि लांजी-बिसोनी मार्ग, चारटोला-भंडारपुर मार्ग एवं बुदबुदा से नदीटोला मार्ग पर पुल निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि एप्रोच रोड का कार्य शेष है। कलेक्टर ने सड़कों की मरम्मत एवं एप्रोच रोड का कार्य वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही भटेरा रेल ओवरब्रिज एवं जागपुर घाट पुल निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा।

छात्रावास, स्कूल एवं सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा

बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि छात्रावास अधीक्षक आवास के 36 भवनों में से 24 का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इकाई के महाप्रबंधक ने बताया कि आरसीपीएलडब्ल्यू योजना अंतर्गत स्वीकृत सभी पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। पीआईयू के कार्यपालन यंत्री ने जानकारी दी कि बोलेगांव एवं खैरलांजी में सीएम राइज स्कूल भवन का कार्य पूर्ण हो गया है। सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सातनारी जलाशय का कार्य वर्षा ऋतु पूर्व पूर्ण करने एवं जगला जलाशय के जीर्णोद्धार कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य, भवन निर्माण एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा

बैठक में लोक निर्माण विभाग, हाउसिंग बोर्ड, पुलिस हाउसिंग, पीआईयू, भवन निर्माण निगम एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा बनाए जा रहे शिक्षा, स्वास्थ्य, जेल एवं राजस्व विभाग के भवनों की समीक्षा की गई। जिला चिकित्सालय में नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र एवं छात्रावास भवन, बिरसा, कटंगी एवं परसवाड़ा में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल भवनों का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्टेडियम निर्माण, जिला पुनर्वास केंद्र भवन एवं जिला खनिज निधि मद से स्वीकृत कार्यों की भी समीक्षा की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान नलजल योजनाओं एवं टंकी निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही शालाओं एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल एवं शौचालय के लिए टंकी से जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

चिन्हित मरीजों की फ्री एंजियोग्राफी के साथ नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर 21 मई को

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। महावीर इंटरनेशनल अभ्युदय वीरा केंद्र बालाघाट के संयुक्त तत्वावधान में स्व. श्रीमती कमला देवी वैद्य की द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस पर 21 मई 2026, गुरुवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पार्श्वनाथ भवन, मेन रोड बालाघाट में विशाल नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, नेत्र रोग सहित विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नि:शुल्क परामर्श दिया जाएगा।

शिविर में ईसीजी, शुगर जांच, बी.पी. जांच, सीबीसी जांच एवं नेत्र जांच की सुविधा भी नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी। जांच के दौरान चिन्हित गंभीर हृदय रोगियों की फ्री एंजियोग्राफी सुविधा भी सहयोग हॉस्पिटल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आयोजकों ने बताया कि शिविर में आयुष्मान भारत योजना (PMJAY) के तहत पात्र मरीजों को नि:शुल्क उपचार संबंधी जानकारी एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। मरीजों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था भी शुरू की गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग समय पर अपना पंजीयन करा सकें। शिविर के आयोजन में वीर कैलाश शर्मा (सचिव), वीरा अलका चौधरी (सचिव महिला केंद्र) एवं विक्रम त्रिवेदी सचिव यूथ केंद्र तथा सहयोग हॉस्पिटल गोंदिया के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। आयोजकों ने जिलेवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शिविर के माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य का लाभ लेने की अपील की है।

मकान बेचना है

17×44 एरिया में
निर्मित डबल स्टोरी सेमी
फर्निश्ड बोरिंग सहित
पूर्वमुखी मकान बेचना है
वार्ड नं. 6 चित्रगुप्त नगर, बालाघाट

9244108543

आवश्यकता है

होटल कान्हा में काम करने
वाले लड़के की आवश्यकता है
अनुभवी को प्राथमिकता

9993282223
9425139875

किराये पर उपलब्ध

धनराज कॉम्पलेक्स
बालाघाट में प्रथम तल पर
दुकानें किराये पर देना है।

महेन्द्र सुराना 94251 38670
ललित बाघरेचा 9424765679

नवीन की टीम के अलावा केन्द्र में मंत्री बनने में प्रदेश के नेताओं की दिलचस्पी

आधा दर्जन कद्दावर नेता कैलाश, प्रहलाद, विजय, राकेश सिंह और विष्णुदत्त को मिल सकता है नया दायित्व

भोपाल। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद अब सभी राजनीतिक पंडितों की निगाहें भाजपा की राष्ट्रीय टीम के साथ ही मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार पर लग गई है। कुछ राजनीति के जानकारों का मानना है कि प्रदेश के कुछ बडें नेताओं को राष्ट्रीय टीम में या फिर केन्द्रीय केबिनेट में जगह देकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का राहत दी जा सकती है। दरअसल मोहन मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे कद्दावर नेता है जिनके सामने स्व्यं मुख्यमंत्री कुछ भी कहने पर कई बार सोच विचार करते है क्योकि यह सभी मंत्री उनसे काफी वरिष्ठ है इस लिए डॉ. मोहन यादव उनकी वरिष्ठता को ध्यान भी रखते है। वही दूसरी और प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री इस बात सें परेशान हैं, कि कही पार्टी उन्हें संगठन की राष्ट्रीय टीम में शामिल कर उनसे मंत्री पद छोड़ने को कह सकती है। इसी तरह पार्टी के कुछ वरिष्ठ सांसद भी राष्ट्रीय टीम में शामिल होने की बजाय मोदी कैबिनेट में स्थान पाना चाहते हैं, जिससे वे भी संगठन के दायित्व से दूर भाग रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान कभी भी हो सकता है। जिसमें मध्यप्रदेश से भी कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है.हालॉकि प्रदेश के कुछ मंत्री इससे बचने का प्रयास कर रहे है। क्योंकि अगर वह राष्ट्रीय टीम में शामिल होते हैं, तो उन्हें राज्य सरकार का मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इन मंत्रियों ने अपनी इस मंशा से पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है। पार्टी से जुड़े सूत्रों की मानें तो मध्यप्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल के अलावा कुंवर विजय शाह का नाम भी राष्ट्रीय टीम की संभावित सूची में बताया जा रहा है। आदिम जाति कल्याण मंत्री शाह को लेकर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यदि शाह का मंत्री पद नहीं बच पाता है, तो पार्टी उन्हें राष्ट्रीय संगठन में लेकर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे मध्यप्रदेश में पार्टी का आदिवासी वोट बैंक सधा रह सके। माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इसी तरह पार्टी तीनों वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह को भी राष्ट्रीय राजनीति में वापस ले जाना चाहती है और उनका उपयोग अगले साल यूपी सहित दूसरे राज्यों के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए कर सकती है। लेकिन ये सभी मंत्री फिलहाल मध्यप्रदेश सरकार में ही अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। बताया गया है कि पिछले दिनों इन सभी मंत्रियों ने अपनी बाते भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व के समक्ष रख दी है।वही दूसरी और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि वे संगठन की टीम से ज्यादा केन्द्र सरकार में शामिल होना चाहते है, लेकिन संगठन का उनके अनुभव के आधार पर यदि पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, तो वे उसे इंकार नहीं करेंगे।

डॉ. नरोत्तम के नाम की भी चर्चा

वही काफी दिनों से राजनीतिक हाशिए पर चल रहे प्रदेश में एक समय पार्टी के संकटमोचक की भूमिका निभाने वाले डॉ नरोत्तम मिश्रा को अगर दतिया से पार्टी चुनाव मैदान में नहीं उतारती है तो उन्हें भी राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि मध्यप्रदेश की अगले महीने खाली हो रही तीन राज्यसभा सीट लिए भी पार्टी डॉ. मिश्रा को मैदान में उतारकर पूरी तरह से केन्द्रीय राजनीति में सक्रिय कर सकती है। इसी तरह मध्यप्रदेश से महिला नेत्री कविता पाटीदार या फिर हिमांद्री सिह को राष्ट्रीय महासचिव पद या महिला मोर्चा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

पार्टी की शीर्ष इंकाइयों पर नज़र

प्रदेश के इन नेताओं को अगर संगठन टीम नितिन नवीन में काम करने के लिए राजी कर लेता है तो इनकी नजर पार्टी की दो महत्वपूर्ण इंकाईयों संसदीय बोर्ड और केन्द्रीय चुनाव समिति पर रहेगी। भाजपा में ये दोनों इकाईयां पार्टी के अहम फैसले लेती है। चर्चा है कि पार्टी नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को इन दोनों समितियों में स्थान दे सकती है, जिससे इन नेताओं का कद और मजबूत होगा और उससे उनका मध्यप्रदेश की राजनीति में भी प्रभाव बना रहेगा, साथ ही राज्य का राजनीतिक प्रभाव भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगा ।

गौरव,भक्ति प्रबल दावेदार

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री थे, तब उनके साथ मध्यप्रदेश से आने वाले गौरव तिवारी, राहुल कोठारी और भक्ति शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नवीन की टीम में गौरव तिवारी और भक्ति शर्मा को जगह मिल सकती है। कोठारी पहले से ही प्रदेश के महामंत्री है, ऐसे में उनका राष्ट्रीय टीम में शामिल होना मुश्किल लग रहा है।

डॉ महेन्द्र सिंह और सतीश की भी हो सकती है विदाई

मध्यप्रदेश भाजपा जल्द ही प्रदेश प्रभारी की भ्भूमिका में काम कर रहे डॉ महेन्द्र सिंह औेश्र सह प्रभारी सतीश उपाध्याय को कार्यभार से मुक्त कर सकती है इसेके पीछे जो कारण बताए जा रहे है वहां वर्ष 2027 में उत्तरप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव है जिनमें डॉ महेन्द्र सिंह को बडी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वही दूसरी और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी दिल्ली से विधायक है, जिससे उनका भी पूरा समय अपने क्षेत्र व पार्टी द्वारा सौपी गई दूसरी जिम्मेदारियों पर रहेगा, जिससे मप्र के लिए किसी दूसरे नेता को सहप्रभारी के तौर पर भेजा जा सकता है।

युवक ने शराब के नशे में घर में मचाया तांडव

शराब के नशे में धुत छोटे भाई को धक्का देने से सिर में आई चोट बड़े भाई और भाभी ने ही अस्पताल में कराया भर्ती

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम बोदा में एक युवक ने शराब के नशे में अपने घर में तांडव मचाते हुए पहले भाभी को गालिया देकर घर से निकाला और फिर बड़े भाई से गाली-गलौज करने पर समझाइश के दौरान यह युवक धक्का लगने से घायल हो गया। सिर में

चोट लगने से घायल युवक हरिप्रसाद नगपुरे 26 वर्ष उसके बड़े भाई मंगल प्रसाद और भाभी ने ही जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया। जहां उसका इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिप्रसाद नगपुरे अपने बड़े भाई मंगल प्रसाद नगपुरे के साथ बोदा में रहता है। मंगल प्रसाद शादीशुदा हैं, उसके बच्चे हैं और वह गांव के ही अजीत लिल्हारे के घर मजदूरी करता है। हरिप्रसाद अविवाहित है वह भी मजदूरी करता है। घटना 13 मई की शाम की है। दोपहर 4 बजे मंगल प्रसाद काम पर चला गया था और उसकी पत्नी भी भटेरा काम करने गई थी। घर में हरिप्रसाद और छोटे बच्चे थे। शाम 5 बजे शराब के नशे में धुत हरिप्रसाद ने काम से घर लौटी अपनी भाभी को गाली-गलौज कर घर से निकाल दिया था। शाम करीब 6 बजे जब मंगल प्रसाद घर पहुंचा तो हरिप्रसाद उससे भी अभद्रता करने लगा। मंगल प्रसाद ने छोटे भाई हरिप्रसाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन हरिप्रसाद और आक्रोशित होकर मारपीट पर उतारू हो गया। विवाद बढ़ने पर मंगल प्रसाद ने बचाव में हरिप्रसाद को थप्पड़ मारा और धक्का दे दिया। धक्का लगने से हरिप्रसाद जमीन पर गिर पड़ा और सिर में गंभीर चोट लगने से लहूलुहान हो गया। घटना के बाद घायल हरिप्रसाद को उसके ब? भाई मंगल प्रसाद और भाभी ने तुरंत जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती कराया। सूचना पर जिला अस्पताल चौकी पुलिस ने मंगल प्रसाद के बयान दर्ज किए। पुलिस ने तहरीर तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए भरवेली थाना भेज दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग बालाघाट

भवन हस्तांतरण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है, कि प्रेम नगर कालोनी जिला बालाघाट स्थित भवन क्र. एल. आई. जी. 29 श्री फूलचंद श्रीवास पिता श्री मंडल श्रीवास को इस कार्यालय के आदेश क्रं. 1276-82 दिनांक 28/01/1983 के द्वारा आबंटित है, जिसका विक्रय विलेख दिनांक 08/01/1990 को आबंटी के पक्ष में निष्पादित हो चुका है, उक्त भवन को श्री फूलचंद श्रीवास पिता श्री मंडल श्रीवास ने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 22/01/2008 के माध्यम से श्री सत्येन्द्रनाथ अवस्थी पिता श्री स्व. रामप्रसाद अवस्थी को विक्रय किया गया है। श्री सत्येन्द्रनाथ अवस्थी की मृत्यु 15/12/2024 को हो गयी है मृत्यु उपरांत श्री सत्येन्द्रनाथ अवस्थी के वैध वारिश श्री स्नेहांशु अवस्थी पिता स्व. श्री सत्येन्द्रनाथ अवस्थी द्वारा उक्त भवन की लीज अपने नाम पर हस्तांतरण हेतु दस्तावेज/आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं, यदि व्यक्ति संस्था आदि को उपरोक्त लीज हस्तांतरण (भवन/भूखण्ड) बाबत आपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने से 15 दिवस के अंदर लिखित में वैध आपत्ति सप्रमाण प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात हस्तांतरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। जिस पर किसी की कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

संपदा अधिकरी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मंडल संभाग- बालाघाट

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग बालाघाट

भवन नामांतरण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि प्रेम नगर कालोनी बालाघाट, जिला बालाघाट स्थित भवन क्र. एल. आई. जी. 30 श्रीमति मंजू अवस्थी पति स्व. श्री सत्येन्द्रनाथ अवस्थी को इस कार्यालय के आदेश क्रं. 205 दिनांक 10/01/1983 के द्वारा आबंटित है जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 22/03/2006 को निष्पादित की गई है। श्रीमति मंजू अवस्थी पति स्व. श्री सत्येन्द्रनाथ अवस्थी की मृत्यु दिनांक 06/02/2023 को हो गयी है, मूल आबंटी के नामिनी श्री स्नेहांशु अवस्थी पिता स्व. श्री सत्येन्द्रनाथ अवस्थी द्वारा उक्त भवन की लीज अपने नाम नामांतरण करने हेतु दस्तावेज/आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था आदि को उपरोक्त भवन के नामांतरण (भवन/भूखण्ड) बाबत् आपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने से 15 दिवस के अंदर लिखित में वैध आपत्ति सप्रमाण प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात नामांतरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। जिस पर किसी की कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

संपदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मंडल संभाग- बालाघाट

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देवास के टोंककला की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट पर किया शोक व्यक्त

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि विस्फोट में कई लोगों के हताहत होने का समाचार हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जिले के प्रभारी एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। घटना की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने एवं घायलों का नि:शुल्क इलाज करने के लिये निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुर्घटना में घायलों को त्वरित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने बाबा महाकाल से दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिजन को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

एमएसपी पर केवल घोषणा नहीं, किसानों को कानूनी गारंटी दे केंद्र सरकार -जीतू पटवारी

भोपाल । मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार द्वारा 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों की भावनाओं को समझने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद, लेकिन केवल रूस्क की घोषणा कर देना किसानों के साथ न्याय नहीं है। देश और मध्यप्रदेश के किसानों को आज भी उनकी उपज का वास्तविक समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश के किसानों को यह बताना चाहिए कि आखिर मध्यप्रदेश में कौन-सी फसल वास्तव में रूस्क पर बिक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि दावा कर रही है कि किसानों को रूस्क का लाभ मिल रहा है तो इसका भौतिक सत्यापन कराया जाए और सच्चाई जनता के सामने रखी जाए। उन्होंने कहा कि केवल आंकड़ों की जादूगरी और घोषणाओं के माध्यम से किसानों को गुमराह करना उचित नहीं है। जमीनी स्थिति यह है कि दलहन, तिलहन, मोटा अनाज, सरसों सहित अधिकांश खरीफ फसलें रूस्क से नीचे बिक रही हैं मूंग किसानों को रूस्क क्यों नहीं मिल रहा, जवाब दें मोहन यादव सरकार और किसान मजबूरी में अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने को विवश हैं। पटवारी ने कहा कि किसान अपनी आर्थिक परिस्थितियों, कर्ज और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण कम दाम पर उपज बेचने को मजबूर होता है, लेकिन व्यापारी और खरीददार उसकी मजबूरी का लाभ उठाते हैं। इसलिए यदि केंद्र सरकार वास्तव में किसानों का हित चाहती है तो रूस्क से नीचे खरीद करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार और भाजपा रूस्क से नीचे खरीद को अपराध घोषित करने का साहस दिखाएगी? क्या देश में किसानों के हित में ऐसा कानून बनेगा? क्या मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को रूस्क की कानूनी गारंटी देंगे?

कार्यालय तहसीलदार तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट (म.प्र.)

रा.प्र.क्र. 0009/ब-154/2026-27
मौजा पनबिहरी, रा.नि.मं. लालबर्रा

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राधेश्याम ब्रम्हे पिता कृष्णदास ब्रम्हे जाति गढ़ेवाल, निवासी ग्राम पनबिहरी, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मौजा पनबिहरी, रा.नि.मं. लालबर्रा, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट में स्थित आवेदक द्वारा अपने पिता कृष्णदास पिता रूपदास का अनुज्ञा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 (2), म.प्र. मृत्यु पंजीयन 1999 नियम 12 (2) प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त मृत्यु की घटना दिनांक 21.04.2000 मृत्यु की घटना स्थल ग्राम पनबिहरी के अंतर्गत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह दिनांक 25.05.2026 के पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक/अधिवक्ता सहित उपस्थित होकर इस न्यायालय में दावा आपत्ति पेश कर सकते है। नियत तिथि उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 14.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

स्थान - लालबर्रा
दिनांक - 15.05.2026

भूपेन्द्र अहिरवार
तहसीलदार
तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट म.प्र.

बारबेड वायर (कांटेदार तार) एवं चेन लिंक जाली उचित दाम पर उपलब्ध

लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध

—निर्माता—
तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोन:- 07632-243531
मो:- 8989976858, 9425139998

न्यूज गैलरी

ईंधन बचत की दिशा में बालाघाट प्रशासन की अनूठी पहल, अब साझा होंगे शासकीय वाहन

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। देशभर में लगातार बढ़ रही ईंधन की खपत और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल की बचत को लेकर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आम नागरिकों और सरकारी तंत्र से ईंधन बचाने की अपील की गई है। अब इसका असर बालाघाट जिले में भी दिखाई देने लगा है, जहां जिला प्रशासन ने एक नई

पहल करते हुए शासकीय वाहनों के साझा उपयोग यानी कारपूलिंग व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान समय में ईंधन की बचत केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी बन गई है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए अब प्रशासनिक अधिकारी अलग-अलग वाहनों के स्थान पर एक ही वाहन से कार्यालय आने-जाने की व्यवस्था बना रहे हैं। इससे न केवल पेट्रोल और डीजल की बचत होगी, बल्कि सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा। जानकारी के अनुसार बालाघाट कलेक्ट्रेट में पदस्थ कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने की शुरुआत भी कर दी है। अब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जैसे अधिकारी साझा वाहन व्यवस्था के तहत कार्यालय पहुंचेंगे। जिले में पदस्थ दोनों एडीएम डीपी बर्मन और जीएस धुर्वे अब अलग-अलग वाहनों के बजाय एक ही शासकीय वाहन का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार संयुक्त कलेक्टर राहुल नायक, मायाराम कौल और डिप्टी कलेक्टर प्रदीप कौरव भी साझा वाहन व्यवस्था के माध्यम से कार्यालय आने-जाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि दो अधिकारी एक ही मार्ग और आसपास के क्षेत्र से कार्यालय आते हैं तो वे एक ही वाहन का उपयोग करेंगे। इससे प्रतिदिन सड़कों पर चलने वाले शासकीय वाहनों की संख्या कम होगी और ईंधन की खपत में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी। इसके साथ ही वाहन रखरखाव, मरम्मत और अन्य खर्चों में भी कमी आने की संभावना है। विशेष बात यह है कि अभी तक शासन स्तर से इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बालाघाट प्रशासन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए देशहित के आह्वान को गंभीरता से लेते हुए इस पहल को अमल में लाने का निर्णय लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि छोटे-छोटे प्रयासों से भी बड़े स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। प्रशासन का यह भी मानना है कि यह पहल केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आम नागरिकों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि यदि लोग निजी वाहनों का कम उपयोग करें, साझा यात्रा को बढ़ावा दें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करें तो ईंधन की खपत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी और आर्थिक बचत भी होगी। कई लोगों ने इसे समय की आवश्यकता बताते हुए सराहना की है। लोगों का कहना है कि जब प्रशासनिक अधिकारी स्वयं इस प्रकार की व्यवस्था अपनाएंगे तो समाज में भी सकारात्मक संदेश जाएगा और लोग ईंधन बचाने के प्रति अधिक जागरूक होंगे। प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले समय में अन्य विभाग भी इस पहल को अपनाएंगे और यह व्यवस्था पूरे जिले के लिए एक उदाहरण बनेगी।

यात्री प्रतीक्षालय में समस्याओं का अंबार, बैठने उठने तक की नहीं है व्यवस्था

भीषण गर्मी में पंखे बंद, कंठ तर करने पानी तक नही, गंदगी और दुर्गंध से सराबोर माहौल,यात्री परेशान

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

स्थानीय बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय में समस्याओं का अंबार देखा जा रहा है। जिसपर नगर पालिका का कोई भी ध्यान नहीं है सुविधाएं न मिलने के कारण ज्यादातर यात्री इस प्रतीक्षालय में बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं परंतु दूरदराज की यात्रा करने वाले लोगों को मजबूरन यात्री प्रतीक्षालय का सहारा लेना पड़ रहा है,ना तो इस यात्री प्रतीक्षालय में यात्रियों के बैठने के कोई इंतजाम है ना ही भीषण गर्मी में राहत देने के लिए पंखे चलते है। वहीं जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिसको लेकर दूरदराज से आने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।जहा तहा गंदगी और अव्यवस्थाओ के बावजूद भी यात्रियों को मजबूरन यात्री प्रतिक्षालय में बैठकर समय गुजारना पड़ रहा है।पुराने यात्री प्रतिक्षालय का आलम तो यह है कि यहां बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां अज्ञात तत्वों द्वारा तोड़ दी गई है। इसके अलावा नियमित साफ सफाई ना होने से हमेशा बदबूदार माहौल बना रहता है वहीं जहां तहां कचरा पड़ा होना, यहां के लिए आम बात सी हो गई है।उचित रखरखाव न होने से यात्री प्रतीक्षालय अपने उद्देश्य की सही ढंग से पूर्ति नहीं कर पा रहा है।जिसको लेकर यात्री काफी परेशान है जिन्होंने सुविधाएं दिए जाने की मांग की है।

भीषण गर्मी में बंद पड़े है सभी पंखे, पीने का पानी तक नही

वर्तमान समय में भीषण गर्मी का दौर जारी है इस दौर में जहां यात्रियों को ठंडी हवा की जरूरत है तो वही भीषण गर्मी में कंठ सुखा देने वाली प्यास को बुझाने के लिए उन्हें ठंडे पानी की आवश्यकता है।लेकिन यात्री प्रतीक्षालय में यह दोनों सुविधा भी यात्रियों को नहीं मिल रही है।नपा प्रशासन ने यात्री प्रतीक्षालय में पंखे तो लगा दिए हैं परंतु यह लगे सभी पंखे बंद पड़े हैं।जिन्हें सुधारने, उनका मेंटनेंस करने या उसे बदलवाने की जहमत भी नपा द्वारा नही उठाई जा रही है।नए यात्री प्रतीक्षालय में रोशनी की व्यवस्था है लेकिन पुराना यात्री प्रतीक्षालय तो महज एक लाईट के भरोसे है। इससे प्रतीक्षालय में बसों का इंतजार करने वाले यात्रियों को चोरी का भी भय बना रहता है।यात्री प्रतीक्षालय में विद्युत व्यवस्था तो है लेकिन वहां लगे पंखे काम नहीं करते या कहा जाए कि पंखे कई दिनों से बंद पड़े हुए हैं जिनको दुरुस्त करने की जहमत भी अब तक नगर पालिका ने नहीं उठाई है

नजर नहीं आ रहा स्वच्छता अभियान

मुख्यालय के बस स्टैंड में बदहाली के किस्से किसी से छिपे नहीं है। एक ओर शासन द्वारा गंदगी से निपटने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है वही यात्री प्रतीक्षालय की साफ सफाई पर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है और नपा के जिम्मेदार अधिकारी भी इस अभियान पर पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे है।स्टैंड का आलम यह है कि यात्री यहा दो मिनट बैठना तो दूर खड़ा रहना भी पसंद नहीं करता है।लेकिन भीषण गर्मी और धूप के चलते उन्हें मजबूरी में यात्री प्रतीक्षालय का उपयोग करना पड़ रहा है।

यात्री प्रतीक्षालय बना विज्ञापन का स्थान

बस स्टैंड का यात्री प्रतिक्षालय इन दिनों प्रतिक्षालय कम और विज्ञापन का स्थान ज्यादा नजर आ रहा है यात्री प्रतीक्षालय की चारों ओर की दीवारों पर अनेक प्रकार के विज्ञापनों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं मानों वह यात्री प्रतीक्षालय नहीं कोई प्रचार प्रसार का स्थान हो। वहीं दूसरी ओर कोन-कोने में गुटखा-पान की पीके है।इसे देख ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रतीक्षालय नहीं बल्कि कोई विज्ञापन प्रचारक व पीकदान का एरिया हो। इन सारी असुविधाओं से बचने के लिए अधिकतर यात्री दुकानों के सामने बैठना पसंद करते हैं। यात्री व स्थानीय नागरिकों ने नपा से इन सारी समस्याओं से निजात दिलवाने की मांग की है। संबंधित को चाहिए कि वे इस प्रतीक्षालय को स्वच्छ व सुंदर बनाए ताकि लोग यहां दो मिनट बैठ राहत की सांस ले सके।

बैठने तक की नहीं है व्यवस्था

बस स्टैंड के नए यात्री प्रतीक्षालय में तो बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। यात्री प्रतीक्षालय में बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां अज्ञात तत्वों द्वारा चोरी कर ली गई है वहीं कई कुर्सियों में तोड़फोड़ भी की जा चुकी है। नगर पालीका की अनदेखी के चलते यहां इस तरह के हालात बने हुए हैं। यात्री प्रतीक्षालय में तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराए जाने की कई बार मांग उठाई जा चुकी है लेकिन इस पर किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।वही सुविधाओ का अभाव होने के चलते यात्रियों को बस का इंतजार करने के लिए होटल और पान दुकानों का सहारा लेना पड़ता है।

मवेशियों का आतंक

यात्री प्रतीक्षालय में प्रतिदिन आवारा श्वानों(कुत्तों) व पशुओं की भरमार रहती है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय में रोजाना आवारा पशु बैठे रहते हैं। इनसे यात्रियों को सदैव भय बना रहता है। जिसपर अभी तक नगर पालिका ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

नपा ने व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए- प्रतीक

स्थानीय नागरिक प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि यात्री प्रतीक्षालय के बुरे हाल हैं, यहां पर सभी पंख लंबे समय से बंद पड़े हैं। इसका मेंटेनेंस तक नहीं किया गया है। बैठने के लिए जो कुर्सियां लगाई गई है उनमें से कई कुर्सियां टूट गई है, यहां तक कि भीषण गर्मी के इन दिनों में यहां पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है यहां आने वाले लोग भी जागरूक नहीं है ,लोग यहां पर पान खाकर थूक देते हैं, जगह-जगह कचरा फेक रहे है । ऊपर से गर्मी में सबके बुरे हाल है करीब 5-6 महीनो से यहां लगे पंखे बंद है जिसके मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया है हमारी मांग है यात्री प्रतीक्षालय में सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। समय-समय पर व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

तत्काल बनाई जाएगी व्यवस्था- उइके

इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सूर्य प्रकाश उइके ने बताया कि यह मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, कर्मचारी भेजकर वस्तु स्थिति का पता लगाया जाएगा और तत्काल व्यवस्था बना दी जाएगी।उन्होंने बताया कि नगरपालिका द्वारा बस स्टैंड सहित नगर के विभिन्न स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था बनाई गई है दोनों यात्री प्रतिक्षालयों में भी आज की आज प्याऊ की व्यवस्था बना दी जाएगी, इसके अलावा विद्युत लाइन को दुरुस्त कर पंख का मेंटेनेंस कर उसे भी शुरू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री की 1 साल तक सोना ना खरीदने अपील का बालाघाट में व्यापक असर

सराफा कारोबार हुआ आधा, व्यापारी भी नाराज

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। देश मे 5 राज्यो के चुनाव सम्पन्न होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील की गई है,इस अपील का असर अब सराफा बाजारों में दिखाई देने लगा है।जिसने व्यापारियों की चिंता ब ?ा दी है।पीएम की इस अपील का देश प्रदेश सहित बालाघाट के सराफा कारोबार पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद ग्राहकों की संख्या अचानक कम हो गई है और कारोबार लगभग आधा रह गया है।बालाघाट के सराफा व्यापारियों के अनुसार पहले जहां प्रतिदिन दुकानों में ग्राहकों की अच्छी भीड़ रहती थी, वहीं अब बाजार में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। लोगों ने सोने की खरीदी टालना शुरू कर दिया है, जिससे छोटे व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति बनने लगी है।

शादी ब्याह का सीजन भी ठंडा

व्यापारियों का कहना है कि शादी-विवाह और निवेश के लिए लोग बड़ी मात्रा में सोना खरीदते थे, लेकिन अब ग्राहक सिर्फ जरूरत भर की खरीदारी कर रहे हैं। कई दुकानदारों ने बताया कि बिक्री में 40 से 50 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है।बताया गया कि दाम अधिक ब ?ने से सराफा व्यापार वैसे ही कमजोर पड़ गया था।अब पीएम मोदी की अपील के बाद से व्यापार और अधिक प्रभावित हो गया है।

व्यापारी ही नही कर्मचारी व कारीगर का कार्य भी प्रभावित

1 साल तक सोना चांदी के जेवरात ना खरीदने की अपील का असर स्थानीय बाजारों और छोटे व्यापारियों पर साफ दिखाई दे रहा है।सराफा व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है

कि सोने की खरीदी कम होने से केवल दुकानदार ही नहीं, बल्कि कारीगर, डिजाइनर और इस व्यवसाय से जुड़े मजदूर भी प्रभावित हो रहे हैं। बाजार में मंदी का असर रोजगार पर भी दिखाई देने लगा है।व्यापारियों ने यह भी कहा कि यदि लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही तो छोटे कारोबारियों के लिए दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सरकार से व्यापारियों के हित में सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है।फिलहाल बालाघाट का सराफा बाजार ग्राहकों की कमी और घटते कारोबार से जूझ रहा है और व्यापारी आने वाले त्योहारों व शादी सीजन से उम्मीद लगाए बैठे हैं।

नगर में 500 करोड़ से अधिक का है सराफा व्यापार

एक जानकारी के अनुसार बालाघाट में सराफा का एक बड़ा व्यवसाय है, साल में 500 करोड़ से ज्यादा का व्यापार होता है, लेकिन अपील के बाद व्यापार मंदा होने से ना केवल व्यापारियो में नाराजगी है बल्कि, सराफा व्यवसाय से जुड़े कामगारो में भी रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है।

सराफा व्यापार आधा हो गया है- कारडा

सराफा व्यापारी दिलीप कारडा ने बताया कि इस इंडस्ट्री से लाखो लोगों का परिवार जुड़ा है, जिसका ध्यान प्रधानमंत्री को रखना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील को देश की जनता गंभीरता से लेती है, यही कारण है कि उनकी अपील के बाद व्यापार आधा हो गया है। जिससे व्यापार से जुड़े व्यापारियों और कामगारों को रोजी की चिंता सताने लगी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने अपील में डिटेलिंग कर यह कह सकते थे कि ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज कर गोल्ड खरीदे या फिर चांदी खरीदे लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपील की है, उससे व्यवसाय और इसे जुड़े लोगों का नुकसान है। इस अपील के बाद व्यापार काफी कम हो गया है ना सिर्फ व्यापारी बल्कि कारीगर व व्यापार से जुड़े सभी लोग प्रभावित हो गए हैं।

पीएम ने ऐसी अपील नही करनी चाहिए थी- महेंद्र सुराना

मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान सराफा एशोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता व सराफा व्यापारी महेन्द्र सुराना ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील को व्यापार, व्यापारी और कामगार के हित में गलत बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ऐसे समय अपील कर रहे है, जब पांच राज्यों के चुनाव खत्म हो गए है। जबकि वर्तमान में शादी-ब्याह का सीजन है, सनातन धर्म में शादी को 13 वां संस्कार माना गया है, जिसमें बहु-बेटियों को सोने का आभूषण देकर उसे विदा करने की परंपरा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील से लोग भृमित हो रहे है।पीएम ने ऐसी अपील नही करनी चाहिए थी यह महिलाओं की भावना के विरूद्ध भी हैं। प्रधानमंत्री की अपील भी व्यापार के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अभी मात्र एक से डेढ़ महीने का सीजन बचा है यदि शादी की सीजन में भी व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा व्यापारी सिर्फ आभूषण नहीं भेजता बल्कि पुराने आभूषण को खरीदना भी है उसकी मरम्मत को करता है पीएम मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया है यह सर्राफा व्यापारियों के लिए ठीक नहीं है आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति बनते जा रही है।

झूठी एफआईआर दर्ज करने का आरोप, ग्रामीण पहुंचे एसपी कार्यालय

निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर महिलाओं और ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, राजनीतिक रंजिश में मामला दर्ज होने का लगाया आरोप

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम गर्रा में एक बार फिर सामाजिक विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव में समाज बहिष्कार को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। मामला पवार समाज से जुड़ा हुआ है, जिसमें समाज के कुछ लोगों पर परिवार को समाज से बाहर करने और बाद में दोबारा समाज में शामिल करने के लिए रुपए मांगने के आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार, दूसरे समाज में बेटी

विवाह करने को लेकर संबंधित परिवार को समाज से बाहर कर दिया गया था। आरोप है कि बाद में समाज में पुन: शामिल करने के बदले राशि की मांग की जाने लगी। इस संबंध में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने पवार समाज के गणेश चौहान और दिलीप चौहान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मामले में दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में ग्रामीण और संबंधित पक्ष के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पुन: जांच किए जाने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि मामले में एकतरफा कार्रवाई की गई है और सभी पक्षों को ठीक तरह से नहीं सुना गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाया जाए, ताकि किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी होने की बात कही जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ग्रामीण गणेश चौहान और सूरजलाल बिसेन ने बताया कि गांव के कुछ लोगों द्वारा 11 मई को कोतवाली थाना में धारा 308(2) के तहत मामला दर्ज कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह प्रकरण राजनीतिक और आपसी रंजिश के चलते दर्ज कराया गया है तथा पुलिस द्वारा बिना प्रारंभिक जांच किए ही एफआईआर दर्ज कर ली गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि गर्रा स्थित एक दुकान में कुछ लोगों द्वारा समाज में मिलाने के नाम पर पैसों की मांग की गई थी। इसी विवाद को लेकर बाद में मामला दर्ज कराया गया। ग्रामीणों ने दावा किया कि घटना के दिन और समय पर दिलीप भैरम अपने घर पर परिवार के साथ मौजूद था, जबकि गणेश चौहान ग्राम गर्रा से लगभग 100 किलोमीटर दूर कान्हा मुक्की क्षेत्र के एक रिसॉर्ट में फेब्रिकेशन कार्य कर रहा था। ऐसे में दोनों के खिलाफ दर्ज प्रकरण को पूरी तरह झूठा और तथ्यहीन बताया गया। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही घटना स्थल के आसपास मौजूद संभावित प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के बयान लिए जाएं। उन्होंने यह भी मांग की कि यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो संबंधित शिकायतकर्ता के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि इस प्रकार की एकतरफा कार्रवाई से गांव का सामाजिक वातावरण प्रभावित हो सकता है और आपसी तनाव बढ़ सकता है। पीड़ित गणेश चौहान ने कहा कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि सामाजिक लोगों और ग्रामीणों के साथ वे एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। उनका कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। गणेश चौहान ने बताया कि गांव के ही समाज के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी दूसरे समाज में करवाई थी। समाज के कुछ पारंपरिक नियमों के तहत उस व्यक्ति पर सामाजिक दंड लगाए जाने की बात चल रही थी। इसी बात को लेकर संबंधित व्यक्ति ने उन पर झूठा आरोप लगाते हुए रुपए मांगने की शिकायत दर्ज करवा दी, जो पूरी तरह गलत और निराधार हैं। वहीं सूरजलाल बिसेन ने कहा कि पूरा मामला संदिग्ध और गलत प्रतीत होता है। गांव के लोग चाहते हैं कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने बताया कि न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और सामाजिक लोग एसपी कार्यालय पहुंचे थे।

एक सप्ताह से स्लॉट बुकिंग ठप, अन्नदाता हो रहे परेशान, जिम्मेदार मौन

समर्थन मूल्य में गेंहू खरीदी जारी, 490 किसानों से 12,625 क्विंटल गेंहू की हुई खरीदी

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुए अभी कुछ ही समय बीता है, लेकिन सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई गहरी होती नजर आ रही है।

नगर मुख्यालय के पांढरवानी से टेंगनीकला पहुंच मार्ग अनय वेयर हाउस में वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति लालबर्रा के द्वारा समर्थन मूल्य में गत दिवस से गेंहू की खरीदी की जा रही है। लेकिन पिछले एक सप्ताह से स्लॉट बुकिंग का सर्वर पूरी तरह ठप होने के कारण किसानों के लिए अपनी उपज बेचना एक बड़ी चुनौती बन गया है और अन्नदाता उपज विक्रय करने के लिए खरीदी केन्द्रों का चक्कर लगा रहे है। जबकि 23 मई तक स्लॉट बुकिंग किया जाना है उसके पहले ही पोर्टल नही चलने से किसान परेशान है। अगर स्लॉट बुकिंग नही होने पर किसान उपज विक्रय करने वंचित हो सकते है। किसानों ने शासन-प्रशासन से स्लॉट बुकिंग का पोर्टल जो बंद है किसी कारण वश उसे चालू करवाने की मांग की है ताकि स्लॉट बुकिंग कर किसान गेंहू उपज समर्थन मूल्य में विक्रय कर सके। वहीं लालबर्रा वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति के द्वारा अनय वेयर हाउस में गेंहू खरीदी की जा रही है और 584 किसानों ने स्लॉट बुकिंग करवाये है। जिसमें से अब तक 490 किसानों से 12,625 क्विंटल गेंहू समर्थन मूल्य में खरीदी की गई है। वहीं एक सप्ताह से स्लॉट बुकिंग नही होने से शेष किसान उपज विक्रय हेतु परेशान हो रहे है और जब तक उनका स्लॉट बुकिंग नही होगा वे उपज विक्रय नही कर सकते।

नियमों के फेर में फंसा किसान

आपकों बता दे कि शासन के द्वारा समर्थन मूल्य 2585 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेंहू की खरीदी की जा रही है। वहीं इस वर्ष प्रशासन के द्वारा पिछले वर्ष गर्मी के दिनों में जो जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसको मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष लालबर्रा क्षेत्र के किसानों से रबी सीजन में धान की फसल न लगाने की अपील की गई थी और कम पानी वाली फसल लगाने कहा गया था। जिसका ही परिणाम है कि इस वर्ष क्षेत्र के अधिकांश किसानों ने अपने खेतों में गेंहू की फसल लगाये और उत्पादन भी अधिक लिये है। शासन के द्वारा लालबर्रा विकासखण्ड में समर्थन मूल्य में गेंहू उपज की खरीदी के लिए मात्र एक खरीदी केन्द्र वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति लालबर्रा को बनाया गया है। जिनके द्वारा पूर्व में सिवनी मार्ग पावर हाउस के समीप स्थित वेयर हाउस में खरीदी की गई। जहां अव्यवस्था होने के कारण किसानों व कर्मचारियों को उपज विक्रय एवं खरीदी करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जहां कुछ दिनों तक खरीदी होने के बाद स्थान परिवर्तन कर अब पांढरवानी-टेंगनीकला पहुंच मार्ग अनय वेयर हाउस में खरीदी की जा रही है। लेकिन वह भी इस भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे खरीदी की जा रही है। जिससे किसानों व कर्मचारियों को खरीदी करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही विकासखण्ड में गेंहू खरीदी के लिए एक ही खरीदी केन्द्र बनाया गया है जहां क्षेत्र भर के किसान बड़ी संख्या में उपज विक्रय करने पहुंच रहे है। वहीं गुरूवार तक वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति के द्वारा 490 किसानों से 12,625 क्विंटल गेंहू की खरीदी की गई है। लेकिन एक सप्ताह से स्लॉट बुकिंग नही हो रहा है जिससे किसान परेशान है क्योंकि शासन द्वारा तय किये गये मापदंडों के अनुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन के बाद स्लॉट बुकिंग अनिवार्य है। बिना ऑनलाइन स्लॉट बुक किये खरीदी केंद्रों पर तौल संभव नहीं है। पिछले सात दिनों से पोर्टल का सर्वर डाउन होने की वजह से किसान स्लॉट बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। इस तकनीकी खराबी ने पूरी खरीदी प्रक्रिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है।

शीघ्र समाधान की मांग

जिन किसानों का स्लॉट बुकिंग नही हुई है ऐसे किसान प्रतिदिन खरीदी केन्द्र और कियोस्क सेंटरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सर्वर एरर के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने खून-पसीना एक कर फसल तैयार की है, लेकिन अब उसे बेचने के लिए उन्हें सिस्टम की खामियों से लड़ना पड़ रहा है। किसानों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि जब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो तकनीकी बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाना चाहिए। सर्वर की समस्या का त्वरित निराकरण हो ताकि किसान अपनी उपज सही समय पर और सही दाम पर बेच सकें और समर्थन मूल्य का लाभ ले सकें।

स्लॉट बुकिंग नही हो रहे है - गणेश

चर्चा में वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति लालबर्रा के खरीदी प्रभारी गणेश लांजेवार ने बताया कि शासन के निर्देश पर गत दिवस से समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी की जा रही है और 584 किसानों ने उपज विक्रय करने स्लॉट बुकिंग करवाये है। जिसमें से 490 किसानों से 12,625 क्विंटल गेंहू की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही यह भी बताया कि एक सप्ताह से नये स्लॉट बुकिंग कार्य ठप है, पोर्टल नही खुल रहा है सर्वर की समस्या के कारण, उक्त संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। श्री लांजेवार ने बताया कि किसान स्लॉट बुकिंग करवाने आते है, लेकिन पोर्टल नही चलने पर वापस हो रहे है। साथ ही 31 मई तक 2585 रूपये समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीदी की जायेगी।

समाज के समृद्ध लोग सामूहिक विवाह सम्मेलनों में विवाह का करें ट्रेंड सेट-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सनातन संस्कृति में विवाह जन्म-जन्मांतर का पवित्र बंधन है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे वर-वधुओं के लिए आने वाला समय कई जिम्मेदारियां लेकर आता है। सभी परिवारों के लिए विवाह का आयोजन आनंद और उत्सव का वातावरण निर्मित करता है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक ही मंडप में समाज के विभिन्न वर्गों के बेटे-बेटी वैवाहिक बंधन में बंधते हैं, सामूहिक चेतना का यह उत्सव फिजूल खर्ची और दिखावे पर रोक का संदेश देता है। सरकार और समाज ने जब से सामूहिक विवाह का बीड़ा उठाया है तब से गरीब माता-पिता ने चैन की सांस ली है। समाज के समृद्ध लोग सादगी को अपने व्यवहार में उतारे और सामूहिक विवाह सम्मेलनों में विवाह का ट्रेंड सेट करें। इससे समाज का हर वर्ग विवाह के अनावश्यक खर्च से बचेगा और उपलब्ध संसाधनों का परिवार के भविष्य निर्माण में उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि उन्होंने स्वयं भी अपने पुत्र का विवाह सामूहिक सम्मेलन में ही किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बेटियों की शिक्षा की चिंता करना और उसके लिए पर्याप्त प्रबंध करना, हर माता-पिता का दायित्व हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित 200 बेटियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर-वधु को आशीर्वाद प्रदान कर उनके परिजन को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दिसंबर 2023 से अप्रैल 2026 तक 1 लाख 70 हजार 187 बेटियों के विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत कराये गए है। योजना अंतर्गत अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन से आर्थिक रूप से कमजोर भाई-बहनों की बेटियां भी पूरे सम्मान के साथ विदा होती हैं। समाज का कोई भी वर्ग हो, बच्चों का विवाह हर माता-पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सामूहिक विवाहों के आयोजन से अब विवाह के लिए माता-पिता को कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है। समाज और सरकार एक-दूसरे के पूरक हैं। परिवर्तन के लिए समाज और सरकार दोनों का हाथ मिलाकर चलना जरूरी है। सामूहिक विवाह सम्मेलन जैसे आयोजन वर्तमान समय में समाज सेवा का सर्वोत्तम माध्यम बन चुके हैं।

लाखों की लागत से बना सामुदायिक स्वच्छता परिसर बदहाली का शिकार

देखरेख के अभाव में शराबियों का अड्डा बना सुलभ शौचालय, साफ-सफाई करवाने की उठी मांग

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए लाखों रूपये खर्च कर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। लेकिन प्रशासन और ग्राम पंचायत की उदासीनता के कारण ये परिसर अब सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लालबर्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खारी का सामने आया है। जहां लाखों रूपयों की लागत से बना सुलभ शौचालय देखरेख के अभाव में उक्त स्थान पर शराब की बोतलों का अंबार लगा हुआ है एवं गंदगी भी फैली हुई है। इस तरह से देखरेख के अभाव में सुलभ शौचालय शराबियों का गड्ढा बना हुआ है। लेकिन उसकी देख-रेख एवं साफ-सफाई की ओर जिम्मेदारों के द्वारा कोई ध्यान नही दिया जा रहा है जिससे ग्रामीणजनों में आक्रोश व्याप्त है।

गंदगी और शराब की बोतलों का अंबार

आपकों बता दे कि ग्राम पंचायत खारी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सार्वजनिक रूप से लाखों रूपयों की लागत से सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया गया है ताकि दुर-दराज से आने वाले लोग एवं ग्रामीणजन उसका उपयोग कर सके। लेकिन जिन लोगों के द्वारा उक्त सुलभ शौचालय का उपयोग किया जाता है उन्ही के द्वारा गंदगी की जा रहा है। लेकिन उसकी देख-रेख एवं साफ-सफाई पर पंचायत के द्वारा विशेष ध्यान नही दिया जा रहा है तभी तो लाखों रूपयों की लागत से बना सुलभ शौचालय में शराब की बोतल सहित गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में जिस मंशा से शासन के द्वारा सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया है उसका उपयोग बाहर से आने वाले एवं ग्रामीणजन नही कर पा रहे है। इस तरह से सफाई के बड़े-बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत यह है कि इस स्वच्छता परिसर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात के समय यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। परिसर के पास शराब पीकर खाली बोतलें फेंकी जा रही हैं, जिससे स्व'छता परिसर की स्थिति बेहद खराब हो रही है। जबकि विगत वर्ष पूर्व ही लाखों रूपयों की लागत से सुलभ शौचालय का निर्माण करवाये गये थे ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। परंतु वर्तमान में दीवारों पर लिखे स्व'छ भारत, स्वस्थ भारत के नारे केवल उपहास बनकर रह गये हैं। देखरेख के अभाव में यह भवन धीरे-धीरे जर्जर हो रहा है और इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणजनों ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि इस परिसर की नियमित रूप से साफ- सफाई और असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करें ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

जल्द सफाई करवा दी जायेगी - डिलेश्वरी

दूरभाष पर चर्चा में खारी सरपंच श्रीमती डिलेश्वरी नखाते ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पंचायत के सामने सुलभ शौचालय का विगत वर्ष पूर्व निर्माण किया गया है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए और समय-समय पर उसकी साफ-सफाई भी करवाई जाती है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा रात्रि के समय उक्त स्थान पर शराब पीकर उसकी बोतल को वही छोड़ देते है एवं गंदगी की जा रही है जो गलत है। जबकि सभी की सुविधा के लिए सुलभ शौचालय बना हुआ है और स्व'छता बनाये रखना चाहिए। आगे बताया कि जल्द सफाई करवा दी जायेगी और अगर कोई गंदगी करते पाये जाते है तो उन पर कार्यवाही की जायेगी एवं ग्रामीणजनों से भी अपील है कि स्वच्छता बनाये रखे।

औल्याकन्हार फिजिकल क्लब का मैदान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार के सहयोग से जगमगाया

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। औल्याकन्हार का फिजिकल क्लब खेल मैदान लालबर्रा क्षेत्र की एक पहचान बन चुका है। जिसमें वर्तमान समय में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जारी है। यह आयोजन खेल युवा कल्याण विभाग बालाघाट के निर्देशानुसार किया जा रहा है। जिसमें 1 मई से 30 मई तक कक्षा पहली से 12 वीं कक्षा के बच्चें व खिलाड़ी पहुंचकर खेल की बारीकियां सीख रहे है। वही इस खेल मैदान में पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार से हाई मास्ट लाइट लगाने की मांग की गई थी। जिनके सहयोग से उक्त मैदान में हाई मास्ट लाइट लगा दी गई है। जिसके बाद अब फिजिकल क्लब खेल मैदान प्रकाश से जगमगा गया है और प्रकाश की व्यवस्था हो जाने से शाम के समय भी बच्चें एवं खिलाड़ी खेल का प्रैक्टिस (अभ्यास) कर सकते है। फिजिकल क्लब के अध्यक्ष ओपी बिसेन ने बताया कि फिजिकल क्लब खेल मैदान में गत 1 मई से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर जारी है जो 30 मई तक चलेगा। इस शिविर में कक्षा पहली से बारहवीं तक के बच्चे आसपास के ग्रामों से पहुंचते है। जिन्हे विभिन्न खेल की गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं मुख्य अतिथि और विद्वानों की उपस्थिति प्रशिक्षुओं में नई ऊर्जा, अनुशासन और सीखने के प्रति उत्साह का संचार करती है। शिविर की खास बात यह है कि प्रतिदिन नये-नये अतिथियों का आगमन होते रहता है जिससे बच्चों के दिमाग में निम्नलिखित प्रभाव प्रभाव पड़ता है जैसे-उनके अनुभव से प्रतिभागियों को वास्तविक चुनौतियों का बोध होता है, वरिष्ठों की उपस्थिति से शिविर की गंभीरता और महत्व बढ़ जाता है। उनके विचार भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहायक होते हैं, जिस मैदान पर लालबर्रा क्षेत्र के बच्चे अपनी अपनी प्रतिभाओं को निखारने के साथ-साथ फिजिकल गतिविधियां सुबह - शाम करते हैं। उन्हीं बच्चों की आवाज को जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने सुना और जिला पंचायत के पांचवें वित्त मद से 2 लाख की राशि हाई मास्ट लाइट के लिए स्वीकृत कर दी। आगे बताया कि ग्राम पंचायत के माध्यम से हाई मास्ट लाईट लगाया जा चुका है। हाई मास्ट लाइट लगने से खिलाड़ियों को रात्रि में खेल अभ्यास की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो चुकी है। श्री बिसेन ने बताया कि जनप्रतिनिधि द्वारा बच्चों से किया गया वादा पूरा करना समाज में विश्वास और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। जब कोई नेता बच्चों की शिक्षा, खेल या सुविधाओं से जुड़ा संकल्प पूरा करता है, तो इसके कई लाभ होते हैं। बच्चों का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास बढ़ता है, यह समाज के अन्य लोगों को भी सेवा के लिए प्रेरित करता है, बेहतर सुविधाओं से बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है।

बच्चों एवं खिलाड़ियों को मिलेगी सुविधा - प्रेमलता

वहीं सरपंच श्रीमती प्रेमलता/ओमप्रकाश बिसेन ने जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सरस्वार का आभार जताते हुए बताया कि एक सक्रिय जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि वह स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाये। खेल के मैदान में आधुनिक हाई मास्ट लाइट की स्थापना न केवल खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करती हैं, बल्कि यह क्षेत्र के युवाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का भी प्रतीक है। श्रीमती बिसेन ने बताया कि हाई मास्ट लाइट लगने से अब चिलचिलाती धूप से बचकर खिलाड़ी अब शाम और रात के समय भी अपनी तैयारी जारी रख पायेगें, रोशनी से मैदान सुरक्षित होता है, जिससे महिला खिलाड़ियों और स्थानीय निवासियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। अब गांव या शहर के इस मैदान पर डे-नाइट टूर्नामेंट्स का आयोजन संभव हो सकेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम दर्शाता है कि जब नेतृत्व खेल और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, तो समाज की ऊर्जा को सही दिशा मिलती है। इस सराहनीय कार्य के लिए सरपंच श्रीमती प्रेमलता बिसेन, फिजिकल क्लब के अध्यक्ष ओमप्रकाश बिसेन, सचिव शरद धानेश्वर, पंच कोमल बोपचे, श्रीमति रविता पांडे, श्रीमति डिलेश्वरी बोपचे, दीपक कटरे, श्रीमती सरला यादव, श्रीमती पुष्पा चौहान, संदीप गुनेश्वर, शंकरलाल यादव, शीतलप्रसाद हरिद्वाज, झामसिंह राणा, परमानंद नागेश्वर, सालिकराम कटरे, नगारची नागेश्वर, महेद्र चौहान, मुकेश चौहान, प्रमोद चौहान, सुनील यादव, प्रहलाद बिसेन, भुवनेश्वर कटरे, उम्मेद चावले, रामप्रसाद राणा, श्यामकिशोर यादव, कृष्णा सहारे, सुरेश नागेश्वर, मुकेश यादव, ओमकार सहारे, विरेन्द्र मराठा, तपेश रंगारे, सुलेमान खान, पुनाराम बिसेन, सुनील बिसेन, भुनेश्वर कटरे, नागेश चौधरी सहित अन्य ग्रामीणजनों ने जिला पंचायत अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया है।

क्या नगर पालिका अध्यक्ष सक्षम नहीं है जनता की समस्याओं का समाधान करने-विवेक पटेल

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी।

कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में विधायक पटेल ने की प्रेसवार्ता आयोजित

वारासिवनी कांग्रेस के जनसंपर्क कार्यालय में गुरूवार को क्षेत्रीय विधायक विवेक पटेल के द्वारा प्रेसवार्ता आयोजित की गई। प्रेसवार्ता आयोजन के दौरान विधायक विवेक पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में पेपर माफियाओं ने पूरे देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को अपने कब्जे में ले लिया है। जिस देश में शिक्षा और परीक्षा पेपर माफियाओं के हवाले हो जाए। वहां लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है आखिर नीट का पेपर कैसे लीक हुआ और वह कौन सा एजुकेशन माफिया है। जिसके तार भाजपा नेताओं के साथ केंद्र सरकार तक जुड़े हुए हैं, भाजपा सरकार के राज में कई बार पेपर लीक हो चुका है। ३ मई को होने वाली नीट पेपर को रद्द कर दिया गया जिससे लगभग २२ लाख विद्यार्थियों का भविष्य पर अंधकार के बादल छा गए है। नई तारीख कब तक आएगी क्या दुबारा आवेदन या फीस नहीं देनी होगी। विधायक पटेल ने कहा कि सरकार को इस पर छात्रहित में गंभीर चिंतन और उनका निवारण करना चाहिए। पेपर कैसे लीक होता है,कैसे बिक जाता है इस पर सरकार को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

गेहूं खरीदी में स्लॉट नहीं हो रहे बुक

विधायक पटेल ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के द्वारा इकतीस सौ रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का भरोसा किसानों को दिया गया था। सरकार बनने के बाद भी आज तक इकतीस सौ रुपए में धान नहीं खरीदा जा रहा है। वही समर्थन मूल्य पर बेची जाने वाली फसलों के विक्रय स्लॉट बुक नहीं हो रहे है। जिससे गेहूं,चना की उपज को समय पर विक्रय नहीं किया जा रहा है और सरसो की उपज को खरीदने की बात करके अब तक खरीदी नहीं हो रही है।

रेत का ठेका नहीं होने से क्षेत्र के हितग्राही हो रहे परेशान

बालाघाट जिले में रेत का ठेका नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास, सांसद निधि और विधायक निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जिससे जनता को रेत के लिए परेशान होना पड़ रहा है ग्रामीण क्षेत्र के रहवासी अपना कच्चा मकान तोड़कर झोपड़े में रहकर निवास के रहे है ऐसे में उन्हें मकान बनवाने रेत नहीं मिल रही है। हमने अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की है अगर जल्द ही जनता को रेत नहीं मिलेगी तो हमें सड़को पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा।

जिसे कोई अधिकार नहीं है वह नपा अध्यक्ष की कुर्सी में जाकर बैठ रहे है

विधायक पटेल ने कहा कि मैं विधायक हुं कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या सुनता हुं। हमारे देश में लोकतंत्र है, मैं नगर पालिका अध्यक्ष था। उसके बाद मैं कभी वहां नहीं गया हमारे नगर की जनता ने पार्षद चुने है। और पार्षदों ने अपना अध्यक्ष चुना है,मगर जिसे कोई अधिकार नहीं है वह नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी में जाकर बैठ रहे है। जिस महिला को जनता ने चुना है,उसके अधिकार को छीनकर उसकी कुर्सी में बैठ रहे है। क्या हमारी नगर पालिका अध्यक्ष सक्षम नहीं है जनता की समस्याओं का समाधान करें जो किसी पद पर नहीं है उसे अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का क्या अधिकार है। ना ही पार्षद है,और ना ही एल्डर मेन है ये एक महिला के अधिकार का हनन करना है। चार वर्षों तक कभी जनता दरबार नहीं लगा उन्हें पता चल रहा है कि अब नगर पालिका की गद्दी खसकने वाली है इसलिए अब जनता की याद आ रही है।

वारासिवनी नगर पालिका में चल रही भर्राशाही

विधायक पटेल ने कहा कि इस समय नगर की जनता के कुछ भी काम नहीं हो रहे है व्यापारी जब किसी काम से नगर पालिका पहुंचता है तो उससे पैसे की मांग की जाती है। कुछ दिन पूर्व नगर पालिका में पैसे की लेन देन को लेकर परिषद के अंदर कार्यकर्ताओं का विवाद भी हुआ था। भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है,मगर हमारे क्षेत्र में महिला जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं मिल रहा है। नगर पालिका कौन चला रहा है समझ नहीं आता नपा अध्यक्ष आज तक किसी भी वॉर्ड में जनता की समस्या सुनने नहीं पहुंची। जिससे नगर की जनता का अब नगर पालिका के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है।

सीएम राइज स्कूलो में निजी स्कुलो के बच्चों को नही मिल रहा प्रवेश

बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की बड़ी बड़ी बाते सरकार करती है मगर हकीकत में शिक्षा का क्या हाल है किसी से छुपाया नहीं जा सकता है। जब ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी कक्षा ५ वीं क्लास पास करके सीएम राइज स्कूल में प्रवेश के लिए जा रहा है। तो उसे एडमिशन नहीं मिल रहा है इस मंहगाई के दौर में गरीब घर का छात्र कैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करेगा। सरकार को इसकी चिंता होनी चाहियें

प्रेसेवार्ता के दौरान ये रहे मौजूद

इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सुनील राणा, युवा विधानसभा अध्यक्ष टिकेंद्र पटले, विधायक प्रतिनिधि गगन बिसेन, राजकुमार चौधरी, देवी लिलहारें,शैलेन्द्र पटेल,संदेश बिसेन, सत्तू बिसेन, अनिल गौतम सहित अन्य कांग्रेसीजन मौजूद रहे।

गर्राटोला में किसान का आशियाना जलकर खाक

आग ने छीनी साल भर की गाढ़ी कमाई लाखों का हुआ नुकसान

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। रामपायली थाना अंतर्गत ग्राम गर्रा के वार्ड नंबर ४ गर्राटोला में गुरुवार की सुबह एक भीषण अग्निकांड हुआ। यहाँ रहने वाले किसान प्रहलाद बिसेन अपने परिवार के साथ ग्राम सालेटेका में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए थे तभी पीछे से उनके आशियाने में आग लग गई। इस साथ शादी समारोह में गए थे। सुबह करीब ९.३० बजे अचानक मकान से आग की लपटें उठने लगीं। घर पर मौजूद महिलाओं के शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़कर आए और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलने पर नगर पालिका परिषद वारासिवनी से दमकल वाहन मौके पर पहुँचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

भले ही आग बुझ गई लेकिन तब तक प्रहलाद बिसेन का सब कुछ लुट चुका था। घर में रखा साल भर का राशन १२कट्टी धान, ४ कट्टी चावल, ३ कट्टी गेहूं, ३ कट्टी महुआ, २ कट्टी लखोड़ी, नगदी रूपये, कपड़े और खेती के उपकरण जलकर राख हो गए। किसान के पास खुद की जमीन नहीं है वह अधिया और ठेके पर जमीन लेकर खेती करता है। परिवार के सामने आए इस संकट को देख पड़ोसियों ने अनाज जमा कर पीड़ित परिवार को दिया है। इस आगजनी में पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है तो वहीं परिवार के घटना में किसान की पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रहलाद बिसेन अपनी पत्नी और माताजी को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों के सामने कई प्रकार की समस्या भी खड़ी हो गई है । ऐसे में पीडित परिवार के द्वारा शासन से उचित मुआवजा दिये जाने की मांग की गई है।

कोस्ते माइनर नहर की जर्जर हालत ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें

एक हजार एकड़ की सिंचाई संकट में,शिकायतों पर लीपापोती तक सीमित विभागीय अधिकारी

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। एक तरफ सरकार हर खेत को पानी पहुंचाने का दावा कर रही है वहीं दूसरी ओर वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोस्ते के किसान सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही का दंश झेल रहे हैं। क्षेत्र की महत्वपूर्ण माइनर नहर जो कासपुर से होकर कोस्ते तक आती है वर्तमान में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आलम यह है कि नहर में गाद मिट्टी और झाड़ियों का इस कदर अंबार लगा है कि खेतों तक पानी पहुंचना तो दूर नहर का अस्तित्व पहचानना भी मुश्किल हो रहा है।

आधा अधूरा सीमेंटीकरण और विभागीय लीपापोती

प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में बूटी नहर के माध्यम से पानी का वितरण किया जाता है। इसी की एक शाखा कासपुर से आलेझरी के लिए निकलती है जिससे एक माइनर नहर ग्राम कोस्ते को जोड़ती है। किसानों की सुविधा के लिए इस माइनर का सीमेंटीकरण कार्य स्वीकृत किया गया था लेकिन यह कार्य आधा अधूरा ही किया गया। कोस्ते तक आने वाला करीब २ किलोमीटर का हिस्सा आज भी कच्चा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग को हजारों बार शिकायतें दी गईं लेकिन हर बार एन मौके पर खानापूर्ति और लीपापोती कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया जाता है। नहर की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि इसमें गहरी गाद जमा है और झाड़ियां पनप गई हैं। रिहायशी इलाकों के पास स्थित नहर के हिस्सों में सांप और बिच्छू का खतरा बढ़ गया है। विभाग की निष्क्रियता से तंग आकर अब ग्रामीण स्वयं के खर्च और मेहनत से नहर की झाड़ियों की सफाई करने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि जब फसल कटती है तब विभाग पानी का पैसा वसूलने में तो तत्परता दिखाता है लेकिन सिंचाई के समय उन्हें पानी के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है। इस माइनर नहर के भरोसे करीब १००० एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई निर्भर है। नहर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने के कारण किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए महंगे ट्यूबवेल और अन्य निजी जल स्रोतों पर निर्भर होने को मजबूर हैं। इससे किसानों की लागत बढ़ रही है और सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ रहा है। कोस्ते के किसानों ने विभाग से मांग की है कि वर्तमान सूखे समय का सदुपयोग करते हुए नहर का व्यवस्थित सुधार और शेष २ किलोमीटर का सीमेंटीकरण किया जाए। ग्रामीणों का तर्क है कि विभाग अक्सर बरसात के समय कार्य शुरू करने का ढोंग करता है जिससे कोई स्थायी लाभ नहीं मिलता। यदि अभी गर्मी के मौसम में गाद निकाली गई और मरम्मत हुई, तभी मानसून के दौरान खेतों तक सुचारू रूप से पानी पहुंच पाएगा। अब देखना यह है कि सिंचाई विभाग इन अन्नदाताओं की पुकार सुनता है या फिर इस बार भी किसानों को अपनी किस्मत और सूखे नहर के भरोसे ही रहना पड़ेगा।

नहर की समस्या हमारे यहां कई वर्षो से बनी हुई है-रमेश ठाकरे

ग्रामीण रमेश ठाकरे ने बताया कि नहर की समस्या हमारे यहां बनी हुई है इस नहर का थोड़ी दूर सीमेंटीकरण किया गया है बाकी छोड़ दिया गया है। कोस्ते तक करीब २ किलोमीटर का सीमेंटीकरण नहीं हुआ है जंगली फाल हमारे कहते हैं वहां तक हुआ है। कासपुर से यह नहर आता है करीब २ वर्ष पहले यह निर्माण हुआ था वहां तक अच्छा पानी आता है। फिर हमारे इधर पानी नहीं आ पाता शिकायत पर विभाग आकर थोड़ा बहुत दिखावा कर चले जाते हैं। साहब आते ही पानी आता है और जाते ही पानी चला जाता है। पहले पंचायत के द्वारा यह कार्य किया जाता था परंतु वह देखने नहीं मिल रहा है शायद वह बंद कर दिया गया है यह जो नहर है इसका सीमेंटीकरण होना चाहिए।

सिचांई विभाग के अधिकारी सफाई के नाम सिर्फ आश्वासन देते है-डालीचंद पटले

ग्रामीण डालीचंद पटले ने बताया कि नहर के पानी की बहुत ज्यादा हमारे यहां दिक्कत है नहर में झाड़ी काटे और मिट्टी भर गई है। बारिश में पानी नहर में आता नहीं लाना पड़ता है कई किसान स्वयं के साधन से नहर को सुधारते हैं। तो वहीं कई किसानों ने पानी नहीं मिलने की समस्या को देखते हुए बोरवेल करवा लिए है। इस प्रकार नहर की स्थिति हमारे यहां बनी हुई है हम लोगों को ही नहर में साफसफाई करनी पड़ती है यह आज कल नहीं कई वर्षों की समस्या है। जब से खेती कर रहे हैं देख रहे हैं यह जो नहर है इससे करीब १००० एकड़ खेती भूमि की सिंचाई की जाती है पानी यहां तक आता है आगे नहीं जाता है। विभागीय अधिकारी दिखाई नहीं देते हैं बस वह फसल कटते ही रुपये लेने के लिए आ जाते हैं जब उन्हें बोला जाए तो वहां केवल आश्वासन देते हैं इस व्यवस्था पर सुधार होना चाहिए।

महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबीनार का हुआ आयोजन

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। शासकीय एसएसपी महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के द्वारा गुरुवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वर्चुअल सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्जवलन से हुआ। यह वेबीनार महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सरिता कोल्हेकर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जो मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रायोजित था। कार्यक्रम का संयोजक एवं रसायन शास्त्र विभागध्यक्ष मोहनीष इडपाचे ने बताया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल ११ मई को मनाया जाता हैं जो कि ११ मई १९८८ को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण एवं भारत की तकनीकि आत्मनिर्भरता की याद दिलाता हैं। इस कार्यक्रम में डॉ. वसीम आर शेख सहायक प्राध्यापक मुलजीजेठा कॉलेज, जलगांव महाराष्ट्र से जुडे उन्होंने अपने व्याख्यान के माध्यम से विज्ञान को दैनिक प्रयोग में उपयोग कि जाने वाली सामग्री प्रेषर कुकर, कुलर और एसी से जोडकर समझाया और इनकी कार्यप्रणाली को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया। कार्यक्रम के दूसरे विषेषज्ञ डॉ. एन नदीम अफ्रेज सहायक प्राध्यापक, इस्लामिया कॉलेज वानियामबाडी तमिलनाडु से जुडे जिन्होंने वैज्ञानिक सृजन शीलता मॉडल के तीन आयामो को समझाया पहला रचनात्मक सोच, दूसरा वैज्ञानिक ज्ञान और तीसरा वैज्ञानिक जॉच कौशल' अर्थात केवल विचार और ज्ञान ही नहीं बल्कि उन्हे परखने और साबित करने की क्षमता वैज्ञानिक सृजन शीलता को पूरी करती हैं। विभाग की सहायक प्राध्यापक सविता सेनवार ने कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य में अतिथि विद्वान डॉ. नॅदिनी टेंभरे, श्रीमती मोनिका सोनी,डॉ0 मनोज गजभिये ,श्रीमती सविता सेनवार ने सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

पेपर लीक-लचर न्याय प्रक्रिया के साइड इफेक्ट

एक बार फिर नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई। पिछले दस सालों में यह चौथा मौका है जब देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक नीट यूजी में पेपर लीक होने की घटना हुई है। नीट के अलावा पिछले दस सालों में लगभग सौ प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द की गई हैं। विश्वगुरु होने का दावा करने वाले देश के लिये यह बेहद शर्मनाक घटना है। प्रतियोगी परीक्षा के पीछे केवल परीक्षार्थियों की मेहनत और महत्वाकांक्षा ही ध्वस्त नहीं होती, उनके परिवार के सपने भी टूटते हैं और सारा त्याग और सम्बल व्यर्थ हो जाता है। साथ ही देश के संसाधनों की बरबादी होती है और छात्रों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। उन्नत टेक्नोलॉजी के दौर में देश एक सुरक्षित और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित नहीं कर पाता तो यह सिस्टम की घोर असफलता है। समय और संसाधनों की बरबादी के अलावा ऐसी घटनाओं से देश की प्रतिष्ठा हानि भी होती है। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे कई फैक्टर हैं जैसे छात्रों और उससे ज्यादा उनके परिवारों की महत्वाकांक्षा, गलाकाट प्रतिस्पर्धा, कोचिंग संस्थानों का रैकेट और काला धन। दरअसल पढ़ाई या नौकरी से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा शिक्षा व्यवस्था के दलालों और कोचिंग रैकेट के सरगनाओं के लिए एक कमाई का मौका बन जाती है। पेपर लीक तो सिर्फ पहली सीढ़ी है, उसके बाद मूल्यांकन में गड़बड़ी, मेरिट लिस्ट में हेराफेरी, अलॉटमेंट में जुगा? वगैरह सब पर शिक्षा माफिया का कंट्रोल होता है। अगर कहीं चूक हो जाए तो शोर मच जाता है वरना ये सब घोटाला बदस्तूर चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है; हमारी लचर न्याय प्रक्रिया! समाज के हर क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध वास्तव में कमजोर न्याय प्रक्रिया का साइड इफेक्ट है। मसलन बीसियों बार पेपर लीक हो चुके हैं अथवा नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की गई है मगर हमारी सरकारें कुछ सीखती ही नहीं। लोगों को वर्ष 2013 में मध्यप्रदेश का बहुचर्चित और बदनाम व्यापम घोटाला जरूर याद होगा जिसमें अनेक अपात्रों को मेडीकल कॉलेजों में दाखिला और कई अन्य विभागों में नौकरी दिलाई गई थी। मगर यह किसी को याद नहीं होगा कि पुलिस की चार्ज शीट में लगभग 3000 लोगों के नाम होने के बाद बमुश्किल 100 लोगों को सजा हुई। वह भी लम्बी ट्रायल, जमानत और अपील वगैरह के बाद। ऐसा अमूमन हर घोटाले के साथ होता है। पकड़े जाने पर मीडिया में शोरगुल, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन, जाँच और फिर कानूनी प्रक्रिया का लम्बा दौर। कई बार तो आरोप पत्र ही सालों बाद कोर्ट में पेश होता है। इस लेट लतीफी का लाभ लेकर जमानत पर छूटे चतुर अपराधी सबूतों और गवाहों की भूल भुलैया में केस उलझा देते हैं। आखिर में कुछ लोगों को दण्डित कर मामला खत्म कर दिया जाता है। इस सारी प्रक्रिया में सिस्टम से जुड़े उच्चाधिकारी साफ बच निकलते हैं क्योंकि उनके अलिखित आदेशों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। ये तमाशा केवल पेपर लीक और परीक्षाओं के मैनेज करने तक नहीं बल्कि हर तरह के भ्रष्टाचार में दिखाई देता है। ईडी, इन्कम टैक्स, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जीएसटी वगैरह किसी भी एजेंसी का मामला हो आखिर में अंजाम लगभग यही होता है। डकैती, रेप और हत्या जैसे संगीन अपराधों में भी न्याय प्रक्रिया की कमजोरी और लेट लतीफी आखिर अपराधियों को ही लाभ पहुंचाती है।जनता भी जब-तब उजागर होने वाले नए घोटालों की सनसनी में पुराने मामले भूलती जाती है।

वैश्विक संकटों के दौर में परिवार ही रिश्तों की अंतिम शरणस्थली

(अन्तर्राष्ट्रीय परिवार दिवस-15 मई, 2026)

हर वर्ष 15 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस एक मानवीय रिश्तों का उत्सव ही नहीं, बल्कि मानव सभ्यता को उसकी जड़ों की याद दिलाने का अवसर है। यह दिन हमें बताता है कि दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक, तकनीकी और आर्थिक रूप से विकसित क्यों न हो जाए, मनुष्य की सबसे पहली जरूरत आज भी परिवार ही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिवस इस वर्ष विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, युद्ध, हिंसा, मानसिक तनाव, अकेलेपन और टूटते मानवीय विश्वासों के संकट से गुजर रही है। ऐसे कठिन समय में परिवार केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व, सुरक्षा, संस्कार और संवेदनाओं की सबसे मजबूत छत बनकर सामने आता है।

आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और नैतिक संकट है। बाजार की चकाचौंध ने आदमी को उपभोक्ता तो बना दिया, लेकिन संवेदनशील इंसान नहीं बना सकी। संबंधों में स्वार्थ का प्रवेश हुआ है। विश्वास की जगह संदेह ने ले ली है। आदमी मशीनों से जुड़ रहा है, लेकिन अपनों से कटता जा रहा है। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जा रहे, वे परिवारों के भीतर भी दिखाई देने लगे हैंकृपति-पत्नी के बीच, पीढ़ियों के बीच, भाई-भाई के बीच। संवाद टूट रहे हैं, सहनशीलता घट रही है और 'मैं' का अहंकार 'हम' की भावना को निगलता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में परिवार की भूमिका पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं है, वह जीवन-मूल्यों का विद्यालय है। वहीं मनुष्य पहली बार प्रेम सीखता है, त्याग सीखता है, सहयोग, अनुशासन, धैर्य और सह-अस्तित्व की भावना सीखता है। यदि परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र और विश्व भी संतुलित रहेंगे। इसलिए आज आवश्यकता केवल परिवार बचाने की नहीं, बल्कि परिवारों को मूल्यनिष्ठ बनाने की है।

आज जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, जीवन की आवश्यकताएं महंगी होती जा रही हैं और बेरोजगारी युवाओं के सपनों को तोड़ रही है, तब संयुक्त परिवार की अवधारणा फिर प्रासंगिक बनती दिखाई दे रही है। संयुक्त परिवार केवल आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का भी आधार है। वहां संसाधनों का साझा उपयोग होता है, जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं और संकट अकेले व्यक्ति पर नहीं टूटता। अकेलेपन से उपजी अवसाद की समस्याएं संयुक्त परिवारों में अपेक्षाकृत कम दिखाई देती हैं क्योंकि वहां संवाद और अपनापन जीवित रहता है। वास्तव में आधुनिक सभ्यता ने स्वतंत्रता तो दी, लेकिन उस स्वतंत्रता ने कई बार व्यक्ति को संबंध-विहीन भी बना दिया। महानगरों के छोटे-छोटे फ्लैटों में रहने वाले हजारों लोग आर्थिक रूप से संपन्न होकर भी भीतर से बेहद अकेले हैं।

वृद्ध माता-पिता उपेक्षा के शिकार हैं, बच्चे संस्कारों से दूर हो रहे हैं और पति-पत्नी के बीच संबंधों की ऊष्मा कम होती जा रही है। यही कारण है कि मानसिक रोग, तनाव, असुरक्षा और आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह केवल व्यक्तिगत विफलता नहीं, परिवार संस्था के कमजोर पड़ने का संकेत है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवार को केवल उपभोग और सुविधा का केंद्र न बनाकर उसे अहिंसा की प्रयोगशाला बनाया जाए। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना नहीं है। कठोर शब्दों से बचना, अपमान न करना, एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, क्रोध पर संयम रखना, संवाद बनाए रखना और क्षमा का अभ्यास करना भी अहिंसा है। यदि परिवार के भीतर हिंसक भाषा, कटुता, अपमान और असहिष्णुता होगी तो समाज में शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है? परिवार वह पहला स्थान होना चाहिए जहां बच्चा सहिष्णुता और करुणा का पाठ सीखे। जहां उसे यह सिखाया जाए कि जीवन प्रतियोगिता नहीं, सह-अस्तित्व है। जहां बुजुर्ग बोझ नहीं, अनुभवों की धरोहर माने जाएं। जहां स्त्री को सम्मान मिले, बच्चों को संस्कार मिले और युवाओं को विश्वास मिले। आज दुनिया में बढ़ती हिंसा का एक बड़ा कारण यह भी है कि परिवारों में संवाद और संवेदना कमजोर हो रही है। बच्चे मोबाइल से बातें कर रहे हैं, लेकिन माता-पिता से नहीं। परिवार साथ रहते हुए भी भीतर से बिखर रहा है। जलवायु परिवर्तन, युद्ध और आर्थिक अस्थिरता ने पूरी दुनिया को असुरक्षित बना दिया है। यूक्रेन-रूस युद्ध हो या पश्चिम एशिया के संघर्ष, इन सबका सबसे अधिक प्रभाव परिवारों पर ही प?ता है। लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और महिलाएं असुरक्षा का सामना करती हैं। इन वैश्विक संकटों के बीच परिवार ही वह इकाई है जो टूटे हुए मनुष्य को फिर जीने का साहस देती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष परिवार-केंद्रित नीतियों पर विशेष बल दे रहा है। क्योंकि सतत विकास केवल आर्थिक विकास से संभव नहीं, बल्कि मजबूत और मूल्यनिष्ठ परिवारों से ही संभव है।

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति भी उसका परिवार तंत्र रहा है। यहां परिवार केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य केवल युद्ध कथाएं नहीं, बल्कि पारिवारिक मूल्यों, संबंधों, कर्तव्यों और त्याग की महान गाथाएं हैं। भारतीय जीवनदृष्टि फ़वसुधैव कुटुम्बकम्फ़ की बात करती हैकृअर्थात पूरी पृथ्वी ही परिवार है। यदि इस भावना को व्यवहार में उतारा जाए तो युद्ध, हिंसा, आतंक और घृणा की कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज परिवारों में भी उपभोक्तावादी संस्कृति प्रवेश कर चुकी है। रिश्तों को भी लाभ-हानि के तराजू पर तौला जाने लगा है। सहनशीलता कम हो रही है और अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। छोटी-छोटी बातों पर टूटते संबंध इस बात का संकेत हैं कि हमने सुविधा तो बढ़ाई, लेकिन संवेदना खो दी। जबकि परिवार की असली ताकत संपत्ति नहीं, बल्कि विश्वास होता है। जहां विश्वास बचा रहता है, वहां अभाव भी उत्सव बन जाते हैं; और जहां विश्वास टूट जाता है, वहां वैभव भी बोझ बन जाता है।

आज परिवारों को नई दिशा देने की आवश्यकता है। घरों में सामूहिक भोजन की परंपरा लौटे, संवाद का समय तय हो, बुजुर्गों के अनुभवों को महत्व मिले, बच्चों को केवल करियर नहीं बल्कि चरित्र निर्माण की शिक्षा मिले। परिवारों में क्रोध के स्थान पर करुणा, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग और अधिकार के स्थान पर कर्तव्य की भावना विकसित करनी होगी। यही परिवार को अहिंसा की प्रयोगशाला बना सकता है। दरअसल, भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों की नहीं, मूल्यों की होगी। जिस समाज के परिवार टूट जाएंगे, वहां सामाजिक स्थिरता भी नहीं बचेगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। हमें सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को कैसी दुनिया देना चाहते हैंकृघृणा और अकेलेपन की दुनिया या प्रेम और विश्वास की दुनिया? यदि परिवारों में प्रेम, संवाद, सहिष्णुता, अहिंसा और साझेदारी का वातावरण बनेगा तो दुनिया के बड़े से बड़े संकटों का सामना किया जा सकता है। परिवार केवल एक सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा का आश्रय है। वह जीवन की तपती धूप में शीतल छांव है, संघर्षों में सहारा है और टूटते विश्वासों के बीच उम्मीद की अंतिम किरण है। इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत हैकृपरिवार को बचाने की नहीं, परिवार के भीतर मानवीय मूल्यों को बचाने की। यही मानवता का भविष्य सुरक्षित करेगा और यही अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का वास्तविक संदेश भी है।

-ललित गर्ग

अपराधियों के बेखौफ होते कदम और कानून व्यवस्था की चुनौती के बीच घिरता सूरत

गुजरात लंबे समय से देश के सबसे विकसित और सुरक्षित राज्यों में गिना जाता रहा है। उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के कारण इस राज्य की पहचान एक मजबूत आर्थिक केंद्र के रूप में बनी है। खासतौर पर सूरत को देश की डायमंड और टेक्सटाइल राजधानी कहा जाता है, जहां करोड़ों रुपए का कारोबार प्रतिदिन होता है। लेकिन अब यही सूरत बढ़ते अपराधों के कारण चिंता का विषय बनता जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ने जिस तरह गुजरात में अपराधों की बढ़ती संख्या को सामने रखा है, उसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपराधियों में पुलिस का डर कम होता दिखाई दे रहा है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में वर्ष 2024 के दौरान 6.15 लाख से अधिक अपराध दर्ज किए गए। यह संख्या पिछले दो वर्षों की तुलना में करीब 18 प्रतिशत अधिक है। राज्य में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब और ड्रग्स से जुड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। कुल अपराधों में लगभग 58 प्रतिशत मामले शराब और नशे से संबंधित हैं। यह स्थिति बताती है कि प्रतिबंध होने के बाद भी अवैध कारोबार खुलेआम जारी है और अपराधी नेटवर्क मजबूत होता जा रहा है।

राज्य में हिंसक अपराधों की बढ़ती संख्या सबसे अधिक चिंता पैदा करती है। हत्या, हत्या की कोशिश, मारपीट और गंभीर हमलों जैसे मामलों में एक वर्ष के भीतर 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2024 में गुजरात में 999 लोगों की हत्या हुई। यह केवल आंकड़ा नहीं बल्कि कानून व्यवस्था के कमजोर होते ढांचे का संकेत है। यदि किसी राज्य में अपराधी खुलेआम हत्या करने से नहीं डर रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि अपराधियों के मन से कानून का भय कम हो चुका है।

सूरत की स्थिति इस संदर्भ में और भी गंभीर दिखाई देती है। देश के बड़े शहरों में अपराध के मामलों में सूरत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। शहर में लगभग 63 हजार अपराध दर्ज हुए हैं। हत्या, लूट, हमला, चोरी, दुष्कर्म और अवैध गतिविधियों के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। पांडेसरा, उधना और लिम्बायत जैसे क्षेत्रों में हर महीने हत्या और हमले की घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं। स्थानीय लोगों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। कई मामलों में अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इससे आम नागरिकों का भरोसा कमजोर पड़ता है।

सूरत केवल एक सामान्य शहर नहीं है। यह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला औद्योगिक केंद्र है। यहां लाखों मजदूर और व्यापारी काम करते हैं। डायमंड उद्योग और टेक्सटाइल कारोबार से जुड़े करोड़ों रुपए हर दिन बाजार में घूमते हैं। ऐसे शहर में यदि अपराध बढ़ते हैं तो उसका असर सीधे व्यापारिक माहौल पर पड़ता है। निवेशक और व्यापारी सबसे पहले सुरक्षा और स्थिरता देखते हैं। यदि शहर में लगातार हत्या, हमला और गैंग गतिविधियां बढ़ेंगी तो इसका प्रभाव उद्योग और रोजगार पर भी पड़ेगा।

शहर में अपराध बढ़ने के पीछे कई कारण दिखाई देते हैं। तेजी से बढ़ती आबादी, बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या, बेरोजगारी, नशे का फैलता कारोबार और स्थानीय स्तर पर सक्रिय असामाजिक तत्व अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। कई क्षेत्रों में अवैध शराब और ड्रग्स का नेटवर्क युवाओं को अपराध की ओर धकेल रहा है। पुलिस कार्रवाई होने के बावजूद अपराधी गिरोह दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। इससे यह धारणा बनती है कि अपराधियों के खिलाफ कठोर और लगातार कार्रवाई की कमी है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई है। महिलाओं के खिलाफ हजारों मामले दर्ज हुए, लेकिन बहुत कम मामलों में अंतिम फैसला आया। जब अपराधियों को सजा मिलने में लंबा

समय लगता है तो अपराध का डर कम हो जाता है। यही कारण है कि कई अपराधी कानून की कमजोर प्रक्रिया का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। महिलाओं की सुरक्षा किसी भी समाज की सभ्यता का पैमाना होती है। यदि महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो विकास के सारे दावे कमजोर पड़ जाएंगे।

साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंक फ्रॉड, फर्जी लिंक और डिजिटल ठगी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अपराधी अब तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने तकनीकी संसाधनों और विशेषज्ञों की कमी भी चुनौती बनी हुई है। आने वाले समय में साइबर अपराध कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं।

राज्य में चोरी और लूट के मामलों ने भी चिंता बढ़ाई है। पिछले 12 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए का माल चोरी हुआ लेकिन उसका केवल एक चौथाई हिस्सा ही बरामद हो सका। यह स्थिति पुलिस जांच और रिकवरी सिस्टम की कमजोरी को दर्शाती है। जब चोरी का माल वापस नहीं मिलता तो पीड़ित व्यक्ति का विश्वास टूटता है। अपराधियों को भी लगता है कि वे आसानी से बच सकते हैं।

आत्महत्या के आंकड़े भी समाज की गंभीर स्थिति को उजागर करते हैं। बेरोजगारी, करियर का दबाव, पारिवारिक समस्याएं और बीमारी के कारण हजारों लोगों ने आत्महत्या की। यह केवल मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दबाव का संकेत भी है। जब युवा रोजगार और भविष्य को लेकर निराश होते हैं तो समाज में अस्थिरता बढ़ती है। ऐसी परिस्थितियों में अपराध का वातावरण भी मजबूत होता है।

सूरत जैसे शहर में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों के बीच यह भावना बननी चाहिए कि कानून सबसे ऊपर है और अपराध करने वालों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए पुलिस को अधिक सक्रिय, आधुनिक और सख्त बनना होगा। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त, सीसीटीवी निगरानी, नशे के कारोबार पर कठोर कार्रवाई और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर विशेष नजर रखने की जरूरत है। केवल अपराध दर्ज करना पर्याप्त नहीं है बल्कि अपराध रोकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाना भी आवश्यक है। कई बार लोग डर या अविश्वास के कारण शिकायत दर्ज नहीं कराते। यदि स्थानीय पुलिस जनता से संवाद बढ़ाए और त्वरित कार्रवाई करे तो अपराध पर नियंत्रण संभव है। मोहल्ला स्तर पर निगरानी समितियां, व्यापारिक संगठनों के साथ समन्वय और युवाओं के लिए जागरूकता अभियान भी प्रभावी साबित हो सकते हैं।

राज्य सरकार को भी यह समझना होगा कि केवल विकास परियोजनाएं और बड़े निवेश ही पर्याप्त नहीं हैं। यदि कानून व्यवस्था कमजोर होगी तो विकास की गति भी प्रभावित होगी। सुरक्षित वातावरण किसी भी विकसित समाज की पहली शर्त होता है। गुजरात की पहचान उद्योग और शांति से रही है। इसलिए अपराध की बढ़ती घटनाओं को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सूरत में हर महीने होने वाली हत्याएं और हमले इस बात का संकेत हैं कि अपराधियों में पुलिस का डर कम हो रहा है। यह स्थिति किसी भी शहर के लिए खतरनाक होती है। पुलिस का खौफ अपराधियों के मन में होना जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ केवल सख्ती नहीं बल्कि प्रभावी और निष्पक्ष कानून व्यवस्था भी है। अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि उसे तुरंत कार्रवाई और सजा का डर होगा तो अपराध स्वत: कम होंगे।

आज जरूरत केवल आंकड़ों पर चर्चा करने की नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की है। गुजरात और विशेष रूप से सूरत को सुरक्षित बनाए रखना सरकार, पुलिस प्रशासन और समाज तीनों की साझा जिम्मेदारी है। यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो अपराध का यह बढ़ता ग्राफ आने वाले वर्षों में और बड़ी चुनौती बन सकता है।

- कांतिलाल मांडोत

मॉडर्न ज़माने में ऊंचा रुतबा पाना है अपराध का कारण

-संजय गोस्वामी

आज का समाज भौतिकवादी दौड़ में शामिल होकर मॉडर्न बनना चाहता है और इस मॉडर्न जमाने में ऊंचा रुतबा पाना चाहता है। इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। इस ज़माने में, कोई भी इंसान ईमानदारी से दो वक्त की रोटी कमाए बिना इज्जत की ज़िंदगी नहीं जी सकता। इसलिए, ऊंचा रुतबा पाने के लिए लोग दूसरे गैर-कानूनी धंधे करने लगते हैं और ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत क्राइम को जन्म देती है। साफ़ है कि क्राइम से इंसान का सामाजिक और आर्थिक नुकसान होता है। क्राइम से उसका परिवार और समाज टूटता है। आर्थिक गिरावट आती है। उसका कल्चरल और नैतिक पतन होता है। इसलिए, क्राइम के खिलाफ़ आवाज़ उठाना और अपराधियों को सुधारने की कोशिश करना ज़रूरी है।यह निर्विवाद सर्व स्वीकार्य तथ्य है कि अपराध से कानून की अवहेलना और अपराधों में वृद्धि होती है। आज जो अपराध है वह कल परिवर्तित सामाजिक परिस्थिति में अपराध नहीं रह सकता है और जो आज अपराध नहीं है वह कल अपराध के स्वरूप का मानक बन सकता है। अपराध को परिभाषित करने के सम्बन्ध में दो विचार धारायें हैं, एक को शास्त्रीय, सनातन तथा मिश्रयवादी और द्वितीय को नवउन्मेषकारी, सांदर्भिक तथा परिमार्जनवादी कहना संगत होगा। प्रथम कानून की सीमाओं में ही संकुचित रहती है, दूसरी सामाजिक जीवन के व्यापक परिवेश में विचरण निन्दनीय अथवा अनौचित्यपूर्ण क्यों न हो, अपराध तब तक नहीं माना जाता जब तक कि उसे आपराधिक कानून के द्वारा निषिद्ध नहीं घोषित किया गया है। डोनाल्ड आर. टैफ्ट के शब्दों में, "वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानूनतः दण्डनीय है।" गिलिन एवं गिलिन के अनुसार कानूनी दृष्टिकोण से अपराध किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्य है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी परिभाषाओं का विश्लेषण किया जाय तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अपराध जानबूझकर किया गया व्यवहार है। आपराधिक परिवारों के पुरुष एवं महिलाओं का विभिन्न प्रकार के करती हैं प्रथम को परम्परागत तथा द्वितीय को आधुनिकतम अपराधों में संलिप्तता का क्या उद्देश्य रहा है, जब इन कहना भी प्रथम की मर्यादा एवं उपयुक्तता का हनन किये बिना समीचीन होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपराध कानून का उल्लंघन है। यह वह व्यवहार है जिसे आपराधिक संहिता में निषिद्ध तथा दण्डनीय घोषित किया गया है। विवेचनागत अध्ययन की सुगमता हेतु अपराध की अन्य वैज्ञानिक परिभाषाएँ जो आपराधिक परिवारों से प्राप्त आँक?ों की मदद से निष्कर्ष निकाला गया तो 53.01 प्रतिशत अपराधियों ने अपराध करने की सहमति स्वीकार किया एवम् 46.99 प्रतिशत का कहना है कि पुलिस ने अनावश्यक रूप से वैसे ही झूठे, फर्जी केस दर्ज करके अपनी कार्यवाही पूरी की। 1. अक्सर गरीबी रेखा के नीचे के परिवार कहीं न कहीं न कहीं, वे किसी न किसी रूप में अपराध में शामिल हो जाते हैं, जैसा कि लगभग 53 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना। 2. कुछ मामलों में, पुरुष और महिलाएं, विशेष रूप से पुरुष, इन परिवारों से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर होते हैं, और पुलिस इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करती है। 3. आपराधिक परिवारों के पुरुष अक्सर शराब पीते हैं, और इसके प्रभाव में, वे सही और गलत की अपनी समझ खो देते हैं, अपराध की ओर प्रेरित होते हैं, और अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। वे यह समझ नहीं पाते कि वे क्या कर रहे हैं या यह सही है या गलत, और वे अपराधों में शामिल हो जाते हैं। 4. उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। अपराध एक सार्वभौमिक घटना है जो सीधे मानव व्यवहार से संबंधित है। इस मानव व्यवहार के क्या कारण हैं? दूसरे शब्दों में, अपराध के कारण क्या हैं? वर्ट अपराध के कारणों की एक लंबी सूची प्रस्तुत करता है, जो वास्तव में पूरी तरह से सटीक है। अधूरे मनोरंजन के साधन, दोषपूर्ण ग्रंथियाँ, शारीरिक हीनता, भावनात्मक असंतुलन, अस्थायी पागलपन, शिक्षा का अभाव, व्यक्तिवादी अराजकता, सामाजिक अपूर्णता, अवैध धन अर्जन, मद्यपान आदि। अपराधों में संलिप्तता के सिद्धांत एवं कारण-साधारणतया कुछ परिस्थितियाँ एवं कुछ कारण आपराधिक प्रवृत्तियों के जागृत होने, प्रोत्साहन एवं अपराधों में संलिप्तता के लिए अवश्य ही उत्तरदायी होते हैं। 1. साधारणतया अपराध का संबंध मानव व्यवहार से होता है। अपराधों में संलिप्त होने से उनके परिवार के सदस्य दु:खी होते हैं, परंतु अपराध में समस्त मानवीय व्यवहार दु:खी होते हैं। अपराध सदैव विनाशकारी होता है, वह समाज के दायरे में नहीं आता, चाहे वह किसी भी कारण से किया गया हो। स्पष्ट है कि अपराध की बढ़ती हुई बुरी प्रवृत्ति व्यक्ति, समुदाय एवं समाज के लिए हानिकारक है। विभिन्न विद्वानों ने अपराधियों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है, जैसे लोम्ब्रोसो ने जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, कामुक अपराधी एवं आकस्मिक अपराधी। गैरिफालो ने भी अपराधियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: सनकी अपराधी, हिंसक अपराधी, दया एवं ईमानदारी से रहित अपराधी एवं लम्पट अपराधी। सदरलैंड ने अपराधियों को साधारण निम्नवर्गीय अपराधी एवं सफेदपोश अपराधी में वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अपराधियों को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। अपराधी परिवारों के पुरुष और महिलाएं मानवीय व्यवहार को ही अपराध मानते हैं, क्योंकि सामान्य व्यवहार पैटर्न के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य अपराध है। 2. इरादे और व्यवहार के बीच संबंध है, लेकिन अपराध होने के लिए यह आवश्यक है कि आपराधिक इरादे एक साथ बाहरी रूप से व्यक्त हों। 3. अपराध व्यक्तिगत विघटन का कारण बनता है। इस संदर्भ में अपराध विज्ञानी ओटो रांके का कहना है कि विघटित व्यक्तित्व अपराध का कारण है। प्रो. मार्क्स और एंगेल्स का कहना है कि परिस्थितियां अपराध के लिए जमीन तैयार करती हैं और अपराध आर्थिक स्थितियों की उपज है और आर्थिक स्थितियां समाज की उपज हैं। इसलिए अपराध को भी समाज के उत्पाद के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अपराध का मुख्य कारण पर्यावरण है। इसमें पैसे की कमी शामिल है। व्यापार बुरी तरह प्रभावित होता है। उजड़े हुए घर, गंदी बस्तियां, बुरी संगत, अस्वस्थ मनोरंजन, गरीबी, पारिवारिक माहौल, अशांत उपसंस्कृतियां, झुग्गी-झोपड़ियां, छात्रावास और कॉलेज की संस्कृति, जुनून आदि और साथी समूहों की भूमिका आदि से आश्रित प्रभावित होते हैं और समाज प्रभावित होता है। अपराध के अन्य कारण- 1. अज्ञानता - कुछ लोगों में गलत धारणा है कि वे सब जानते हैं कि अपराध एक सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक बुराई है जो हत्या, मकानों की बिक्री और दिवालियापन का कारण बनती है। लोग अपराधी बन जाते हैं, उनकी शादियां बर्बाद हो जाती हैं, हत्या और आत्महत्याएं होती हैं और यहां तक कि दुख और गरीबी भी पनपती है। जुआ, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, अपहरण, चोरी, डकैती, मारपीट आदि भी अपराध का परिणाम हैं। नैतिक पतन, भ्रष्टाचार और कानून की अवहेलना भी इसके दुष्परिणाम हैं। व्यक्तिगत टूटन, पार्लर टूटन और सामाजिक टूटन भी इसका परिणाम है 2. तनाव, पारिवारिक क्लेश एवं निराशा - जब परिवार में धन के अभाव के कारण बीमारी एवं दैनिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं, तो मानसिक एवं पारिवारिक क्लेश प्रारंभ हो जाता है। इससे तनाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर होता है। 3. संगति एवं मित्र मंडली - अपने सगे-संबंधियों एवं मित्रों के साथ रहकर भी अनेक अपराध करने के कारण व्यक्ति को अपने जीवन में निम्न सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के ये दोष हैं - 1. इससे कानून की अवहेलना एवं व्यभिचार बढ़ता है। 2. इसका प्रभाव व्यक्ति के परिवार पर पड़ता है। 3. इसका प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है और उसमें भय फैल जाता है। 4. बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। भय के कारण उनका बाहर निकलना या बैठना दूभर हो जाता है।

समय के साथ भारत ने आईएलओ के 47 समझौतों और एक प्रोटोकॉल को किया मंजूर

नई दिल्ली। एजेंसी। कर्नाटक ने 2023 में कारखाना श्रमिकों के लिए 12 घंटे की शिफ्ट की अनुमति दी तब ट्रेड यूनियनों ने जिनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में तर्क दिया कि यह बदलाव भारत की उस प्रतिबद्धता का उल्लंघन है जो उसने आईएलओ के काम के घंटे समझौते 1919 के तहत जताई थी। इसके तहत श्रमिकों को अधिकतम प्रतिदिन आठ घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे काम करने का प्रावधान है। इस प्रकार जो बहस घरेलू स्तर पर उत्पादकता, वेतन और श्रमिकों की पसंद के बीच संतुलन पर होनी चाहिए थी वह एक अंतरराष्ट्रीय मामले में बदल गई।

यह अपनी तरह की कोई इकलौती घटना नहीं है। यह एक सदी पहले लिए गए फैसला का परिणाम है। भारत ने काम के घंटों को लेकर खुद को आईएलओ के नियमों के सबसे हस्तक्षेपकारी हिस्से से आबद्ध कर लिया था। भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है और वह 1922 से ही उसकी संचालन संस्था का स्थायी सदस्य रहा है। समय के साथ हमने आईएलओ के 47 समझौतों और एक प्रोटोकॉल को मंजूर किया। इनमें से 39 अभी तक जारी हैं। यह समस्या उतनी गंभीर नहीं होती यदि यह समझौता सार्वभौमिक सहमति को दर्शाता। आईएलओ के 187 सदस्य देशों में से केवल 52 ने सी001 को अनुमोदित किया है और केवल 30 ने इसके साथ जुड़े काम के घंटे समझौते, 1930 (सी030) को अनुमोदित किया है। प्रमुख विनिर्माण शक्तियों जैसे अमेरिका, जर्मनी, चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम ने सी001 को अनुमोदित नहीं किया है। वहीं न्यूजीलैंड ने विपरीत रास्ता अपनाया। कई दशकों तक इस संधि का पालन करने के बाद उसने इसे नामंजूर कर दिया और अब कार्य समय को राष्ट्रीय कानून और सामूहिक सौदेबाजी के जरिए नियंत्रित करता है। भारत एक बड़ा, औद्योगीकरण की प्रक्रिया में शामिल श्रम-संपन्न अर्थतंत्र है जिसने स्वयं को 1919 के युग की कार्य समय संधि के अधीन कर लिया है, जिसे इसके अधिकांश निर्यात प्रतिस्पर्धियों ने टाल दिया है। केवल कार्य समय ही नहीं, बल्कि भारत ने अपनी 47 अनुमोदित संधियों के साथ अन्य बड़े विनिर्माण देशों की तुलना में कहीं ज्यादा सक्रियता दिखाई है। जैसे अमेरिका ने 14 और चीन ने 28 को ही किया है। भारत के संविधान में श्रम को समवर्ती सूची में रखा गया है। आईएलओ की संधियां केवल सिफारिशें नहीं हैं। आईएलओ का प्रत्यक्ष शिकायत तंत्र और त्रिपक्षीय स्वरूप उसको संयुक्त राष्ट्र की अन्य संस्थाओं से अलग बनाता है। किसी भी नियोक्ता या श्रमिक संगठन, किसी अन्य सदस्य राज्य, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के किसी प्रतिनिधि, या आईएलओ की अपनी संचालन संस्था द्वारा शिकायत या प्रस्तुति दर्ज की जा सकती है। गंभीर और लगातार मामलों में यह एक आयोगीय जांच का रूप ले सकता है। यदि कोई सरकार आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सहमत नहीं होती, तो आईएलओ की संचालन संस्था अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को 'ऐसी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है जिसे वह उचित और आवश्यक समझे।' आईएलओ के फैसले व्यापार और सहायता की शर्तों में भी शामिल होते हैं। विशेषकर यूरोपीय संघ के साथ और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं।

सरकार अब ई25 फ्यूल पर दे रही जोर, नियमों में होंगे बड़े बदलाव

नई दिल्ली। एजेंसी। सरकार गाड़ियों के लिए बनने वाले नए कैफे-3 नियमों में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इन नियमों में ई20 की जगह ई25 फ्यूल को आधार बनाया जा सकता है। मतलब आने वाले कुछ सालों में देश की ज्यादातर गाड़ियां ई25 पेट्रोल से चलेंगी, इसलिए नए नियम भी उसी हिसाब से बनाए जाएं। कैसे नियम यह तय करते हैं कि किसी ऑटो कंपनी की गाड़ियों से कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो सकता है। ये नियम अप्रैल 2027 से लागू होने वाले हैं और अगले पांच साल तक प्रभावी रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अभी देश में ई20 पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है यानी पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाया जाता है। अब सरकार ई25 अपनाना चाहती है, जिसमें एथेनॉल 25 फीसदी होगा। एथेनॉल गन्ने और अनाज से भारत में ही बनाया जाता है। सरकार का मानना है कि अगर पेट्रोल में ज्यादा एथेनॉल मिलाया जाएगा तो कच्चे तेल के आयात पर खर्च कम होगा और विदेशी तेल पर निर्भरता भी घटेगी। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने से पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर असर पड़ा। इसके बाद भारत सरकार के अलग-अलग विभागों ने ऑटो कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की कि ई20 से आगे बढ़कर जल्द ई25 पर कैसे जाया जाए। सरकार को लगता है कि ज्यादा एथेनॉल इस्तेमाल करने से तेल आयात का बोझ कम किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) अब कैफे-3 के ड्राफ्ट में बदलाव कर सकता है। अभी तक जो टेस्ट और गणना ई20 फ्यूल के आधार पर हो रही थी, उसे अब ई25 के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि जब आने वाले सालों में गाड़ियां ई25 पर चलेंगी, तो फिर पुराने ई20 फॉर्मूले पर नियम बनाने का कोई मतलब नहीं है। ऑटो कंपनियां काफी समय से सरकार से कह रही हैं कि कैफे-3 नियमों को जल्द अंतिम रूप दिया जाए। कंपनियों का कहना है कि नए नियम साफ होने के बाद ही वे नई गाड़ियों, इंजन तकनीक और निवेश की योजना बना पाएंगी। गाड़ियों की टेस्टिंग में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल बहुत अहम होता है क्योंकि उसके आधार पर कार्बन उत्सर्जन मापा जाता है। एथेनॉल में सामान्य पेट्रोल के मुकाबले कार्बन कम होता है। इसलिए अगर पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ती है, तो गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी बदल जाता है। यही वजह है कि सरकार अब नए कैफे-3 नियमों में ई25 फ्यूल को आधार बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

रुपया बढ़त पर बंद

मुम्बई। एजेंसी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज भारतीय रुपय तीन पैसे की बढ़त के साथ ही 95.72 पर बंद हुआ। इससे पहले आज सुबह भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोरी के साथ खुला और अपने ऑल-टाइम लो (सर्वकालिक निचले स्तर) पर पहुंच गया। रुपया सुबह डॉलर के मुकाबले 20 पैसे टूटकर 95.86 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर खुला। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया 95.74 पर खुला और बाद में और गिरकर 95.86 के स्तर तक आ गया। वहीं बुधवार को रुपया 95.75 पर बंद हुआ था। मजबूत अमेरिकी डॉलर और ऊंची ऊर्जा कीमतों के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच घरेलू मुद्रा में यह गिरावट आई।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुम्बई। एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में ये तेजी दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी रहने से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 789.74 अंक बढ़कर 75398.72 के स्तर पर बंद हुआ जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 277 अंक उछलकर 23689.60 के स्तर पर बंद हुआ। आज लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी रही। कारोबार के दौरान दूरसंचार, फार्मा और निजी बैंकिंग शेयरों में में उछाल आया। सेंसेक्स शेयरों में, भारती एयरटेल सबसे बड़ा लाभ कमाने वाला शेयर रहा, जिसके शेयरों में 5 फीसदी से अधिक की तेजी आई। वहीं एटरनल के शेयरों में 3.32 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 2.67 फीसदी की बढ़त हुई, जिससे सेंसेक्स में सबसे अधिक लाभ इन्हीं शेयरों के कारण हुआ। . अदानी पोर्ट्स, सन फार्मास्युटिकल्स, बजाज

फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर भी उछले। दूसरी ओर इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर नीचे आये। इससे पहले आज सुबह घरेलू शेयर बाजार तेजी के साथ खुले। सुबह बाजार खुलते ही बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा ऊपर आया जबकि निफ्टी 23,500 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। सुबह सेंसेक्स 338 अंक बढ़कर 74,947.12 पर कारोबार कर रहा था जबकि निफ्टी 118 अंक उछलकर 23,530 पर पहुंच गया। वहीं आज एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई इंडेक्स करीब 0.47 फीसदी उछला जबकि हांगकांग का हैंग सेंग लगभग 1 फीसदी बढ़ा। चीन का सीएसआई 300 इंडेक्स करीब 0.52 फीसदी गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। दूसरी ओर अमेरिकी बाजारों में टेक शेयरों में उछाल आया। एसएंडपी 500 इंडेक्स करीब 0.58 फीसदी और नैस्डैक 1.2 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए।

पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी- प्रमुख शहरों में जानें ताजा भाव

नई दिल्ली। एजेंसी। 14 मई 2026 को देशभर में पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच लोगों की नजरें ईंधन के दामों पर टिकी हुई हैं। हालांकि, दिल्ली और मुंबई सहित कई बड़े शहरों में आज कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन कुछ अन्य शहरों में हल्की बढ़ोतरी या कमी दर्ज की गई है। भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, इसके बाद वैश्विक बाजार में कीमतों का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ता है। मध्य-पूर्व में जारी तनाव के कारण दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य पर खतरा बना हुआ है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में और उछाल आने की आशंका है। इसकारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से बिना जरूरत वाहन का उपयोग कम करने, ईंधन की बर्बादी रोकने और ऊर्जा बचाने वाली आदतों को अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने गैर-जरूरी सोने की खरीदारी टालने और खाद्य तेल का सीमित उपयोग करने की सलाह भी दी। आंकड़ों के अनुसार, नई दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर रहा, जबकि मुंबई में पेट्रोल 103.54 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर बिका। कोलकाता में पेट्रोल 105.45 रुपये और चेन्नई में 100.80 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया। केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल ईंधन राशनिंग या देशभर में कीमतों में बड़े बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकारी सूत्र लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और सप्लाई चेन को सामान्य बनाए रखने की कोशिश जारी है।

सरकार ने बढ़ाया धान का एमएसपी

नई दिल्ली। एजेंसी। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। अब सामान्य धान का एमएसपी 2,441 रुपये प्रति क्विंटल होगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ए-ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। नई दरें खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के दौरान लागू होंगी, जिसकी शुरुआत सितंबर-अक्टूबर से होगी।

सरकार का कहना है कि किसानों को उनकी लागत का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान का एमएसपी उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक रखा गया है, ताकि किसानों को बेहतर आमदनी मिल सके और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिले। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद किसानों को अनुमानित रूप से 2.60 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने आगामी सीजन में करीब 824.41 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है।

क्या है एमएसपी?

धान देश की प्रमुख खरीफ फसलों में शामिल है और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य हर वर्ष केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। एमएसपी वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है, ताकि बाजार में कीमतें गिरने की स्थिति में किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को राहत मिलेगी, हालांकि बढ़ती उत्पादन लागत और महंगाई को देखते हुए कुछ किसान संगठनों ने अधिक वृद्धि की मांग भी की थी।

मेष- आज बिजनेस में कभी फायदा तो कभी चुनौती वाला माहौल रह सकता है, लेकिन आपकी समझदारी हर स्थिति को आपके पक्ष में मोड़ सकती है। योजनाओं में किया गया छोटा बदलाव बड़ा लाभ दिला सकता है। लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए खर्च बढ़ सकता है। परिवार की सलाह आज आपके लिए किसी गुप्त मंत्र से कम नहीं होगी। पुराने वादों को निभाने का समय आ चुका है और कामों को टालना नुकसान दे सकता है।

वृषभ- आज पैसों के मामलों में सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। लंबे समय से रुका काम आखिरकार पूरा होने की ओर बढ़ सकता है। ऑफिस में आपकी सकारात्मक सोच बॉस को प्रभावित करेगी और प्रमोशन की चर्चा भी तेज हो सकती है। अचानक वाहन पर खर्च बढ़ने से बजट थोड़ा हिल सकता है। संतान की संगति पर नजर रखना जरूरी रहेगा।

मिथुन- आज किस्मत आपके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है। यात्रा या घूमने के दौरान मिली जानकारी भविष्य में बड़ा फायदा दे सकती है। कुछ खास लोगों से मुलाकात बिजनेस में नई उड़ान दे सकती है। शेयर मार्केट में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है, इसलिए एक्सपर्ट की सलाह जरूरी होगी। नई नौकरी का ऑफर आकर्षित करेगा, लेकिन फिलहाल पुरानी जगह टिके रहना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

कर्क- आज धन और सफलता दोनों आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। माता-पिता का आशीर्वाद आपके रुके हुए कामों को गति देगा। जीवनसाथी के लिए नया बिजनेस शुरू करने का विचार उत्साह बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानी के लिए जांच करवानी पड़ सकती है। ऑफिस में बॉस के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी छवि बेहतर बनेगी।

सिंह- आज खर्चों पर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी रहेगा, वरना बजट गड़बड़ा सकता है। विद्यार्थियों को मानसिक दबाव से राहत मिलने के संकेत हैं। आपकी लापरवाही परिवार के लोगों को परेशान कर सकती है, इसलिए खुद में बदलाव लाना जरूरी होगा। पुराने दोस्त से मुलाकात दिल को खुश कर सकती है, बस बीती बातों को दोबारा न छेड़ें। रुका हुआ उधार वापस मिलने की संभावना भी बन रही है।

कन्या- आज चुनौतियाँ थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों और जीवनसाथी का साथ आपको संभाले रखेगा। मनचाहा काम न मिलने से निराशा हो सकती है। जीवनसाथी को नई नौकरी का ऑफर मिलने से घर में उत्साह का माहौल बनेगा। छोटे बच्चों के साथ बिताया गया समय आपकी टेंशन कम करेगा और चेहरे पर मुस्कान लौटाएगा।

तुला- आज समाज सेवा और अच्छे कामों से आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है। दान-पुण्य के कार्यों में हिस्सा लेने से मन को सुकून मिलेगा। जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन प्यार भरी बातचीत से खत्म हो सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को बड़ी खबर मिल सकती है। परिवार की निजी बातें बाहरी लोगों से साझा करने से बचें। संतान के साथ घूमने का प्लान दिन को खास बना देगा।

वृश्चिक- आज कमाई के नए रास्ते खुलते दिखाई देंगे। पुराने निवेश से शानदार लाभ मिलने की संभावना है। कोई नई साइड इनकम शुरू होने से खुशी दोगुनी हो सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने का सपना साकार होने की दिशा में कदम बढ़ सकता है। भाइयों की सलाह आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई फायदा भी मिल सकता है।

धनु- आज का दिन पहले से बेहतर और राहत भरा रहेगा। अपनी कमियों को पहचानकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन सच आपके साथ रहेगा। वाहन पर अचानक खर्च बढ़ सकता है। पारिवारिक मामलों में मां की सलाह मन को सुकून देगी। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें।

मकर- आज खुशियों और जिम्मेदारियों का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न कर सकती है। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरकर गर्व महसूस कराएगी। जिम्मेदारियों में लापरवाही करने पर पिताजी नाराज हो सकते हैं। बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े लोगों को प्रमोशन मिलने के योग हैं। नई नौकरी के लिए आवेदन करना भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है।

कुंभ- आज चुनौतियाँ आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती हैं। कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना ही आपकी जीत का रास्ता बनेगा। संतान पढ़ाई में लापरवाही कर सकती है, इसलिए उनकी भावनाओं और परेशानियों को समझने की जरूरत होगी। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम की तैयारी माहौल को खुशनुमा बना सकती है। अपने काम खुद करने की आदत ही आपको सफलता दिलाएगी।

मीन- आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और बॉस आपके काम से बेहद प्रभावित रहेंगे। आपके सुझावों को भी महत्व मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। पड़ोस और समाज में आपकी छवि मजबूत होगी। घूमने-फिरने की योजना बन सकती है, लेकिन सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। परिवार में चल रही नाराजगी को प्यार और बातचीत से खत्म करने में आप सफल रहेंगे।

शब्दजाल - 8259

यु	क	दो	अ	ल्जी	रि	या	तू	ग	इ	क
ज	पा	ल	प	ह	भा	पू	ना	ट	की	को
अं	इ	कि	म	सं	र	ल	श	र	ला	ल
क	कु	दा	स्ता	धा	त	क	फ	लो	श	या
क	मो	श	ब्न	न	क	ट	री	ग	रि	ता
द	र	ल	प	व	जि	र्त	ऐ	जी	प	रु
ती	क्को	ल	श	इ	प	म	इ	कौ	ला	इ
क	इं	डो	ने	शि	या	ना	प्प	न	श	रा
क	स	बा	तें	व	न	ज	द	शा	जू	न
द	र	ल	प	व	जी	र्त	ऐ	वें	प	रु
बां	ग	ला	दे	श	नी	हो	जा	एं	प	क

शब्द जाल में उन 10 देशों के नाम हैं जहां मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है. नाम ऊपर से नीचे एवं तिरछे भी हैं.

पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, टर्की, इरान, नाईजीरिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इजिप्ट.

शब्दजाल - 8258 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

फिल्म वर्ग पहेली- 7203

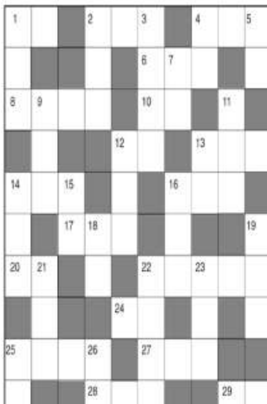

ऊपर से नीचे:-

१. सनी देओल, मीनाक्षी की फिल्म-३
२. संजयदत्त, जूही चावला की 'आलारे चउस अला' गीत वाली फिल्म-३
३. आशुतोष गोवारीकर की बहुचर्चित फिल्म 'लगान' के संगीतकार कौन है-४
४. जीतेंद्र, रीना रायचौधरी की फिल्म-२
५. संजय खान, मुमताज की 'ऐ हसीनों नाजनीनों' गीत वाली फिल्म-२
७. 'दिल मेरा अकेला' गीत वाली आमिर, फैजल, ट्विंकल की फिल्म-२
९. फिल्म 'मन की आँखें' की नायिका थी-३
११. शाहरूख, माधुरी की 'बड़ी मुश्किल है' गीत वाली फिल्म-३
१२. 'गोरिया रे गोरिया रे' गीत वाली जैकी, जूही, अमृता की फिल्म-३
१३. राजकपूर, नर्गिस की 'काहे कोयल शोर मचाये' गीत वाली फिल्म-२
१४. 'तन्हा तन्हा दिल धड़के' गीत वाली अक्षय कुमार, सोनाली की फिल्म-३
१५. 'अभिमान' में अमिताभ की नायिका-२
१६. राज बब्बर, रेखा की 'रुसवानी ना जाइये' गीत वाली फिल्म-३
१८. राजेश खन्ना, बबीता की फिल्म-२
१९. 'बेचारा दिल क्या करे' गीतवाली फिल्म-३
२१. धर्मेन्द्र, राजेश खन्ना, वहीदा की फिल्म-३
२२. 'कोयल बोली दुनिया डोली' गीत वाली फिल्म-४
२३. अमिताभ, संजीव, शर्मिला की फिल्म-३
२५. 'मैं तो हूँ पागल मुंडा' गीत वाली फिल्म-२
२६. संजयदत्त, सलमान, रवीना की फिल्म-२

बायें से दायें:-

१. मनोज बाजपेयी, अरशद, तब्बू की 'बाब मेरी वे' गीत वाली फिल्म-२
२. 'जीवन से भरी' गीत वाली राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर की फिल्म-३
४. सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी की 'हैलो हैलो बोलके' गीत वाली फिल्म-३
६. 'ऐसा मिलन कल हो ना' गीत वाली सैफअली, काजोल की फिल्म-३
८. कुमार गौरव, विजयेता की 'याद आ रहो है' गीत वाली फिल्म-२,२
१०. 'आँखें' तो नायिका कौन थी-२
१२. 'दिल में छुपाके प्यार' गीत वाली दिलीपकुमार, निम्मी की फिल्म-२
१३. दिलीपकुमार, मीना की 'राधा ना बोले ना' गीत वाली फिल्म-३
१४. 'किसी से तुम' गीत वाली लारा दत्ता, प्रियंका, अक्षय की फिल्म-३
१६. राजकपूर, राजेंद्र, वैजयंती की 'मैं क्या करूंगा' गीत वाली फिल्म-३
१७. 'छूकर मेरे मन को' गीत वाली अमिताभ, अमजद, नीतू की फिल्म-३
२०. फिल्म 'कहानी किस्मत की' में धर्मेंद्र के साथ नायिका कौन थी-२
२२. नसीर, आमिर, सोनाली, उपासना की 'वो हाल दिल' गीत वाली फिल्म-५
२४. 'दिल में जागी धड़कन' गीत वाली सकी अली, गौरी की फिल्म-२
२५. अशोककुमार के गाये बालगीत 'रेलगाड़ी रेलगाड़ी' वाली फिल्म-४
२७. 'घर आजा परदेसी' गीत वाली सनी देओल, अमीषा की फिल्म-३
२८. संजयदत्त, मनीषा की 'कसम से कसम से' गीत वाली फिल्म-३
२९. अक्षय, अभिषेक, रानी, एशा की 'कभी नीम नीम' गीत वाली फिल्म-२

फिल्म वर्ग पहेली- 7202

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

15 मई 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति	लग्नारंभ	समय
सूर्य	मेष में	वृष	05.23 बजे से
चंद्र	मेष में	मिथुन	07.21 बजे से
मंगल	मेष में	कर्क	09.34 बजे से
बुध	वृष में	सिंह	11.51 बजे से
गुरु	मिथुन में	कन्या	14.03 बजे से
शुक्र	मिथुन में	तुला	16.13 बजे से
शनि	मीन में	वृश्चिक	18.28 ब.से
राहु	कुंभ में	धनु	20.44 बजे से
केतु	सिंह में	मकर	22.49 बजे से
राहुकाल 10.30 से 12.00 बजे तक		कुंभ	00.36 बजे से
		मीन	02.08 बजे से
		मेष	03.39 बजे से

शुक्रवार 2026 वर्ष का 135 वा दिन **दिशाशूल** पश्चिम **ऋतु** ग्रीष्म। **विक्रम संवत्** 2083 **शक संवत्** 1948 **मास** ज्येष्ठ (दक्षिण भारत में वैशाख) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** त्रयोदशी 08.32 बजे तदनन्तर चतुर्दशी 05.12 बजे प्रातः को समाप्त। **नक्षत्र** अश्विनी 20.15 बजे को समाप्त। **योग** आयुष्मान 14.21 बजे को समाप्त। **करण** वणिज 08.32 बजे, विष्टि 18.55 बजे तदनन्तर शकुनि 05.12 बजे प्रातः को समाप्त। **चन्द्रायु** 24.5 घण्टे **रवि क्रान्ति** उत्तर 18° 49' **सूर्य** उत्तरायण **कलि अहर्गण** 1872710 **जूलियन दिन** 2461175.5 **कलियुग संवत्** 5128 **कल्पारंभ संवत्** 1972949128 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885128 **वीरनिर्वाण संवत्** 2552 **हिजरी सन्** 1447 **महीना** जिल्काद **तारीख** 27 **विशेष** मासिक शिवरात्रि, विश्व परिवार दिवस।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
चर	05.55 से 07.23	बजे तक	रोग	05.38 से 07.1	बजे तक
लाभ	07.23 से 08.51	बजे तक	काल	07.11 से 08.43	बजे तक
अमृत	08.51 से 10.19	बजे तक	लाभ	08.43 से 10.15	बजे तक
काल	10.19 से 11.47	बजे तक	उद्वेग	10.15 से 11.47	बजे तक
शुभ	11.47 से 01.15	बजे तक	शुभ	11.47 से 01.19	बजे तक
रोग	01.15 से 02.43	बजे तक	अमृत	01.19 से 02.51	बजे तक
उद्वेग	02.43 से 04.10	बजे तक	चर	02.51 से 04.23	बजे तक
चर	04.10 से 05.38	बजे तक	रोग	04.23 से 05.55	बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभाशुभ श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगतः पत्नी की चूड़ियां

बीरवल की बुद्धि की परिक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर अक्सर बेसिर-पैर कि बातें पूछते थे। एक दिन बादशाह ने पूछा- बीरवल ! तुम दिन में अपनी पत्नी का हाथ एक या दो बार तो पकड़ते ही होंगे। बीरवल बोले- हां, जहांपनाह ! क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? यह बात सुनकर बीरबल एक बार तो असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कभी पत्नी के हाथ की चूड़ियों की गिनती नहीं की। थोड़ी देर सोचने का बाद अचानक बीरबल का बुद्धि दौड़ी और वे बोले- हां, मैं इस बात का जवाब दे सकता हूं। इसके पहले मेरी एक बात का जवाब देना होगा। अकबर ने कहा- पूछो-पूछो अपनी बात। बीरबल बोला- जहांपनाह, मैं तो पत्नी के हाथ दिन में एक आध बार ही लगाता हूं। पर आप हर वक्त अपनी मूंछ पर हाथ रखते हो इसलिए पहले आप बताओ की आपकी मूंछ में कितने बाल हैं। अरबर बीरबल की बात सुनकर निरूत्तर हो गए। बीरबल के ठहाके के बीच बात आई-गई हो गई।

सूडोकु नवताल- 7512

★★★★☆ कठिन

					1	4		
	9					5	8	
			7	9				
			2				6	7
4								3
5	8				9			
				8	5			
	7	6					1	
		9	3					

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
■ पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7511 का हल

7	8	9	2	3	1	6	5	4
3	2	4	6	5	9	7	8	1
6	5	1	8	4	7	2	9	3
5	1	7	3	9	8	4	6	2
4	6	8	5	1	2	9	3	7
9	3	2	4	7	6	8	1	5
1	4	6	9	2	3	5	7	8
2	9	3	7	8	5	1	4	6
8	7	5	1	6	4	3	2	9

Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्द पहेली - 8727

बाएँ से दाएँ

1. जी,इच्छा,चित्त-2
2. तन,बदन,देह-3
4. अग्निदग्ध-2
6. रनिवास (उर्दू-3)
7. स्नान करना-3
8. विश्राम-3
9. राजा,सम्राट-3
10. वचन,प्रतिज्ञा-3
11. तरंग,हिलोर-3
13. दौड़ना (अंग्रेजी-2)
14. सही का विलोम-3
15. सद्पुरुष-2
16. पाठ,शिक्षा-3
17. कर्ता,कार्य करने वाला-3
18. इज्जत,मान,सम्मान-3
19. सब कुछ छीन लेना-2
20. भवन,प्रासाद-3
21. वजह-3
23. खेल दिखाने वाला-2
24. पेन,लेखनी-3
25. ठाठ-बाट-2

ऊपर से नीचे

1. राय,वोट,अभिप्राय-2
2. लाज,लज्जा-2
3. 500 कागजों की गड्डी -2
4. दुनिया,जगत-3
5. लेकर आना-2
6. अवैध,नाजायज-3
7. निगाह,दृष्टि-3
8. बैठने की जगह-3
9. आराम,मदद-3
10. कर्म,भाग्य-3
11. लगन,जिद,उत्साह-3
12. दांपत्य संबंध विच्छेद-3
14. जवान,तरुण-3
15. रिक्त जगह पूर्ण करना-3
16. दुर्बल का विलोम-3
17. वजह-3
18. पदचाप, किसी के आने की आवाज-3
19. रनिवास (उर्दू-3)
20. जी,इच्छा,चित्त-2
21. समयगति-2
22. देह,बदन-2

शब्द पहेली -8726 का हल

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

पार्षद पूनम आसटकर ने डिवाइडर निर्माण व विद्युत पोलों की गुणवत्ता पर उठाए गंभीर सवाल

नगर परिषद के उपयंत्री व सीएमओ की भूमिका संदेहास्पद

पद्मेश न्यूज। लांजी। नगर परिषद लांजी में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फि र सवालों का बवंडर खड़ा हो गया है। वार्ड क्रमांक 03 की पार्षद श्रीमती पूनम शरद असाटकर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए नगर में बनाए गए डिवाइडरों एवं लगाए गए विद्युत पोलों की गुणवत्ता पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि नगर परिषद के कई निर्माण कार्य समय से पहले ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे जनता के पैसों के दुरुपयोग की बू आने लगी है। पार्षद श्रीमती पूनम आसटकर ने आरोप लगाया कि नगर में बनाए गए डिवाइडरों से लगातार कांक्रीट झड़ रहा है, कई स्थानों पर निर्माण सामग्री टूट रही है और डिवाइडरों की चौड़ाई आवश्यकता से अधिक होने के कारण वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदारों की चुप्पी लोगों को खटक रही है। उल्लेखनीय है की पार्षद पूनम शरद आसटकर इससे पहले भी वे लगातार नगर की समस्याओं को प्रमुखता से उठाती रही हैं। चाहे डिवाइडरों और सड़कों की अव्यवस्था का मामला हो उन्होंने कई जनहित के मुद्दों पर खुलकर आवाज बुलंद की है। इस गंभीर मामले को लेकर विगत तीन माह पूर्व भी श्रीमती पूनम आसटकर शिकायत कर चुकीं है परंतु नगर परिषद के जिम्मेदारों द्वारा उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ठेकेदार को क्लीन चिट दे दी थी जिसका खामियाजा अब नगर की जनता को गुणवत्ताहीन निर्माण के रूप में उठाना पड़ेगा।

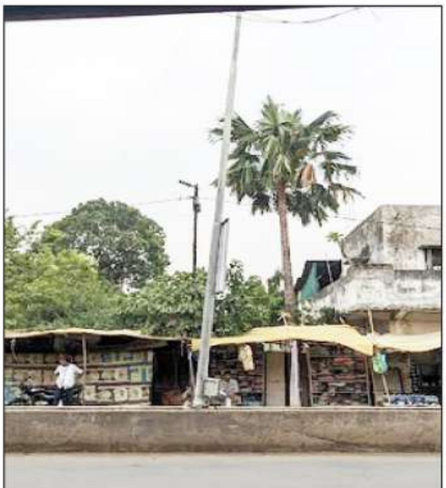

विद्युत पोलों को लेकर भी गंभीर सवाल

विद्युत पोलों की स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत के अनुसार कई पोलों के बेस से कांक्रीट उखड़ रहा है तथा उन्हें जकड़ने वाले बोल्ट बाहर दिखाई दे रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार कार्य नहीं हुआ तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस पूरे मामले में नगर परिषद में पदस्थ इंजीनियर की भूमिका पर भी तीखे सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इंजीनियर शायद ही कभी निर्माण स्थलों पर पहुंचकर निरीक्षण करते हों। ठेकेदार मनमर्जी से काम कर रहे हैं और तकनीकी निगरानी केवल कागजों तक सीमित होकर रह गई है। यही वजह है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य खोखले साबित हो रहे हैं।

सीएमओ भी लगा रहे भ्रष्टाचार की गंगा में डूबकी

नगर में यह चर्चा भी जोरों पर है कि नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को यहां का पानी' बहुत कम समय में ही सूट कर गया है। लोगों का कहना है कि जिस सख्ती और जवाबदेही की उम्मीद की जा रही थी, वह धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। उल्टा अब नगर परिषद के भीतर फैले भ्रष्टाचार के रंग में जिम्मेदार अधिकारी भी रंगते नजर आ रहे हैं। निर्माण कार्यों की बदहाल स्थिति और लगातार उठते सवाल इस धारणा को और मजबूत कर रहे हैं। पार्षद ने मांग की है कि संपूर्ण निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए तथा लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों, इंजीनियर और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में नागरिकों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो।

पंचायतों को नल-जल योजना में आ रहें अनाप-शनाप बिल

पंचायतों पर छाया आर्थिक संकट, विद्युत विभाग के साथ बैठक कर सुधार की रखी मांग

पद्मेश न्यूज। लांजी। जनपद पंचायत लांजी के सभागृह में मंगलवार 13 मई को हुई बैठक में नल-जल योजनाओं के बिजली बिलों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सरपंचों और सचिवों ने बिजली विभाग की मनमानी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गलत, अनुमानित और बिना मीटर के भारी-भरकम बिलों ने पंचायतों की कमर तोड़ दी है। अनुविभागीय अधिकारी कमलचंद सिंहसार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि जहां मीटर लगा ही नहीं है, वहां भी लाखों रुपये के बिल थोपे जा रहे हैं। कहीं वास्तविक खपत से कई गुना ज्यादा यूनिट जोड़ दी गई तो कहीं एवरेज बिलिंग के नाम पर मनमानी की जा रही है। ग्राम पंचायत आवा के प्रतिनिधियों ने बताया कि हर महीने वास्तविक खपत से ज्यादा यूनिट जोड़कर बिल भेजा जा रहा है, जिससे 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ग्राम पंचायत बिंझलगांव के सरपंच-सचिव ने खुलासा किया कि पंचायत क्षेत्र के तीन स्थानों पर आज तक मीटर नहीं लगाए गए, फिर भी लगातार बिल आ रहे हैं। एक मीटर में फरवरी 2026 की रीडिंग इतनी बढ़ा-चढ़ाकर डाली गई कि बिल अनाप-शनाप हो गया। ग्राम पंचायत मोहारा ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि कुल 8 कनेक्शनों में सिर्फ 5 में डिजिटल मीटर लगे हैं, जबकि मीटर लगने से पहले ही विभाग ने करीब 5 लाख रुपये का एवरेज बिल थमा दिया। इससे पंचायत गहरी आर्थिक संकट में फंस गई है। बैठक में ग्राम पंचायत बिसोनी, बहेला, टेमनी, भानेगांव, सहेकी, सांवरीखुर्द, बड़गांव क, ओटेकसा, कारंजा, औंधियाटोला समेत कई अन्य पंचायतों के सरपंच-सचिवों ने भी अपनी शिकायतें रखीं। अधिकांश ने गलत रीडिंग, बिना मीटर बिल जारी करने, एवरेज बिलिंग और शिकायत के बाद भी सुधार न करने की शिकायत की। पंचायत पदाधिकारियों ने मांग की है कि सभी जगह मीटर तुरंत लगाए जाएं, गलत बिलों का तत्काल सुधार हो, अनुमानित बिलिंग बंद की जाए, वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी किए जाएं। सरपंचों ने साफ चेतावनी दी- अगर बिजली विभाग ने समय रहते बिलों का सत्यापन और सुधार नहीं किया तो नल-जल योजनाओं का संचालन बंद करना पड़ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से पानी की समस्या है, ऊपर से ये बढ़ते बिल योजनाओं पर दोहरी मार बन गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी कमलचंद सिंहसार ने बैठक में उपस्थित बिजली विभाग के अधिकारियों को सभी शिकायतों का तत्काल परीक्षण कर सुधार करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रीडिंग और मीटर संबंधी गड़बड़ियों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि ग्रामीण पेयजल योजनाएं प्रभावित न हों। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जपं लांजी अंकित सिंघई, कनिष्ठ अभियंता ललित मार्को, विश्वजीत शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

छात्र वेद अग्रवाल ने सीबीएसई 12 वी मे 95.4 प्रतिशत अंक हासिल कर लांजी का नाम किया गौरवांवित

पद्मेश न्यूज। लांजी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा घोषित कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम 2026 में कृष्णा पब्लिक स्कूल, भिलाई के छात्र वेद अग्रवाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 95.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय एवं परिवार का नाम गौरवान्वित किया है। बता दे कि वेद अग्रवाल लांजी के प्रतिष्ठित व्यापारी दीपक अग्रवाल के पुत्र है, आपने सीबीएसई 12 वी मे शानदार प्रदर्शन कर सम्पूर्ण लांजी क्षेत्र का नाम गौरवांवित किया है. उल्लेखनीय है कि वाणिज्य संकाय के छात्र वेद अग्रवाल ने अकाउंटेंसी में 99 अंक, अंग्रेजी में 90 अंक, बिजनेस स्टडीज में 96 अंक, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में 92 अंक प्राप्त किए। इसके साथ ही हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल में 100 अंक हासिल कर विशेष उपलब्धि दर्ज की है। वेद के इस शानदार सफलता से परिवार एवं विद्यालय में खुशी का माहौल है। वेद की इस उपलब्धि पर पिता दीपक अग्रवाल, माता रेखा अग्रवाल, बहन हर्षिका अग्रवाल, दादी पुष्पा अग्रवाल, चाचा-चाची ललित एवं श्वेता अग्रवाल सहित भवी अग्रवाल, और राघव अग्रवाल तथा नाते रिश्तेदारों, ईष्ट मित्रों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई प्रेषित कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं विद्यालय के शिक्षकों हरमीत मैम एवं आकाश सर ने भी वेद को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अध्ययन का यह परिणाम है। वेद ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं नियमित अध्ययन को दिया। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास, समय प्रबंधन और लगातार मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. विद्यालय प्रबंधन ने भी अग्रवाल की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।

ऋषभ भीमटे ने एमपी एसईटी परीक्षा मे हासिल की सफलता

पद्मेश न्यूज। किरनापुर। तहसील मुख्यालय ग्राम पंचायत किरनापुर के वार्ड नंबर 15 निवासी धनराज भीमटे के सुपुत्र एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऋषभ भीमटे ने अपनी लगन एवं कठिन परिश्रम के बदौलत MP SET परीक्षा में भूगोल विषय से सफलता प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बताएं कि MP SET (Madhya Pradesh State Eligibility Test (मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा) है। यह परीक्षा [MPPSC (मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग) द्वारा राज्य के सरकारी व निजी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। ऋषभ भीमटे की इस सफलता पर ग्राम पंचायत किरनापुर सरपंच धर्मकला भाई जे पी रामटेके, डॉ. शुभेच्छा पलास ऊके,व्ही एन मेश्राम, एम आर बागड़े,एस सी वैद्य, एस आर पटले, रविन्द्र कुमार शेंडे,राकेश बोरकर दुर्गेश भीमटे, अमित गेडाम, संदीप नागवंशी, राजेन्द्र वैद्य, दिलीप धरडे,प्रेमनाथ नागवंशी, डैनी भीमटे, गजेन्द्र सूर्यवंशी,मिलिंद चौरे, स्वाकेश भीमटे, प्रजात वासनिक,राहुल वैद्य, मुन्ना रामटेके,अमरदीप रामटेके, मनोज भीमटे,हंसराज वाहने, देवेन्द्र वासनिक,जे के गेडाम, शैलेष नागवंशी,महेश डोंगरे,सहित समस्त सामाजिक बंधुओं ने हर्ष व्यक्त कर ऋषभ भीमटे को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

बिना अनुमति धड़ल्ले से हो रहा बोरवेल खनन, प्रशासनिक नियमों को आखिर कौन दिखा रहा ठेंगा?

बिसोनी में कार्रवाई के बाद उठे सवाल – अनुमति पत्र देखे बिना कैसे पहुंच रही बोरवेल मशीनें, क्या कार्रवाई का नहीं रहा खौफ?

पद्मेश न्यूज। लांजी। जनपद क्षेत्र लांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसोनी में बिना अनुमति कराए जा रहे बोरवेल खनन पर प्रशासन की कार्रवाई ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घरेलू उपयोग के नाम पर चल रहे इस बोर खनन कार्य में न तो विभागीय अनुमति ली गई थी और न ही नियमों का पालन किया गया, बावजूद इसके बोरवेल मशीन मौके तक पहुंच गई और खनन शुरू भी हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बोरवेल मशीन संचालक अनुमति पत्र देखे बिना काम शुरू कैसे कर देते हैं? जानकारी के अनुसार बिसोनी निवासी बुधराम पिता जैपाल देवगड़े के घर पर भवानी बोरवेल गोपालपुर, किरनापुर की मशीन क्रमांक एमपी 50 जेड ई 9779 से बोर किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर तहसीलदार संजय बारस्कर मौके पर पहुंचे और बिना अनुमति बोर खनन पाए जाने पर मशीन को जब्त कर थाने पहुंचाया गया। तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि मामले में आगे की कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी स्तर से की जाएगी। इधर कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन की सख्ती का वास्तविक खौफ होता तो बोरवेल मशीन संचालक बिना अनुमति दस्तावेज देखे मशीन लेकर मौके पर पहुंचने की हिम्मत ही नहीं करते। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ऐसे मामलों में केवल जुर्माना लगाकर खानापूर्ति कर दी जाएगी, या फिर किसी मशीन को राजसात कर प्रशासन सख्त संदेश देगा ताकि नियमों को हवा में उड़ाने वालों पर लगाम लग सके। गौरतलब है कि क्षेत्र में लगातार गिरते भू-जल स्तर के बीच बिना अनुमति बोर खनन गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। इसके बावजूद कई स्थानों पर नियमों को ताक पर रखकर रात-दिन बोर खनन की शिकायतें सामने आती रहती हैं। ऐसे में अब लोगों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिक गई हैं कि यह कार्रवाई केवल कागजी साबित होगी या फिर वास्तव में नियम तोड़ने वालों पर नकेल कसने वाली मिसाल बनेगी।

चार माह के मासूम अयांश को मिली नई जिंदगी की उम्मीद

एयर एम्बुलेंस से मुंबई रवाना, आयुष्मान योजना से होगा नि:शुल्क उपचार

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के चार माह के मासूम अयांश मसराम के लिए गुरुवार का दिन नई उम्मीद लेकर आया। गंभीर हृदय रोग से जूझ रहे अयांश को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की पहल पर शुरू की गई पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना के तहत एयर लिफ्ट कर बेहतर उपचार के लिए मुंबई भेजा गया। यह पूरा उपचार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निश्शुल्क कराया जा रहा है। कटंगी विकासखंड के ग्राम देवरी बुजुर्ग निवासी अयांश मसराम, पिता शैलेश मसराम, पिछले कई दिनों से गंभीर हृदय रोग से पीड़ित था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार के लिए बड़े शहर में इलाज कराना लगभग असंभव था। लेकिन शासन की संवेदनशील पहल और जिला प्रशासन की तत्परता ने इस मासूम को जीवनदान की उम्मीद दे दी। कलेक्टर मृणाल मीना के मार्गदर्शन में 14 मई 2026 को सुबह जिला चिकित्सालय बालाघाट से अयांश को पड़ोसी महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले के बिरसी एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से प्रात: 10 बजे पीएम श्री एयर एम्बुलेंस द्वारा उसे मुंबई स्थित नारायण हृदयालय के लिए रवाना किया गया। वहां उसका उपचार एवं आवश्यक सर्जरी आयुष्मान भारत योजना के तहत नि:शुल्क होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ परेश उपलप की मौजूदगी में बच्चे को एयरलिफ्ट कराया गया। इस दौरान जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक आरबीएसके राजाराम चक्रवर्ती भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि 8 मई को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जिला चिकित्सालय बालाघाट के डीईआईसी में आयोजित विशेष शिविर के दौरान अयांश की गंभीर हृदय बीमारी का चिन्हांकन किया गया था। मुंबई के नारायण हृदयालय की शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ प्रिया प्रधान ने जांच के बाद बच्चे की तत्काल सर्जरी आवश्यक बताई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। बीते दो दिनों से जिला अस्पताल के पीआईसीयू में डॉ राहुल गेडाम एवं डॉ आशुतोष बांगरे की निगरानी में बच्चे का उपचार चल रहा था। स्वास्थ्य में सुधार होने पर उसे मुंबई रेफर करने का निर्णय लिया गया। सबसे भावुक पल उस समय आया जब अयांश के परिजन एयर एम्बुलेंस में बैठे। आंखों में आंसू लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। परिजनों ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बच्चा एयर एम्बुलेंस से मुंबई इलाज के लिए जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन की मदद ने उनके बच्चे को नई जिंदगी की उम्मीद दी है। परिजनों की भावुक स्थिति देखकर सीएमएचओ डॉ उपलप ने उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। अधिकारियों की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि शासन की योजनाएं जरूरतमंदों के लिए

लांजी में ''पद्मेश''
इंटरनेट (ब्राडबेंड) कनेक्शन के लिये संपर्क करें
Mo. 8319969927

एमपी में 1.20 लाख पद पर अब नहीं होंगी नई भर्तियां

सिर्फ नियमित और संविदा पदों पर ही भर्ती होगी

भोपाल । एक और जहां प्रदेश के युवा रोजगार की मांग को लेकर आए दिन धरना प्रर्शन करते नज़र आते है वही दूसरी और मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने अब प्रदेश के 1 लाख 20 हजार पदों को डाइंग कैडर घोषित कर दिया है। यानी इन पदों पर नई भर्तियां नहीं होंगी। कैबिनेट ने कार्यभारित, आकस्मिकता निधि और संविदा, कोटवार श्रेणी के पद समाप्त करने का फैसला किया था।

इस पर अमल के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा है कि अगर किसी विभाग या कलेक्टर, विभाग अध्यक्ष ने इन पदों पर नियुक्तियां की तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सरकार का दावा है कि वित्तीय बोझ कम करने के लिए यह फैसला लिया है।

अब सिर्फ नियमित और संविदा पदों पर भर्ती

सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश से अब साफ हो गया है कि प्रदेश में अब सिर्फ नियमित और संविदा पदों पर ही भर्ती की जाएगी। दूसरे सभी कैडर के पदों को खत्म कर दिया गया है। इन पदों पर अब भविष्य में कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी।

कार्यभारित पद सड़क, सिंचाई और भवन निर्माण जैसी परियोजनाओं के लिए अस्थायी रूप से बनाए जाते थे। आकस्मिकता निधि कर्मचारियों का वेतन अस्थायी खर्च के लिए निर्धारित निधि से दिया जाता था।

संविदा, कोटवार पद पर निश्चित अवधि के अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां की जाती थीं। आदेश में स्पष्ट कहा है कि यदि इन समाप्त पदों पर नियमों के विरुद्ध नियुक्ति की गई, तो संबंधित कलेक्टर, कमिश्नर या विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस कैटेगरी के इतने पद हुए खत्म

जिन पदों को खत्म किया है उसमें कार्यभारित श्रेणी के 16,810 पद, आकस्मिकता निधि के 55,808 पद, संविदा और कोटवार श्रेणी के 34,497 पद शामिल हैं। इसके साथ ही नियमित पदों पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को मार्च 2027 तक हटाने और उनकी जगह नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर फैसला वापस लेने की मांग की

मध्य प्रदेश के नौजवान लगातार सरकार से रोजगार और नौकरी देने की माँग कर रहे हैं। प्रदेश में 25 लाख से अधिक युवक-युवतियों ने रोजगार पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है अर्थात् आधिकारिक रूप से कम से कम 25 लाख युवा बेरोज़गार हैं।

लेकिन इन बेरोजगारों को नौकरी देने के बजाय सरकार ने प्रदेश में 1.2 लाख से अधिक नौकरियां खत्म कर दी हैं। सरकार का कहना है कि उसके पास वेतन देने के लिए बजट नहीं है। सरकार के पास कमीशन और घोटालों के लिए ही पैसा है क्या?

जो सरकार इवेंटबाज़ी करने के लिए हर महीने हजारों करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है, उस सरकार के पास नौकरी देने के लिए बजट नहीं है।

एक लाख से अधिक पद खत्म कर सरकार ने साबित कर दिया है कि उसके रोजगार मेले ढकोसला हैं। बीजेपी नौजवानों की दुश्मन है और प्रदेश को बेरोजगार प्रदेश बनाना चाहती है।

मैं माँग करता हूँ कि इस फ़ैसले को वापस लिया जाए। यही नहीं सरकार नए पद सृजित कर प्रदेश में नौकरी के नए अवसर पैदा करे।

जून माह में हो सकता है मोहन सरकार में फेरबदल

भोपाल। मध्यप्रदेश में डॉ मोहन यादव सरकार के करीब ढाई वर्ष पूर्ण हो चुके है। ऐसे में अब प्रदेश मँत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह फेरबदल जून माह में कर लिया जाएगा। मोहन मँत्रिमंडल में वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हैं, जबकि मंत्रिमंडल में कुल 35 मंत्री हो सकते हैं। अभी चार पद रिक्त हैं। बता दें कि लंबे समय से विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। यह भी बताया जा रहा है कि संतुलन बनाने के लिए कुछ मँत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव यानी मिशन 2028 को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र और जातीय संतुलन साधने के लिए विस्तार किया जाएगा। माना जा रहा है कि विंध्य, महाकोशल और ग्वालियर-चंबल जैसे क्षेत्रों को नया प्रतिनिधित्व मिल सकता है।

विस्तार के मामले में पडोसी राज्य से पीछे

मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में एक साथ वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में काफी पहले कैबिनेट विस्तार हो चुका है। छग की विष्णु देव साय सरकार ने

प्रशासनिक कसावट और क्षेत्रीय समीकरणों को समय रहते दुरुस्त कर लिया है। वहां अगस्त 2025 में ही मँत्रिमंडल का विस्तार कर तीन मँत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मुकाबले वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मँत्रियों और कई बार के विधायकों की संख्या बहुत अधिक है। महाकोशल, विंध्य, और ग्वालियर-चंबल जैसे अंचलों से कई दिग्गज कतार में हैं, जिसके कारण केंद्रीय नेतृत्व को समीकरण साधने में लंबा समय लगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट के पुनर्गठन का काम तो आरंभ कर दिया गया है, जून अँतिम या जुलाई के पहले पखवाड़े तक इसे पूरा कर दिया जाएगा। 13 मई को मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के ढाई साल पूरे हो गए हैं। पार्टी ने अब मिशन 28 की तैयारी भी आरंभ कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेता 17 मई को मँत्रियों के साथ अलग- अलग बातचीत भी करेंगे। इस आधार पर किन मँत्रियों का प्रदर्शन कमजोर रहा है, उन्हें चिह्नित किया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुछ विवादों में रहने वाले वरिष्ठ मँत्रियों को मँत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है।

हाई कोर्ट का समय फिर बदला, अब सुबह 10 बजे से होगी सुनवाई, नियम शुक्रवार से लागू

जबलपुर। हाई कोर्ट की स्थापना के बाद दूसरी बार न्यायालयीन समय बढ़ाया गया है। हाई कोर्ट में अब पंद्रह मिनट अधिक कार्य होगा। सुबह 10.15 की जगह अब हाईकोर्ट में सुनवाई सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। नया नियम शुक्रवार से ही लागू हो जाएगा। हाई कोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) समीर कुलश्रेष्ठ ने मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के निर्देश पर इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में हाई कोर्ट के काम का समय सुबह 10.30 से सायं 4.30 तक था। इस बीच विश्राम की अवधि 1.30 से 2.30 बजे तक थी। तीन जनवरी 2022 को इसमें संशोधन किया गया था। संशोधित समय के अनुसार सुबह 10.15 से सायं 4.30 तक न्यायालयीन कार्य हो रहा था। विश्राम की अवधि दोपहर 1.30 से 2.15 तक है। नए आदेश के तहत भोजनावकाश या कोर्ट उठने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कामकाज सुबह दस बजे शुरू होगा।

अब बिजली खरीद समझौतों के लिए कैबिनेट की पूर्व मंजूरी होगी अनिवार्य

भोपाल। मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने निर्णय लिया है कि नई दीर्घकालीन और मध्यकालीन बिजली खरीद समझौते (क्क्ष) और बिजली आपूर्ति समझौते (क्क्ष) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लागू किये जा सकेंगे। यह निर्णय शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अब तक समझौते कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित किए जाते थे, लेकिन अब सभी नए समझौतों के लिए कैबिनेट स्तर की मंजूरी प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। ऊर्जा विभाग और राज्य सरकार पहले से मौजूद लगभग 1,795 छोटे, बड़े एवं लघु तथा दीर्घ अवधि के बिजली खरीद समझौतों और 26,012 मेगावाट की क्षमता के फलस्वरूप वर्तमान में प्रदेश में निर्बाध विद्युत सप्लाई कर रही है। साथ ही मध्यप्रदेश एनर्जी सरप्लस राज्य के रूप में कार्य कर रहा है।

इस नीति में बदलाव का प्रमुख कारण यह है कि दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौते अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताएं हैं, जो वर्षों तक सरकार को प्रभावित करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये समझौते राज्य के हित में हो और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करें। एक अन्य कारण यह भी है कि वर्तमान में नई तकनीकी के कारण बायोमास, सोलर बेट्री स्टोरेज, पम्प हाउड्रो स्टोरेज, न्यूक्लियर एनर्जी जैसी कई नई तकनीकों से उत्पादित होने वाली ऊर्जा के अनुबंधों के प्रस्ताव आ रहे हैं, इस बारे में राज्य शासन और वित्त विभाग के परामर्श की आवश्यकता महसूस हो रही है।

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि बोर्ड ने गहन विचार-विमर्श के बाद वर्तमान ऊर्जा की उपलब्धता और राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की वर्तमान एवं भविष्य की व्यवस्था को देखते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड का यह प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा।

मध्यप्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र वर्तमान में अत्यंत मजबूत है और इसमें राज्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। सौर, पवन, थर्मल और अन्य नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से राज्य की बिजली की जरूरतें पूरी हो रही हैं। यह निर्णय राज्य की बिजली आपूर्ति को स्थिर रखने और भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धा को दर्शाता है।

मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर शासन को बढ़ावा देगा। इससे सभी नई बिजली खरीद योजनाएं अधिक सुविचारित और राज्य की ऊर्जा नीति के अनुरूप होंगी।

भिंड भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष को वाहन रैली पड़ी भारी : सज्जन सिंह यादव को पद से हटाया

भोपाल। भाजपा के भिंड जिला किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव को वाहन रैली निकालना भारी पड गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हे पद से हटा दिया है।

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीजल-पेट्रोल की खपत कम करने की अपील के बावजूद निकाली गई वाहन रैली को संगठन ने अनुशासनहीनता माना। मामले की जानकारी सामने आने के बाद प्रदेश भाजपा संगठन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिलाध्यक्ष पद से हटाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। संगठन का मानना है कि पार्टी की कार्यशैली और शीर्ष नेतृत्व के संदेश के विपरीत इस तरह की वाहन रैलियां गलत संदेश देती हैं और यह प्रधानमंत्री की अपील की अवहेलना है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए अपने कारकेड में 13 वाहनों को घटकार 8 कर दिया है। बुधवार को सीएम के कारकेट में सिर्फ 6 वाहन थे। उन्होंने मँत्रियों और निगम मंडलों में हो रही नियुक्तियों के पदाधिकारियों को सालीन तरीके से पदभार ग्रहण करने और मंत्रियों को भी अपने काफिले में गाड़ियां कम करने की अपील की थी। इसके बाद पार्टी और सरकार दोनों स्तर पर सादगी और ईंधन बचत को लेकर संदेश दिया जा रहा है। ऐसे में बुधवार को किसान मोर्चा की ओर से निकाली गई बड़ी वाहन रैली संगठन के निशाने पर आ गई।

केंद्रीय मंत्री शिवराज ने लिखी पीएम पर किताब अपनापन

भोपाल । केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कार्यशैली पर आधारित पुस्तक अपनापन लिखी है। इसकी जानकारी शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। पुस्तक का विमोचन 26 मई को दिल्ली में किया जाएगा। शिवराज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके लिए अपनापन केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिताए गए 33 वर्षों के अनुभवों को शब्दों में उतारने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि दुनिया मोदी को एक नेता के रूप में देखती है, लेकिन उन्होंने उनमें एक साधक, कर्मयोगी और असाधारण इंसान को करीब से देखा है।

खैर वनोपज के अवैध व्यापार में शामिल मुख्य सरगना अनूप यादव को किया गिरफ्तार

भोपाल । सामान्य वनमंडल शिवपुरी के वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा अंतर्गत शिकार, अवैध कटाई एवं अवैध परिवहन के आरोपी अनूप यादव पर 7 मई, 2025 को अपराध प्रकरण दर्ज किया गया था। फरार आरोपी की तलाश के लिये स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा दल बनाकर राज्य के बाहर हरियाणा व राजस्थान भेजा गया था। मुखबिर तंत्र विकसित कर छापामार कार्यवाही की गई। कार्यवाही में खैर के अवैध व्यापार के मुख्य सरगना अनूप यादव पुत्र सुरेश यादव, उम्र 34 वर्ष, निवासी झांसी खास, सीपरी बाजार, जिला झांसी (उ.प्र) को 10 मई, 2026 को मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, क्षेत्रीय इकाई शिवपुरी, वनमंडल शिवपुरी और वनमंडल ग्वालियर द्वारा संयुक्त कार्यवाही के दौरान घाटीगांव, जिला ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आरोपी द्वारा खैर की अवैध कटाई कर अवैध परिवहन कर हरियाणा भेजा गया था।

आरोपी अनूप यादव को 11 मई, 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी के समक्ष पेश किया गया। आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में सर्किल जेल शिवपुरी में निरुद्ध है। प्रकरण की विवेचना जारी है। उक्त आरोपी के विरुद्ध खैर के अवैध व्यापार एवं परिवहन से संबंधित वन विभाग के कुल 2 प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध है। इनमें प्रथम प्रकरण वनमंडल शिवपुरी (सामान्य) के वन परिक्षेत्र शिवपुरी अंतर्गत तथा द्वितीय प्रकरण वनमंडल दतिया के वन परिक्षेत्र गोराघाट अंतर्गत दर्ज है। इसके अतिरिक्त थाना गोराघाट में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत वन अमले पर जानलेवा हमला किये जाने संबंधी प्रकरण भी पंजीबद्ध है। आरोपी का संगठित गिरोह घाटीगांव-ग्वालियर, सतनवाड़ा-शिवपुरी एवं मुरैना क्षेत्र में सक्रिय होकर खैर के व्यापार एवं परिवहन गतिविधियों में संलिप्त है। उक्त क्षेत्रों से खैर की अवैध कटाई करवाकर ट्रक से हरियाणा भेजी जाती है। खैर वनोपज की तस्करी संगठित गिरोह द्वारा देश के कई राज्यों में की जा रही है। खैर की लकड़ी का उपयोग पान मसाला और कत्था बनाने में किया जाता है।

नीट-यूजी पेपर लीक के विरोध में एनटीए मुख्यालय पर अभाविप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ दुर्भाग्यपूर्ण-अभाविप

भोपाल । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) दिल्ली ने नीट-यूजी परीक्षा में सामने आए पेपर लीक प्रकरण, परीक्षा प्रक्रिया में लगातार उजागर हो रही अनियमितताओं तथा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हो रहे गंभीर खिलवाड़ के विरुद्ध दिल्ली स्थित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (हृञ्ज) मुख्यालय के बाहर एक जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा बल प्रयोग करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया।

अभाविप का यह स्पष्ट मत है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही गड़बड़ियाँ देशभर के लाखों विद्यार्थियों के परिश्रम, विश्वास और भविष्य पर सीधा आघात हैं। नीट-यूजी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक की घटना केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, अपितु संपूर्ण परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। वर्षों की कठिन तैयारी और अथक परिश्रम के बाद परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार का अन्याय किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। नीट-यूजी पेपर लीक मामले की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से कराई जाए तथा जांच से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि इस पूरे नेक्सस को सामने लाकर ध्वस्त किया जा सके और देशभर के विद्यार्थियों का विश्वास पुनः स्थापित हो। अभाविप ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का

संचालन अस्थायी एवं आउटसोर्स आधारित व्यवस्था के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। प्रिंटिंग, परीक्षा केंद्र प्रबंधन तथा स्टाफिंग जैसी संवेदनशील जिम्मेदारियों को निजी एजेंसियों को सौंपना गंभीर सुरक्षा संकट को जन्म देता है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशंका बढ़ाता है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि, एनटीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी गत वर्षों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के संचालन में विफल रही है। नीट-यूजी पेपर लीक का यह पहला मामला नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि एनटीए परीक्षा संचालन में पूरी तरह सक्षम नहीं है तथा इसके पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय है। अभाविप पूर्व में भी परीक्षाओं को पूर्णतः पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की मांग करती रही है। केंद्र सरकार को परीक्षा प्रणाली में व्यापक संरचनात्मक सुधार करते हुए निजी एजेंसियों पर निर्भरता समाप्त करनी चाहिए, ताकि भविष्य में विद्यार्थियों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ न हो। आज दिल्ली सहित देशभर के प्रमुख केंद्रों पर अभाविप कार्यकर्ता विद्यार्थियों के हित में आंदोलनरत हैं।

अभाविप दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इतने गंभीर मुद्दे पर जवाबदेही तय करने के बजाय छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा ही छात्र हित में खड़ी है और जब तक नीट-यूजी पेपर लीक के वजह से प्रभावित 22 लाख अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक विद्यार्थी परिषद उनके अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी।

नीट घोटाला केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़

भोपाल। मध्यप्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बुधवार को केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं और केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण आदिवासियों के विस्थापन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने नीट परीक्षा विवाद को केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। पटवारी ने कहा कि देश इस समय दो बड़े संकटों से जूझ रहा है, पहला 'नीट परीक्षा घोटाला' और दूसरा केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के नाम पर आदिवासियों का "शोषण"।

उन्होंने कहा कि ये केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, बल्कि देश के भविष्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल हैं। पटवारी ने कहा कि 3 मई को नीट परीक्षा में करीब 24 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन एक बार फिर पेपर लीक और धांधली ने विद्यार्थियों और उनके परिवारों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट-यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बीच मंगलवार को रद्द कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने मामले में "अनियमितताओं" की व्यापक जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए हैं। पटवारी ने दावा किया कि इससे पहले भी कई परीक्षाओं में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा हमेशा अधिकारियों पर फोड़ने की कोशिश करती है। जब-जब परीक्षा घोटाले सामने आए हैं, तब-तब बीजेपी से जुड़े लोगों के नाम उजागर हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को शिक्षा व्यवस्था पर थोपा जा रहा है और विभिन्न संस्थानों में "अपने लोगों" की नियुक्ति की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक और भर्ती घोटाले हुए हैं। मध्यप्रदेश के व्यापमं घोटाले का जिक्र करते हुए पटवारी ने कहा कि बीजेपी के राज में युवाओं के भविष्य को व्यवस्थित तरीके से बर्बाद किया गया है।

वहीं पटवारी ने केन-बेतवा परियोजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वह पिछले कई दिनों से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 11 मई को उन्होंने पन्ना में आंदोलनरत विस्थापित परिवारों से मुलाकात की और अगले दिन छतरपुर जिले में प्रभावित लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों से मिलने के लिए कहा था और कांग्रेस उनके संघर्ष में मजबूती से साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना के कारण हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित हो रहे हैं और उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पटवारी ने दावा किया कि कई वर्ष पहले तय की गई मुआवजा राशि अब बेमानी हो चुकी है और उस समय नाबालिग रहे परिवार के सदस्यों को पुनर्वास और मुआवजे के दायरे से बाहर रखा गया है।

एसडीएम का रीडर ले रहा था 30 हजार की घूस, रंगे हाथों पकड़ा गया

भोपाल। नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा एसडीएम कार्यालय में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने यहाँ घात लगाकर कार्रवाई करते हुए कार्यालय में पदस्थ बाबू सौरभ यादव को कॉलोनाइजर से 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा।

विभाग द्वारा साझा की ग जानकारी के अनुसार फरियादी संजय राय पिता अशोक राय (32) निवासी, तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर ने ईओडब्ल्यू मुख्यालय जबलपुर में लिखित शिकायत करते हुए बताया उसने अपनी कॉलोनी की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से संबंधित नक्शा प्रस्तावित करने के लिये एसडीएम तेंदूखेड़ा कार्यालय को स्पॉट वेरिफिकेशन की जॉच रिपोर्ट लगाने के लिये आवेदन दिया था। लेकिन उसकी फाइल को एसडीएम कार्यालय तेंदूखेड़ा द्वारा बिना किसी कारण लटकाया जा रहा है। बाद में जानकारी लेने पर सौरभ यादव, स्टेनो, कार्यालय एसडीएम, तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर द्वारा इस कार्य के ऐवज में रिश्वत 30 हजार की रिश्वत की मांग की जा रही है। शुरुआती जॉच में रीडर द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत सही पाये जाने पर ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे दबोचने के लिये योजना तैयार की। रिश्वत की रकम के संबध में फरियादी को आरोपी से बात कराई गई जिस पर आरोपी रीडर ने उसे रकम लेकर ऑफिस बुलाया। गुरुवार को फरियादी रकम लेकर एसडीएम कार्यालय तेंदूखेड़ा पहुचां। वहाँ जैसे ही आरोपी बाबू सौरभ यादव ने फरियादी से रिश्वत की रकम अपने कब्जे में ली वहाँ पहले से जाल बिछाकर बैठी ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे दबोच लिया। बाद में कार्यवाही के दौरान आरोपी के हाथ धुलवाए गए जिस पर वे गुलाबी हो गए, जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। कार्रवाई के दौरान टीम ने संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आरोपी बाबू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

ईओडब्ल्यू रीवा ने ग्राम सचिव ग्राम पंचायत बलभद्रगढ़ जनपद हनुमना जिला मऊगंज को रिश्वत लेते रंगे हांथ किया गिरफ्तार

भोपाल। ईओडब्ल्यू टीम रीवा के द्वारा आज दिनांक 14.05.2026 को जिला मऊगंज के ग्राम पंचायत बलभद्रगढ़ जनपद हनुमना के रिश्वत खोर ग्राम सचिव, शरदचन्द्र गिरी को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। उक्त ग्राम सचिव पुलिया निर्माण कार्य एवं पी.सी. सी. रोड़ निर्माण कार्य का पैसा निकालने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। फरियादी प्रकाश यादव निवासी ग्राम पंचायत बलभद्रगढ़ जनपद हनुमना जिला मऊगंज बलभद्रगढ़ पंचायत के सरपंच का पति है, जिसने दिनांक 12.05.2026 को ग्राम पंचायत में कार्य के बदले भुगतान हेतु आवेदन किया था, परन्तु उक्त भुगतान सचिव के डीएससी सिग्नेचर एवं ओटीपी जनरेट करने के बाद ही संभव था, सचिव डीएससी सिग्नेचर एवं ओटीपी जनरेट करने के लिए एक लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। जिसकी पहली किस्त दस हजार रुपये आज दिनांक 14.05.2026 को शरदचन्द्र गिरी ने जैसे ही ली वैसे ही ईओडब्ल्यू रीवा की टीम ने आरोपी ग्राम सचिव शरदचन्द्र गिरी, को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में सराहनीय भूमिका निभाने वाली टीम के सदस्य, उ0पु0अधीक्षक सुश्री किरण किरो निरीक्षक मोहित सक्सेना, उप निरीक्षक अभिषेक पाण्डेय, उप निरीक्षक पवन राज, उप निरी0 (अ) संतोष पाण्डेय, प्र0आर0 पुष्पेन्द्र पटेल, प्र0आर0 सत्यनारायण मिश्रा, प्र0आर0 घनश्याम त्रिपाठी, म0प्र0आर0 कुमारी पूजा सिंह गहरवार, आर0 धनंजय अग्निहोत्री, आरक्षक (चालक) संतोष मिश्रा रहे हैं।

सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ के लिए अपनी संभावनाएं बनाये रखने उतरेगी सीएसके

लखनऊ। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम शुक्रवार को अपने घरेलू मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का मुकाबला करेगी। सुपर जायंट्स की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गयी है। ऐसे में उसका प्रयास इस मैच में जीत के साथ ही अपने सत्र का समापन करना रहेगा। दूसरी ओर सीएसके के लिए ये मैच बेहद अहम है। उसे अपने प्लेऑफ की उम्मीदें बनाये रखने ये मैच हर हाल में जीतना होगा।

सीएसके के अभी 11 मैचों में 12 अंक लेकर 5वें स्थान पर है और उसे प्लेऑफ के लिए अपने सभी बचे हुए मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे।

आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनो ही टीमों के बीच अब तक 7 मुकाबले हुए हैं। इसमें से तीन सुपर जायंट्स ने जबकि इतने ही सीएसके ने जीते हैं।

कप्तान रुतुराज गायकवाड़ की सीएसके के पास संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस जैसे बल्लेबाज हैं। सैमसन ने अब तक इस सत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और सीएसक को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। टीम के पास गेंदबाजी में अंशुल कंबोज के अलावा नूर अहमद जैसे स्पिनर है। टीम को जीत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। इस सत्र में अब तक के प्रदर्शन को देखा जाये तो सीएसके जीत की प्रबल दावेदार नजर आती है। वहीं ऋषभ पंत की कप्तानी में उतर रही सुपर जायंट्स का प्रदर्शन सत्र में बेहद खराब रहा है और वह केवल तीन मैच जीतकर 6 अंक हासिल कर पायी है। टीम में निरंतरता की कमी नजर आयी है। उसकी बल्लेबाजी बेहद खराब रही है। गेंदबाजी में केवल युवा प्रिंस यादव ही प्रभावित कर पाये हैं। अन्य गेंदबाजों का प्रदर्शन खराब रहा है। यहां तक की अनुभवी मोहम्मद शमी भी उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाये हैं।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं

लखनऊ सुपर जायंट्स- ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव

इम्पैक्ट प्लेयर- आवेश खान

चेन्नई सुपर किंग्स- रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान) संजू सैमसन (विकेटकीपर), (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, अकील होसेन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मैट हेनरी/स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी

इम्पैक्ट प्लेयर- प्रशांत वीर

फीफा विश्व कप के मेगा हाफटाइम शो में नजर आयेंगी मैडोना, बीटीएस और शकीरा

उद्घाटन समारोह में कार्यक्रम पेश करेगी नोरा फतेही

लॉस एंजेलिस। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मेगा हाफटाइम शो में इस बार पॉप सिंगर मैडोना, पॉप स्टार शकीरा के अलावा दक्षिण कोरिया की बीटीएस भी कार्यक्रम पेश करेगी जबकि उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही कार्यक्रम पेश करेंगी। इस प्रकार ये विश्वकप दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव साबित होगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस विश्वकप में अमेरिकी सुपर बाउल की तरह ही एक मेगा हाफटाइम शो का आयोजन भी किया जाएगा।

फीफा ने हाल ही में एक टीजर वीडियो जारी कर इस मेगा इवेंट की घोषणा की है। इस वीडियो में मशहूर संगीतकार क्रिस मार्टिन और लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर एल्मो के साथ मपेट शो के कई किरदार भी दिखे। जिन्होंने मैडोना, बीटीएस और शकीरा जैसे ग्लोबल आइकॉन के नामों की घोषणा की। इसके बाद से ही सोशल मीडिया में प्रशंसकों में उत्साह है। इस हाफटाइम शो से होने वाली संपूर्ण कमाई फीफा ग्लोबल सिटिजन एजुकेशन फंड को दान की जाएगी। इस नेक पहल का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के जरूरतमंद बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और फुटबॉल की बेहतर सुविधाएं पहुंचाना है। इस फंड के माध्यम से लगभग 100 मिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि लाखों बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सके। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को न्यू जर्सी में खेला जाएगा, जबकि टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून से होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही भी समारोह में कार्यक्रम पेश करेगी। नोरा कनाडा के टोरंटो में स्थित बीएमओ फील्ड में 12 जून को होने वाले इस भव्य समारोह में गायन और नृत्य दोनों प्रस्तुत करेंगी। उनके साथ कनाडा के दिग्गज कलाकार माइकल बुबले, अलानिस मोरिसेट और एलेसिया कारा सहित कई बड़े कलाकर भी मंच पर नजर आयेंगे।

पीएसजी ने लगातार पांचवीं बार लीग 1 का खिताब जीतकर बनाया रिकार्ड

पेरिस। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) ने रेसिंग क्लब डी लेंस के खिलाफ मिली 2-0 की जीत के साथ ही लगातार पांचवीं बार लीग 1 का खिताब अपने नाम किया है। इसी के साथ ही पीएसजी आधिकारिक तौर पर फ्रांस की सर्वोच्च फुटबॉल लीग की विजेता बन गयी है। ये पीएसजी के लिए इस सत्र में घर से बाहर खेलते हुए 11वीं जीत थी। ये इस सत्र में किसी भी टीम द्वारा दर्ज की गई सबसे ज्यादा जीत का नया रिकॉर्ड है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही पीएसजी ने अपना कुल 14वां खिताब जीता है। यह पहली बार है जब क्लब ने लीग 1 के खिताब को लगातार पांचवीं बार हासिल किया है। यह क्लब की कुल 59वीं ट्रॉफी है, जो फुटबॉल जगत में उसकी लगातार बढ़ती ताकत और सफलता को दिखाती है। इस सत्र में पीएसजी ने यह चौथा खिताब जीता है; इससे पहले टीम ने यूईएफए सुपर कप, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप और ट्रॉफी डेस चैंपियंस भी जीती है।

थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे सिंधु और सात्विक-चिराग

बैंकॉक। भारत की शीर्ष महिला बैडमिंटन स्टार पी वी सिंधु जीत के साथ ही बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी हैं। सिंधु के अलावा पुरुष युगल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी जीत के साथ ही क्वार्टर फाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। महिला एकल में सिंधु ने डेनमार्क की शटलर अमाली शुल्ज को केवल 28 मिनट में 21-13, 21-15 से सीधे गेम में हरा दिया। यह इस टूर्नामेंट में सिंधु की लगातार दूसरी जीत थी। अब क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना मौजूदा विश्व चैंपियन और जापान की शीर्ष खिलाड़ी अकाने यामागुची से होगा। सिंधु का जापानी खिलाड़ी के खिलाफ रिकार्ड 15-13 का है जिससे ये मुकाबला रोमांचक होना तय है।

दूसरी ओर पुरुष युगल में, सात्विक और चिराग की शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी ब्रायन जेरेमी गूनटिंग और मुहम्मद हाइकल को सीधे गेम में 21-12 और 21-19 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। । अब सेमीफाइनल में

अपनी जगह पक्की करने के लिए, सात्विक और चिराग का मुकाबला छठी वरीयता प्राप्त जापानी जोड़ी ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी से होगा। इस भारतीय जोड़ी ने पहले मुकाबले में भी इंडोनेशिया के मुह पुत्रा एरवियनस्याह और बगास मौलाना के खिलाफ 21-19, 21-23, 21-10 से कड़े संघर्ष के बाद जीत दर्ज की थी।वहीं टूर्नामेंट में शामिल अन्य भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। श्रीकांत ने अपने शुरुआती दौर में सिंगापुर के आठवें वरीय लोह कीन यू को 21-14, 21-15 के सीधे गेम में हराया था। इसके अलावा थॉमस कप में लगी चोट से वापसी कर रहे लक्ष्य सेन ने भी सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को 43 मिनट में 21-16, 21-17 से हराकर टूर्नामेंट की जीत के साथ शुरुआत की है। महिला एकल में, देविका ने शुरुआती राउंड में जापान की एन. निदाइरा को हराया था, जबकि विश्व की 50वें नंबर की खिलाड़ी बंसोड़ ने भी झांग वेन यू (13-21, 26-24, 21-13) के खिलाफ एक उतार-चढ़ाव भरे मुकाबले में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया।केवल अनमोल खार्ब को हार का सामना करना पड़ा। अनमोल को विश्व नंबर 4 चेन यू फेई ने 21-19, 13-21, 18-21 से हराया।

नेशंस कप से पहले अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएगी भारतीय महिला हॉकी टीम

नई दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम 15 से 21 जून तक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले एफआईएच हॉकी वूमेंस नेशंस कप 2025-26 की तैयारियों के लिए इसी माह ऑस्ट्रेलिया जाएगी। हॉकी इंडिया के अनुसार भारतीय टीम 21 मई से 3 जून तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अभ्यास मैच खेलेगी। वहीं टीम के कोच स्जोर्ड मारिजने के अनुसार

अभ्यास मैचों से खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट से पहले हालातों के अनुसार ढलने में सहायता मिलेगी। वहीं हॉकी इंडिया के अनुसार भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे में वहां की राष्ट्रीय टीम से चार मुकाबले खेलेगी। ये मुकाबले पर्थ हॉकी स्टेडियम में 26, 27, 29 और 30 मई को आयोजित होंगे। इन मुकाबलों के जरिए भारतीय टीम अपनी कमजोरियों को दूर रते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देगी। इसके अलावा टीम न्यूजीलैंड भी अभ्यास के लिए जाएगी। यहां भी टीम अभ्यास मैच खेलेगी। भारतीय टीम ने इस साल की शुरुआत में अर्जेंटीना दौरे पर अच्छा प्रदर्शन किया था जिससे उसके हौसले बुलंद हैं। अर्जेंटीना दौरे से वापसी के बाद भारतीय महिला टीम ने बेंगलुरु स्थित साई शिविर में अभ्यास किया था। इस दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस, पेनल्टी कॉर्नर और डिफेंस पर खास ध्यान दिया गया। वहीं ड्रैग-फ्लिकर्स को नीदरलैंड हॉकी के विशेषज्ञ टकेइ टकेमा 26 मई से 21 जून तक पर्थ और ऑकलैंड में प्रशिक्षण देंगे। कोच ने कहा, हमें खुशी है कि हॉकी इंडिया ने इस दौरे का आयोजन किया। इन मैचों से हमें अपनी कमजोरियां को दूर करने का अवसर मिलेगा। अर्जेंटीना दौरे में हमने टीम का स्तर देखा था और अब हम अपनी प्रगति को परख पाएंगे।

विराट ऑरेंज कैप की दौर में तीसरे नंबर पर भुवनेश्वर पर्पल कैप की दौड़ में नंबर एक पर पहुंचे

रायपुर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के बीच हुए मुकाबले के बाद एक बार फिर ऑरेंज और पर्पल कैप दावेदारों में बदलाव आया है। केकेआर के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर आरसीबी के विराट कोहली एक बार फिर ऑरेंज कैप की दौड़ में तीसरे नंबर पर पहुंच गये हैं। वहीं पर्पल कैप की दौड़ में भी आरसीबी के ही भुवनेश्वर कुमार शीर्ष पर पहुंच गये हैं। विराट ने केकेआर के खिलाफ नाबाद 105 रनों की तेज पारी खेली। यह कोहली के आईपीएल करियर का नौवां शतक था, जिसने उन्हें ऑरेंज कैप तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। वहीं, गेंदबाजी सूची में सनराइजर्स हैदराबाद के अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 22 विकेटों के साथ शीर्ष पर पहुंच गए हैं, जिससे पर्पल कैप की दौड़ भी तेज हो गई है।

विराट के अब इस सत्र की 12 पारियों में अब तक कुल 484 रन हो गये हैं। उन्होंने यह रन 165.75 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का दिखाते हैंहै। इस पारी ने उन्हें सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में

तीसरा स्थान दिलाया है, जिससे ऑरेंज कैप जीतने की उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। ऑरेंज कैप की दौड़ अब बेहद रोमांचक हो गई है। विराट के आगे अब केवल दो बल्लेबाज सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन, जिन्होंने 508 रन बनाए हैं, और गुजरात टाइटंस के बी साई सुदर्शन, जिनके खाते में 501 रन दर्ज हैं। वहीं चौथे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा 481 रनों के साथ मौजूद हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान केएल राहुल 477 रनों के साथ पांचवें नंबर पर हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल भी 467 रनों के साथ दावेदारों में बने हुए हैं, जिससे आगामी मैच और भी दिलचस्प हो गए हैं।

वहीं गेंदबाजी में पर्पल कैप की दौड़ भी रोमांचक हो गयी है। भुवनेश्वर केकेआर के खिलाफ एक विकेट लेने के बाद 22 विकेट लेकर नंबर एक पर पहुंच गये हैं। उन्होंने पंजाब किंग्स के कगिसो रबाडा को पीछे छोड़ दिया है, जिनके 21 विकेट हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के युवा अंशुल कम्बोज 19 विकेटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रिंस यादव, गुजरात टाइटंस के राशिद खान, केकेआर के कार्तिक त्यागी और सनराइजर्स हैदराबाद के इशान मलिंगा सभी 16-16 विकेटों के साथ चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से काबिज हैं।

नीरज चोपड़ा का रोम डायमंड लीग में खेलना संदिग्ध

नई दिल्ली । ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा अगले माह रोम में होने वाले डायमंड लीग भाला फेंक टूर्नामेंट में शायद ही खेल पायें। इसका कारण है कि नीरज अब तक अपनी पीठ की चोट से नहीं उबर पाये हैं। इसी कारण 4 जून को इटली में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए शुरुआती सूची में नीरज का नाम शामिल नहीं है। नीरज अगर नहीं उतरते हैं तो ये प्रशंसकों के लिए निराशाजन होगा। नीरज पिछले साल विश्व चैंपियनशिप से ही फिटनेस से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे थे। इसी कारण अभी वह तुर्की में रिहैब के दौर से गुजर रहे हैं। अभी उनका लक्ष्य पूरी तरह से फिटनपेस हासिल करना है।

वहीं भारत के ही युवा खिलाड़ी सचिन यादव इस टूर्नामेंट से डायमंड लीग में पदार्पण करने के लिए तैयार हैं। सचिन ने पिछले कुछ समय में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में नीरज के नहीं खेलने पर वह भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगे। उन्होंने पिछले कुछ समय में शानदार प्रदर्शन करते हुए 86.27 मीटर का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया था और एक टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल किया था। रोम में दुनिया के कुछ शीर्ष एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा से भी सचिन को लाभ होगा।

रोम डायमंड लीग में चेक गणराज्य के याकूब वाडलेज और जर्मनी के जूलियन वेबर शामिल जैसे दिग्गज भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स भी अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म को फिर से हासिल करने का प्रयास करेंगे। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराज इस सीज़न की शुरुआत में 89.37 मीटर का प्रभावशाली थ्रो दर्ज करने के बाद में इस इवेंट में एक बड़े दावेदार के तौर पर उतरेंगे। ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के थॉमस रोहलर, अमेरिकी एथलीट कर्टिस थॉम्पसन और पोलैंड के डेविड वेगनर भी यहां नजर आयेंगे। ।

आरसीबी से हार के साथ ही केकेआर के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें समाप्त हुई

कोलकाता। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का प्रदर्शन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19 वें सत्र में अच्छा नहीं रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ 11 वें मुकाबले में हार के साथ ही टीम के प्लेऑफ में पहुंची की बची हुई संभावनाएं भी समाप्त हो गयी हैं। केकेआर अभी टीम अंक तालिका में आठवें स्थान पर फिसल गयी है।

अभी के हालातों को देखते हुए केकेआर की कोई संभावना नहीं बची है। टीम ने अब तक खेले गए 11 मैचों में से चार जीते हैं और एक का परिणाम नहीं निकला। इस प्रकार उसके केवल 9 अंक हैं। वहीं लीग स्तर में अब उसे केवल तीन मैच खेलने हैं। वहीं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कुल 16 अंकों की जरूरत होती है। केवल कुछ अवसरों पर ही 14 अंक में प्लेऑफ की संभावना बन सकती है पर ये तभी होगा जब शीर्ष चार टीमों में से कोई भी 16 अंक तक न पहुंचे। केकेआर अपने बचे हुए तीनों मैच जीत भी लेती है, तो उनके कुल अंक केवल 15 ही हो पाएंगे। यह आंकड़ा प्लेऑफ की दौड़ में शामिल कई अन्य टीमों के संभावित अंकों से काफी कम है।

केकेआर के लिए सबसे बड़ी चुनौती अंक तालिका में उनसे ऊपर मौजूद टीमों का प्रदर्शन है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के पहले ही 16-16 अंक हो गये हैं। इनके अलावा, सनराइजर्स हैदराबाद 12 मैचों में 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है और उसे अभी दो मैच खेलने हैं। दोनों मैच जीतने पर वह 18 अंकों तक पहुंच सकती है। पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और उसके पास तीन मैच बचे हैं, जिससे वह 19 अंकों तक जा सकती है। इसी तरह, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स भी दौड़ में बनी हुई हैं। दोनों टीमों के पास 12-12 अंक हैं और उन्हें अभी तीन-तीन मैच खेलने हैं। ये दोनों टीमें भी अपने सभी बचे हुए मैच जीतकर 18 अंकों के आंकड़े तक पहुंच सकती हैं। दिल्ली कैपिटल्स भी इस दौड़ में शामिल है पर उसे भी हर मैच जीतना होगा। इससे साफ है कि केकेआर, अपने अधिकतम 15 अंकों के साथ, इन प्रतिस्पर्धी टीमों के बीच टिके नहीं रह सकती क्योंकि अन्य सभी 16 या उससे अधिक अंक हासिल कर सकती हैं।

आईपीएल में पिछले छह सत्र से असफल रहे हैं शाहरुख

मुम्बई । इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे जो हर सत्र में असफल होने के बाद भी करोड़ों की कमाई करने में सफल रहे हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी है। तमिलनाडु की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले शाहरुख खान। पिछली छह आईपीएल सत्र में शाहरुख ने अलग-अलग फ्रेंचाइजियों की ओर से खेला है पर एक बार भी वह सफल नहीं हुए हैं। इस प्रकार देखा जाये तो पिछले छह सालों में फ्रेंचाइजी टीमों ने इस खिलाड़ी पर 38 करोड़ रुपये से अधिक लुटा दिये हैं पर परिणाम शून्य रहा है। बल्ले और गेंद से उनका प्रदर्शन अब तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। इस सत्र में भी वह गुजरात टाइटंस की ओर से 9 मैचो में 130.30 की स्ट्राइक रेट से केवल 43 रन बना पाये हैं।

इस क्रिकेटर को घरेलू क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी और ऑफ-स्पिन गेंदबाजी के लिए एक बेहतरीन फिनिशर के तौर पर जाना जाता था। 100 से अधिक टी20 मुकाबलों में निचले क्रम में तेज रन बनाने की क्षमता ने उन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजियों की नजरों में ला दिया। सबसे पहले साल 2021 में पंजाब किंग्स ने उन्हें 5.25 करोड़ रुपये में खरीदा पर उनका सत्र सामान्य रहा। पंजाब किंग्स ने उन्हें 2022 और 2023 सीजन के लिए 9-9 करोड़ रुपये में रिटेन किया। शुरुआती कुछ मैचों में उन्होंने अपनी पावर हिटिंग की झलक भी दिखाई, लेकिन निरंतरता

का अभाव रहा। इसके बावजूद, आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में गुजरात टाइटन्स ने उन्हें 7.4 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। गुजरात ने उन पर लगातार भरोसा बनाए रखा और 2025 तथा 2026 सीजन के लिए 4-4 करोड़ रुपये में रिटेन किया, जिससे उन पर कुल खर्च की गई राशि 38 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई।

इतने बड़े निवेश के बावजूद, शाहरुख खान का आईपीएल प्रदर्शन आंकड़ों में अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। उन्होंने अपने छह साल के आईपीएल करियर में कुल 64 मैच खेले हैं, जिनमें 147.90 की स्ट्राइक रेट से 775 रन बनाए हैं। इन छह सीजनों में उन्हें सिर्फ दो अर्धशतक ही दर्ज करने का मौका मिला है, जो एक फिनिशर के तौर पर उनकी क्षमता से कहीं कम है। 2021 में 153 रन, 2022 में 117 रन, 2023 में 156 रन, 2024 में 127 रन और 2025 में 179 रन ही वह बना पाये।

गंभीर रुप से बीमार शपूर जादरान से मिले नबी और राशिद

ग्रेटर नोएडा। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद नबी और राशिद खान यहां अस्पताल में भर्ती अपने देश के पूर्व क्रिकेटर शपूर जादरान को देखने पहुंचे। पूर्व तेज गेंदबाज रहे जादरान एक गंभीर बीमारी, हेमोफैगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (एचएलएच) से पीड़ित हैं और भारत में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। 38 साल के जादरान अभी गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती हैं। अपने पुराने साथी को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा देख नबी भावुक हो गए।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail - modgmmad@mp.gov.in

क्रमांक/400/खनिज/2026 बालाघाट दिनांक 30/4/2026

म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 18(1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त करनें के लिए.

प्रथम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि, आवेदक आयुश गुप्ता निवासी वार्ड नं. 06 पांडव नगर सोहागपुर शहडोल (म.प्र.) द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2026 को प्रस्तुत किया गया है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिवस तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा हे. में	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	रिमार्क
बालाघाट	खैरलांजी	मानेगांव	378/1/6	3.000 हे.	शासकीय	गिट्टी, बोल्डर, मुरूम	-
			कुल रकबा	3.000 हे.			

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करनें की अंतिम तिथि तक (कार्यालय समय सायं 05:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन प्राप्त होते है तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करनें हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 तहत् अधिमान्यता तय करने की आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समक्षा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नही लिया जाएगा।

जी-12870/26

उप संचालक
(खनि प्रशासन)
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

'स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता'

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल

जब सरकार को ही फैसला लेना है, फिर कमेटी में नेता विपक्ष को रखने का दिखावा क्यों

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयुक्त (इश्वइ) और चुनाव आयुक्तों (श्वइ) की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने कहा- अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष (रमक) को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत क्या है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि इब्रहु डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश (इछुदु) शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं रखा गया है।

कोर्ट 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

इस कानून के मुताबिक, इश्वइ और श्वइ की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री वाली समिति करेगी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था में इसमें भारत के इछुदु को भी शामिल किया था।

याचिकाकर्ताओं का दावा- 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है

याचिकाओं में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। इसमें चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (इछुदु) को हटा दिया गया है।

दरअसल, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ' मामले में कहा था कि जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और इछुदु की समिति करेगी। बाद में केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई, जिसमें इछुदु को समिति से बाहर कर दिया गया। इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

> “हर फैसले में 2:1 के बहुमत से कार्यपालिका का पक्ष ही हमेशा भारी रहेगा। फिर नेता विपक्ष के कमेटी में रहने का औचित्य क्या है। क्या कोई कैबिनेट मंत्री कभी PM के खिलाफ जाएगा?
>
> **सुप्रीम कोर्ट**
> CEC और EC की नियुक्ति पर

कोर्ट ने कहा- नेता विपक्ष दिखावटी हो जाते हैं

कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से पूछा, अगर प्रधानमंत्री एक नाम चुनते हैं और विपक्ष का नेता दूसरा नाम चुनता है, और दोनों में मतभेद होता है, तो क्या तीसरा सदस्य विपक्ष के नेता के पक्ष में जाएगा? इस पर अटॉर्नी जनरल ने माना कि शायद ऐसा नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने कहा- तो फिर सब कुछ कार्यपालिका ही कंट्रोल कर रही है। ऐसे में विपक्ष के नेता को शामिल ही क्यों करते हैं? वे सिर्फ दिखावटी हो जाते हैं।

एनईईटी परीक्षा पेपर लीक मामले में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का विरोध

अहमदाबाद। एनईईटी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में छात्रों के बीच भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के अहमदाबाद दौरे के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का काफिला जब इन्डियन इन्स्टीटयूट ओफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के गेट से बाहर निकला, तभी एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता काले झंडे और काले कपड़ों के साथ वहां पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रमों की जानकारी सामान्यतः पहले से सार्वजनिक कर दी जाती है, लेकिन इस बार विरोध की आशंका के चलते पूरे कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया था। इसके बावजूद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की।

कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई देशभर में एनईईटी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ आंदोलन चला रही है। संगठन की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। एनईईटी पेपर लीक मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच के तार राजस्थान, महाराष्ट्र के नासिक और हरियाणा के गुरुग्राम तक जुड़े बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए कानून के तहत इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। इस कानून में पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए 10 वर्ष तक की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि एनईईटी यूजी-2026 परीक्षा के लिए देशभर से करीब 25 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल हो गई है।

जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए, वे राशन और पेंशन के पात्र नहीं

-एसआईआर बंगाल-बिहार में सरकारी योजनाओं के लिए फिल्टर के रूप में उभरी

नई दिल्ली,। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) पहल, जो मूल रूप से वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए शुरू की गई थी, अब पश्चिम बंगाल और बिहार में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक बड़े फिल्टर के रूप में उभर रही है। दोनों राज्यों की सरकारों ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, वे अब राशन और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र नहीं रहेंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सीएम सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद, प्रशासन ने संकेत दिया कि जिन लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटा दिए गए थे, वे कई सरकारी वेलफेयर स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे। बिहार में भी इसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जहां एनडीए सरकार ने एसआईआर में नाम हटने के बाद राशन लिस्ट से लाभार्थियों को हटाना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जिन लोगों के नाम राज्य की वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, उन्हें सरकारी लाभ जिसमें राशन और वेलफेयर स्कीम शामिल हैं नहीं मिलेंगे।

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने बंगाल और बिहार द्वारा उठाए गए इन कदमों को बेहद आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा कि क्या नागरिकता चुनावी सूची में शामिल होने का आधार है, या चुनावी सूची में शामिल होना नागरिकता का आधार है? सुप्रीम कोर्ट को इस सवाल पर विचार करना चाहिए। कोलकाता के एक अखबार ने पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल कल्याण और समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल के हवाले से कहा कि हम 1 जून से महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करेंगे। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन जिन लोगों का सत्यापन अभी भी ट्रिब्यूनल द्वारा किया जा रहा है, उन्हें फिलहाल लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर उनमें से कोई बाद में फिर से चुनावी सूची में शामिल हो जाता है, तो उसे लाभार्थियों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि कोई भी मौजूदा कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी। अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सरकार के सभी सामाजिक कार्यक्रम चाहे वे 30 साल पहले शुरू हुए हों या 10 साल पहले जारी रहेंगे। अब ये सभी योजनाएं एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत काम करेंगी। किसी भी मृत व्यक्ति, अवैध घुसपैठिए या गैर-भारतीय नागरिक को राज्य के नागरिकों के लिए निर्धारित लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पवन खेड़ा गुवाहाटी पहुंचे, पुलिस के सामने पेशी

गुवाहाटी,। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े आरोपों के मामले में गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद खेड़ा ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। यह मामला मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा पर खेड़ा द्वारा लगाए गए पासपोर्ट विवाद के आरोपों से जुड़ा है, इसके तहत खेड़ा को पुलिस के सामने पेश होना पड़ा।

यह विवाद अप्रैल में तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रिनिकी सरमा के पास भारत, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र के तीन पासपोर्ट हैं। खेड़ा ने दुबई में उनकी कुछ अज्ञात संपत्तियों और अमेरिका के व्योमिंग में एक कंपनी होने का दावा किया था। हालांकि, सरमा परिवार ने इन दावों को पुरजोर खंडन कर इन्हें पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूहों द्वारा प्रसारित एआई-निर्मित मनगढ़ंत कहानियाँ बताया था।

आरोपों के जवाब में, मुख्यमंत्री सरमा ने पहले ही कड़ी कार्रवाई की कसम खाकर कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी थी। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था कि आरोप लगाने से पहले उन्हें विदेश मंत्री से पूछना चाहिए था। सीएम सरमा ने सुझाव दिया था कि राहुल गांधी ने खेड़ा को ये फर्जी दस्तावेज दिए और कहा था, हमें डराने की कोशिश मत करो। यह असम है, और हम लोगों ने इस्लामी आक्रमण के खिलाफ 17 बार लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री ने दावा भी किया था कि पुलिस के उनके दिल्ली आवास पर जाने के बाद खेड़ा हैदराबाद भाग गए थे। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने खेड़ा को अग्रिम जमानत दी थी, जो सरमा को कथित रूप से बदनाम करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोपों से संबंधित है।

एनआईए ने खोला शरिया कानून थोपने की जिहादी साजिश का काला चिट्ठा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बीते साल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के बाहर हुए भीषण कार बम धमाके के मामले में निर्णायक कदम उठाया है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 10 आरोपियों को नामजद किया गया है। एनआईए की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे वैश्विक आतंकी नेटवर्क का हाथ था और इसका मकसद लोकतांत्रिक रूप से स्थापित भारत सरकार को उखाड़ फेंककर शरिया कानून लागू करना था। जांच में सामने आया है कि सभी 10 आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (एलीयूएच) और अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस) से सक्रिय रूप से जुड़े थे। चार्जशीट में पुलवामा निवासी और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. उमर उन नबी (मृतक) को इस पूरे हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। उनकी पहचान डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जरिए सुनिश्चित की गई है।

बीते साल नवंबर 10 को हुए इस हाई-इंटेंसिटी धमाके ने पूरी दिल्ली को हिला दिया था। आतंकियों ने व्हीकल-बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कार बम का इस्तेमाल किया था, जिसमें 11 मासूम लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। धमाके के कारण ऐतिहासिक लाल किले के आसपास की संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुँचा था।

एनआईए के अनुसार, डॉ.नबी के अलावा, चार्जशीट में आमिर राशिद मीर, जासिर बिलाल वानी, डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, सोयब, डॉ. बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद डार के नाम शामिल हैं। अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। यह चार्जशीट यूए(पी) एक्ट 1967, भारतीय न्याय संहिता 2023, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, शस्त्र अधिनियम 1959, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की संबंधित धाराओं के तहत दायर की गई है। यह चार्जशीट एक व्यापक जांच पर आधारित है, जो जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र जैसे राज्यों में की गई थी। इसमें 588 मौखिक गवाहियों, 395 से ज्यादा दस्तावेजों और 200 से ज्यादा जब्त की गई चीजों के रूप में विस्तृत सबूत शामिल हैं। जांच में पता चला कि आरोपी—जिसमें से कुछ कट्टरपंथी मेडिकल पेशेवर थेअंसार गजवत-उल-हिंद (एलीयूएच) और अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिंसक जिहादी विचारधारा से प्रेरित होकर यह जानलेवा हमला करने की योजना बना रहे थे।

भारत ने चीनी के निर्यात पर लगाई रोक, देखें कब रहेगी लागू

नई दिल्ली। देश ने चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी है। इससे पहले चीनी निर्यात प्रतिबंधित श्रेणी में आता था जिसका निर्यात करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 13 मई को जारी अधिसूचना में कहा, चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी एवं परिष्कृत चीनी) की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर, 2026 तक या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) प्रतिबंधित से निषिद्ध कर दिया है। हालांकि, यह आदेश क्रमशः सीएक्सएल और शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) व्यवस्था के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं होगा। इन व्यवस्थाओं के तहत निर्यातकों को निर्धारित मात्रा में चीनी को इन गंतव्यों पर काफी कम या शून्य सीमा शुल्क पर भेजने की अनुमति मिलती है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय का यह आदेश अग्रिम प्राधिकरण योजना, सरकार-से-सरकार निर्यात और उन खेपों पर लागू नहीं होगा जो पहले से भौतिक निर्यात प्रक्रिया में हैं। चीनी विपणन वर्ष 2025-26 (अक्टूबर से सितंबर) के लिए खाद्य मंत्रालय ने शुरुआत में 15 लाख टन निर्यात की अनुमति दी थी। फिर 5,00,000 टन का अतिरिक्त कोटा खोला गया जिसमें से केवल 87,587 टन को मंजूरी दी है। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 16 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी गई। खाद्य मंत्रालय और चीनी मिलों को उम्मीद थी कि समूचे 2025-26 विपणन वर्ष में 7.5-8 लाख टन का निर्यात होगा।

नीट-यूजी पेपर लीक में बड़ा खुलासा, हाथ से लिखे प्रश्नपत्र पहुंचे थे सेंटरों में

नई दिल्ली। सीबीआई की जांच में नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, लीक हुआ प्रश्नपत्र आरोपी यश यादव के जरिए राजस्थान पहुंचा था, जहां इसे सीकर जिले के कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों तक पहुंचाया गया। सूत्रों के मुताबिक, प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के बदले छात्रों से दो लाख से पांच लाख रुपये तक वसूले गए।

जांच में यह भी सामने आया है कि यश यादव की पहचान एक अन्य आरोपी विकास बिवाल से थी। एजेंसी को पता चला है कि विकास बिवाल के पिता दिनेश बिवाल ने ही प्रश्नपत्र की हार्ड कॉपी को स्कैन कर उसे पीडीएफ फॉर्मेट में बदला था। इसके बाद आरोपियों ने शक से बचने के लिए प्रश्नपत्र को हाथ से लिखकर छात्रों के बीच बांटा। सूत्रों के अनुसार, सीकर के कुछ कोचिंग संस्थानों में परीक्षा से पहले चयनित छात्रों को कथित रूप से यह प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया गया। मामले की जांच के तहत सीबीआई ने कोचिंग संस्थानों के मालिकों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। जांच एजेंसी फिलहाल उस पूरी श्रृंखला की पड़ताल कर रही है, जिसके जरिए प्रश्नपत्र लीक होकर आरोपियों तक पहुंचा और फिर छात्रों में वितरित किया गया। साथ ही पैसों के लेन-देन और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपियों को बुधवार देर रात जयपुर में एक मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया। जांच एजेंसी ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए अदालत में प्रस्तुत किया। वहीं, आरोपी शुभम ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए खुद को साजिश का हिस्सा मानने से इंकार किया है।

दर्ज किए जा रहे आरोपियों के बयान

इस मामले में छात्रों और आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सीबीआई ने 12 मई को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। शिकायत में परीक्षा आयोजन में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप लगाए गए थे।

बिहार में भी हुआ गिरोह का भंडाफोड़

इस बीच बिहार पुलिस ने भी नीट-यूजी 2026 पेपर लीक से जुड़े एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। राजगीर के डीएसपी सुनील कुमार सिंह के अनुसार, पुलिस ने कई मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए हैं, जिनमें डिजिटल सबूत मिले हैं। चैट रिकॉर्ड्स में पैसों के लेन-देन और मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। उल्लेखनीय है कि 3 मई को आयोजित हुई नीट-यूजी 2026 परीक्षा को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। एनटीए के अनुसार, इस परीक्षा में 22.79 लाख छात्र शामिल हुए थे और परीक्षा देश के 551 शहरों समेत विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी।

संबित पात्रा ने राहुल गांधी की आय और विदेश यात्राओं के खर्च पर किये खुलासे

नई दिल्ली । भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाते हुए उनकी आय के स्रोत के खुलासे की मांग की। पार्टी ने दावा किया कि राहुल गांधी की साल दर साल आय और उनकी विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च के बीच स्पष्ट विसंगति है।

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी पिछले 22 वर्षों में 54 बार विदेश यात्रा पर गए, जिन पर कुल 60 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आया। भाजपा नेता ने कहा कि इसके विपरीत, पिछले 10 वर्षों के चुनावी हलफनामों के अनुसार उनकी कुल घोषित वार्षिक आय लगभग 11 करोड़ रुपये रही है। सांसद पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की घोषित कुल संपत्ति 2004 में 55.38 लाख रुपये थी, जो 2024 में बढ़कर 20.39 करोड़ रुपये हो गई।

उन्होंने सवाल किया, जब उनकी कुल संपत्ति और देनदारियां लगभग 21 करोड़ रुपये हैं, तो इन विदेश यात्राओं पर खर्च हुए 60 करोड़ रुपये का हिसाब कैसे बैठता है? भाजपा सांसद ने मांग की कि कांग्रेस और राहुल गांधी बताएं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की इन यात्राओं का खर्च किसने उठाया। गांधी की विदेश यात्राओं का वर्षवार ब्योरा साझा करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने अपनी कई विदेश यात्राओं का खुलासा नहीं किया और वे रहस्यमयी रही हैं। उन्होंने कहा, यह कानूनी सवाल पैदा करता है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के प्रावधानों के तहत, किसी भी सांसद, न्यायाधीश या सरकारी अधिकारी को किसी भी एजेंसी द्वारा प्रायोजित यात्रा के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेनी होती है। पात्रा ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत खर्च पर विदेश यात्रा करता है, तो उसे इसका विवरण आयकर रिटर्न में देना होता है। यदि विदेश में आपको कोई उपहार मिलता है या आप पर अज्ञात तरीके से पैसा खर्च किया जाता है, तो यह काला धन अधिनियम 2015 के प्रावधानों के दायरे में आता है। भाजपा नेता ने सवाल किया, क्या उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं के लिए गृह मंत्रालय से अनिवार्य पूर्व अनुमति प्राप्त की थी? दस्तावेज़ कहां हैं? क्या उन्होंने आयकर रिटर्न में इसका खुलासा किया है? पात्रा ने दावा किया कि पिछले साल सितंबर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर दिसंबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच राहुल गांधी की छह अघोषित विदेश यात्राओं पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने अपने आधिकारिक पत्र में कहा कि ये सभी छह विदेश यात्राएं एसपीजी सुरक्षा के येलो बुक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए की गईं।

भाजपा नेता ने कहा, हम पूछना चाहते हैं कि तीन मई 2026 की रात गांधी की मस्कट (ओमान) की निजी यात्रा का एक वीडियो फुटेज सामने आया है। उन्होंने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं की थी। न तो मेजबान का खुलासा किया गया और न ही कोई यात्रा कार्यक्रम बताया गया। उन्हें किसने आमंत्रित किया था?

देश के कई हिस्सों में तापमान 40 के पार, 16 राज्यों में हो सकती है बारिश

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक तापमान 40 के पार पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने 16 राज्यों के लिए राहत वाली खबर दी है। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। कई इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है।

इस बार मॉनसून से पहले ही प्री-मानसून गतिविधियां काफी मजबूत दिखाई दे रही हैं। दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार क्षेत्र में मॉनसून की शुरुआती हलचल ने दक्षिण भारत के मौसम को तेजी से बदला है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में लगातार बादल और बारिश ने गर्मी की रफ्तार को धीमा कर दिया है। दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं।

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर बिजली गिरने और तेज आंधी के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा है। कई राज्यों में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में अचानक तेज हवाओं के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मई के दूसरे पखवाड़े में मौसम और ज्यादा अस्थिर हो सकता है। ऐसे में लोगों को अगले कुछ दिनों तक मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखने की जरूरत होगी।

दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिन मौसम काफी बदला हुआ होगा। आईएमडी के मुताबिक राजधानी में आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन धूल भरी आंधी परेशानी बढ़ा सकती है। 15 मई को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि 16 मई के बाद मौसम कुछ हद तक साफ रहने की संभावना है।

बिहार में मौसम विभाग ने अगले पांच दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, बांका, जमुई, किशनगंज और जहानाबाद समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। दरभंगा और पूर्णिया में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है। हालांकि कैमूर जैसे इलाकों में तापमान अब भी 41 डिग्री के पार बना हुआ है। झारखंड में 14 से 18 मई तक मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। बाड़मेर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, हालांकि चुरू समेत कई इलाकों में बारिश और आंधी के कारण लोगों को कुछ राहत मिली है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले कुछ दिन लू चलने की संभावना है। पंजाब में मौसम बदलने से कई जिलों में गर्मी से राहत मिली है। पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मोहाली और पटियाला समेत कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम सुहावना बना हुआ है। 13 से 17 मई तक रुक-रुक कर हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है।

हिमाचल प्रदेश में 15 और 16 मई को मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है। शिमला, मनाली, धर्मशाला और कुल्लू में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। मौसम विभाग ने भूस्खलन और फिसलन को लेकर पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर एरिया के कारण कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं।

न्यूज गैलरी

जनगणना कार्य में लापरवाही पर 05 प्रगणकों को कारण बताओ नोटिस जारी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्री डीपी बर्मन ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 05 प्रगणकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाए। इन प्रगणकों को 03 दिनों के भीतर चार्ज अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। जिला जनगणना अधिकारी श्री बर्मन द्वारा नगरीय क्षेत्र बालाघाट में जनगणना प्रशिक्षण के उपस्थिति पत्रक का निरीक्षण करने पर पाया गया कि प्रगणक हरीश कुमार धुवारे, अनिल वर्मा, संदीप उइके, थानेश कुमार कटरे, मनोज पुछिया, दुर्गनंदन नेताम जनगणना प्रशिक्षण में उपस्थित नही थे। प्रगणकों की यह लापरवाही जनगणना अधिनियम के विपरित होने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।

सांसद श्रीमती भारती पारधी 15 मई को बालाघाट जिले के दौरे पर रहेंगी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। बालाघाट-सिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद भारती पारधी 15 मई को बालाघाट जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सांसद श्रीमती पारधी प्रातः 10 बजे आमजन एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगी। इसके पश्चात दोपहर 3 बजे वे हट्टा में आयोजित केकती हेल्थकेयर मल्टीस्पेशलिटी सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होकर केंद्र का शुभारंभ करेंगी। वहीं सांय 5 बजे सांसद श्रीमती पारधी लालबर्रा पहुंचकर 50 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेंगी। दौरे के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे।

मंदिर चोरी की 8 वारदातों का खुलासा, महाराष्ट्र के अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने 5 विशेष टीमें गठित कर 5 लाख का मशरूका किया बरामद, दो नाबालिग भी अभिरक्षा में

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

पुलिस द्वारा बीते दिनों जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा किया गया है। इस मामले को लेकर 14 मई को नगर पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी ने शहर के वार्ड क्रमांक 33 स्थित गायखुरी मंदिर परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी मीडिया के सामने रखी। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी हुए करीब 5 लाख रुपए मूल्य के मशरूका को बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों और जब्त सामग्री से संबंधित जानकारी भी साझा की गई। मंदिर परिसर में आयोजित इस प्रेस वार्ता को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते मंदिर परिसर लोगों से भर गया और लोग पुलिस की कार्रवाई एवं प्रेस वार्ता को उत्सुकता के साथ देखते नजर आए। इस दौरान क्षेत्र के कुछ समाजसेवी और वार्डवासी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मंदिर चोरी का खुलासा करने पर पुलिस टीम का स्वागत किया। लोगों ने पुलिस कर्मियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया और चोरी की घटनाओं के खुलासे को सराहनीय कार्रवाई बताया।

जिले में लगातार हो रही मंदिर चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए महाराष्ट्र के अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में सामने आई मंदिर चोरी की सभी 8 घटनाओं का सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 5 लाख रुपए का मशरूका भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के थाना रावनवाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो सुनसान और ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों की पहले रेकी करते थे और बाद में रात के समय ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। जिले के थाना लांजी, हट्टा, नवेगांव, कोतवाली और किरनापुर क्षेत्र में बीते दिनों मंदिरों में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आई थीं। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पांच विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों ने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर संदिग्धों पर नजर रखी और सूचना मिलने पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने विभिन्न मंदिरों में चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने राहुल बिसेन निवासी ग्राम अर्जुनी थाना रावनवाड़ी, विशाल राहंगडाले निवासी शिरपुर थाना रावनवाड़ी और लक्की सावनकर निवासी शिरपुर थाना रावनवाड़ी जिला गोंदिया महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा दो नाबालिग बालकों को भी अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 8 चांदी के मुकुट, 8 चांदी के छत्र, चांदी की आंखें, चांदी के कुण्डल, दान पेटियों की नगदी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लोहे की रॉड जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि जब्त मशरूके की कुल कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 16 अप्रैल से 11 मई के बीच थाना हट्टा, कोतवाली, नवेगांव और लांजी क्षेत्र के कई मंदिरों में चोरी की घटनाएं हुई थीं। इनमें गायखुरी स्थित सहस्त्रबाहु अर्जुन मंदिर, सिंगोड़ी का सार्वजनिक गणेश मंदिर, शीतला माता मंदिर, मोहझरी के भ्रामरी माता मंदिर और बोलेगांव के दुर्गा मंदिर समेत कई धार्मिक स्थल शामिल हैं। बालाघाट पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

अज्ञात सफेद कार की जोरदार टक्कर, महिला की मौके पर मौत, एक घायल

लामता चांगोटोला रोड पर हुई दुर्घटना

पद्मेश न्यूज। लामता। लामता थानांतर्गत के चांगोटोला मुख्य मार्ग पर गुरुवार दोपहर लगभग 2:30 बजे रानी तालाब के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात सफेद कार ने पैदल जंगल जा रही दो महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला मेघा शेख पति अकरम शेख 27 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला रीता पति भुरू टेकाम घायल हो गई। जिसका इलाज लामता के स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है दोनो महिला लामता निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 मई को दोपहर 2:30 बजे मेघा शेख एवं रीता टेकाम लकड़ी लेने के लिए पैदल जंगल की ओर जा रही थीं। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक अज्ञात सफेद कार ने दोनों को महिला को टक्कर मार दी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि रीता टेकाम दूर जा गिरीं, जबकि मेघा शेख कार के साथ कुछ दूरी तक घिसटती चली गईं। गंभीर चोट लगने से मेघा शेख की मौके पर ही मौत हो गई।हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। वहीं घायल रीता टेकाम को तत्काल उपचार के लिए लामता स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।जहां उनका इलाज जारी है।घटना की सूचना मिलते ही लामता पुलिस मौके पर पहुंची और मेघा शेख शव मौके से बरामद कर पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सोप दिया है। मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जुटी हुई है।

सार्वजनिक शीतला माता मंदिर में चोरी

ताला तोड़कर चांदी के तीन छत्र ले उड़े चोर, हट्टा पुलिस जांच में जुटी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के ग्राम हट्टा के वार्ड नंबर 4 स्थित सार्वजनिक शीतला माता मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर माता रानी को चढ़ाए गए चांदी के तीन छत्र चोरी कर लिए। चोरी गए छत्रों में एक बड़ा और दो छोटे छत्र शामिल हैं।जिनकी कुल कीमत लगभग 20 हजार रुपये बताई जा रही है। घटना 8 और 9 मई की दरमियानी रात की बताई गई है। मामले की शिकायत मिलने के बाद हट्टा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम हट्टा के वार्ड नंबर 4 में स्थित सार्वजनिक शीतला माता मंदिर क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां मोहल्ले के अलावा आसपास के ग्रामीण भी नियमित रूप से पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं। मंदिर में प्रत्येक शनिवार को भंडारा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। बताया गया कि 8 मई की शाम लगभग 7 बजे मंदिर में रोजाना की तरह पूजा-पाठ और आरती संपन्न हुई थी। इसके बाद मंदिर के श्रद्धालु भक्तगण एवं मोहल्ले के लोग मंदिर बंद कर अपने-अपने घर चले गए थे। अगले दिन 9 मई की सुबह करीब 6 बजे काशीराम नागेश्वर प्रतिदिन की तरह मंदिर में पूजा करने पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखने पर माता मंदिर में लगा चांदी का एक बड़ा छत्र और सजावट में रखे दो छोटे चांदी के छत्र गायब थे। काशीराम नागेश्वर ने तत्काल आसपास तलाश की, लेकिन छत्रों का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने मोहल्ले के अनिल कसार, अनिल निवारे, रोहित शुक्ला तथा ग्राम सरपंच उमेश सोनेकर को घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों ने भी आसपास खोजबीन की, लेकिन चोरों का कोई पता नहीं चल सका।बताया जा रहा है कि चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों ने दो दिनों तक अपने स्तर पर चोरी गए छत्रों की तलाश की। जब कोई सफलता नहीं मिली। तब काशीराम नागेश्वर ने 13 मई को हट्टा थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई।शिकायत के आधार पर हट्टा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(डी) एवं 331(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा मंदिर और आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है।

पैसा ठीक होने के बाद देना
शादी से पहले एवं शादी के बाद
उम्र की अधिकता से कमजोर सेक्स, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, लिंग का छोटापन, टेडापन, निःसंतान, शुक्राणुओं की कमी, शुगर से आयी कमजोरी आदि सभी सेक्स समस्याओं का शर्तिया ईलाज किया जाता है।
पता-जगजीवन आयुर्वेदिक दवाखाना
गुरूनानक पेट्रोल पंप के सामने समाजवाड़ी रोड, बालाघाट, मो. 9243880464

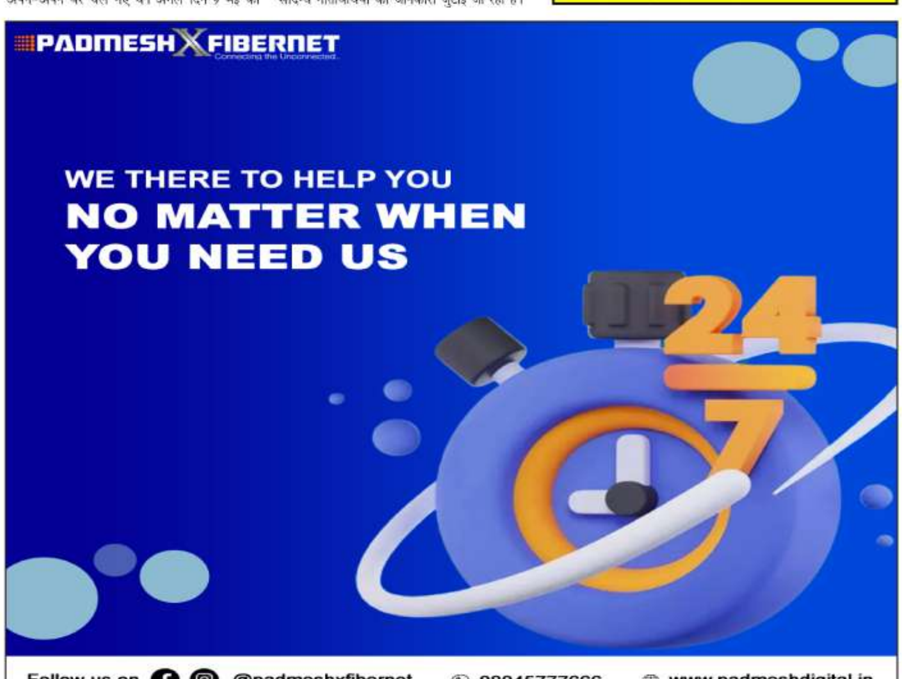

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :9425138710, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट